



नानाजी की दृष्टि में राष्ट्र निर्माण



# शिक्षांतर

Compendium: Two day National Seminar on National Education Policy  
26-27 February, 2022 Chitrakoot



राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी  
26-27 फरवरी 2022, चित्रकूट



दीनदयाल शोध संस्थान

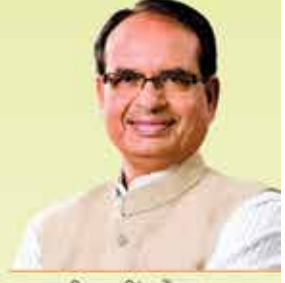


महात्मा गांधी चित्रकूट  
ग्रामोदय विश्वविद्यालय



नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

## भारत सरकार की योजनाओं पर अमल में मध्यप्रदेश अग्रणी



शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

मध्यप्रदेश भारत सरकार की योजनाओं को साकार करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। खासतौर से पिछले डेढ़ दशक का अरसा इस बात का गवाह है, कि मध्यप्रदेश विकास के पथ पर अब आगे ही आगे है। सुविचारित सोच, सुचिंतित नीतियों, फैसलों और प्रेरणादायी नेतृत्व ने सरकार की नीति और नीयत के फर्क को मिटाकर सच्चे अर्थों में प्रदेश के विकास और लोगों की बेहतरी के कामों की तस्वीर में नये रंग भर दिये हैं। आज मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व में न केवल अपनी बल्कि भारत सरकार की भी लोक कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की दिशा में अग्रणी बनकर उभरा है। मध्यप्रदेश की इन्हीं उपलब्धियों को देखकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश को भारत की अर्थ-व्यवस्था की ड्रायविंग फोर्स बनने की पूरी क्षमता वाला प्रदेश बताया है।

### दिव्यांगजन पहचान-पत्र

कुल **6 लाख 60 हजार** के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक मध्यप्रदेश **6 लाख 63 हजार** कार्ड बना और जारी कर देश में दूसरे स्थान पर।



### प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

योजना क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर। अब तक **25 लाख 36 हजार 917** हितग्राहियों को लगभग 1 हजार 84 रुपए से अधिक की सहायता।

### आयुष्मान भारत योजना

योजना के कार्ड जनरेशन में मध्यप्रदेश पूरे देश में प्रथम। अब तक बने **2 करोड़ 66 लाख 14 हजार** से अधिक कार्ड।

### प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना

भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार **4 लाख 5 हजार** पथ-विक्रेताओं को शत-प्रतिशत ब्याजमुक्त ऋण देकर मध्यप्रदेश देश में अव्वल

## मनरेगा से रोजगार में मध्यप्रदेश देश में प्रथम

पिछले वित्त वर्ष में कोरोना काल में 1 करोड़ 6 लाख से अधिक जरूरतमंद लोगों को मनरेगा में रोजगार दिलाकर मध्यप्रदेश, देश में अग्रणी रहा है। इस अवधि में मजदूरों के खातों में रिकॉर्ड 6 हजार करोड़ रुपए पहुँचाये गये। इस वित्त वर्ष में अभी तक 79 लाख 62 हजार श्रमिकों को रोजगार दिया जाकर 3 हजार 924 करोड़ रुपए से अधिक की राशि श्रमिकों के खातों में पहुँचाई गई है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति परिवारों को मनरेगा से रोजगार दिलाने में भी मध्यप्रदेश, देश में पहले स्थान पर है। जनजातीय श्रमिकों द्वारा 6 करोड़ 89 लाख मानव दिवस सृजित किए जाकर उनके खातों में 1 हजार 203 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। मनरेगा योजना में प्रारम्भ से अब तक 5.4 लाख 30 हजार स्थाई परिसंपत्तियों का सृजन कर मध्यप्रदेश, देश में चौथे स्थान पर है।





75  
आपूर्ति  
अमृत महोत्सव

# हर घर जल जल जीवन मिशन

मध्यप्रदेश की शानदार उपलब्धि

18 माह में कोरोना के समय में भी



18 लाख से बढ़ाकर  
**46 लाख परिवारों** को घर  
में नल से जल उपलब्ध कराया

100%

**4 हजार 45 गाँवों** के  
100 प्रतिशत घरों  
में नल से जल पहुँचा



श्री आनंद मिश्रा  
मन्त्री, मध्य प्रदेश



श्री नरेंद्र मोदी  
प्रधानमंत्री

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश

If you are on the lookout for a seat of learning excellence in Agri & allied Technical Education



**The Central Agricultural University**  
**Lamphelpat, Imphal - 795 004**



Website: [www.cau.ac.in](http://www.cau.ac.in)  
is the ideal destination.

Established by an Act of Parliament, 1992 ( Act No.40 of 1992) ACCREDITED BY ICAR, NEW DELHI FOR AGRICULTURAL SCIENCES"



## **A temple of learning for higher education in Agriculture and Allied Sciences**

- First Central University for Agriculture and Allied Technical Education in India.
- 13 Colleges spread in seven states of North Eastern Hill region.
- 6 Krishi Vigyan Kendras, 6 Multi-technology & Vocational Training Centres.
- Mission for Centre of Excellence in Teaching, Research and Extension Education in the field of Agriculture and Allied Sciences.
- World class facilities, viz. Smart Class Room, Language Laboratory and Incubation Centres.
- Internalization of education through MoUs, exposure of 100 students and 40 faculties in global universities.
- Toppers in All India JRF exams in Horticulture, Fisheries & Community Science.
- Cracks in All India Competitive Exam, viz. CSE, IFS, ARS, Bank Pos and state Civil Service Exams.

| S. No. | Name of the Faculty                        | Courses offered  |
|--------|--|--|
| 1      | Agriculture                                | B.Sc (Agri), M.Sc (Agri), Ph.D                                     |
| 2      | Veterinary Science & Animal Husbandry      | B.V.Sc. & A.H. M.V.Sc, Ph.D  |
| 3      | Fisheries                                  | B.F.Sc., M.F.Sc , Ph.D   |
| 4      | Hort.& Forestry                            | B.Sc (Hort.), B.Sc (Forestry),M.Sc. (Hort.), M.Sc (Forestry), Ph.D |
| 5      | Home Science                               | B.Sc (Home Sc.), M.Sc (Nutrition & Dietetics)                      |
| 6      | Agricultural Engineering & Food Technology | B.Tech (Agril. Engg),<br>B.Tech.(Food Technology); M.Tech.         |



# नानाजी की दृष्टि में राष्ट्र निर्माण शिक्षांतर

Compendium: Two day National Seminar on National Educational Policy  
26-27 February, 2022 Chitrakoot

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी  
26-27 फरवरी 2022, चित्रकूट



दीनदयाल शोध संस्थान



महात्मा गांधी चित्रकूट  
ग्रामोदय विश्वविद्यालय

दीनदयाल शोध संस्थान, चित्रकूट एवं  
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्विद्यालय चित्रकूट सतना (म.प्र.)  
के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी



नानाजी की दृष्टि में राष्ट्र निर्माण: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिदृश्य में  
Nanaji's Vision of Nation Building, in the Context of The National Education Policy 2020

26-27 फरवरी 2022

## पंचसूत्रीय चित्रकूट संकल्प

THE FIVE POINT CHITRAKOOT RESOLVE

हम चित्रकूट की पावन धरा पर संकल्प करते हैं कि—

We, the participants of this National Seminar, held in the Holy land of Chitrakoot, promise that:

1. विद्यार्थी अपने ज्ञान, कौशल और प्रतिभा का उपयोग राष्ट्र के सतत् विकास विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत लोगों और अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों के कल्याण के लिए करें, इस हेतु हम उन्हें प्रोत्साहित करेंगे।  
We will encourage the students to utilise their knowledge, skills, and talents for National Sustainable Development, especially the welfare of those who are needy and deprived.
2. शैक्षणिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा गरिमा और उपयोगिता को अक्षुण्य बनाये रखने के लिए हम अपने पाठ्यचर्या, शिक्षण प्रशिक्षण पद्धति एवं अनुसंधान आयामों को स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुरूप पुर्नगठित करेंगे तथा इसके लिए समन्वित प्रयास करेंगे।  
We will jointly attempt to reorganize the syllabus, teaching, training methods and research dimensions as per local needs and resources.
3. हम ऐसी सहभागी मूल्यांकन पद्धति विकसित करेंगे जो छात्र, शिक्षक एवं समाज को जोड़कर स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर समाधान प्रस्तुत करे।  
We will develop a participatory evaluation system that envisages the co-operation of students, teachers and the society.
4. हम सब मिलकर ऐसी रचनात्मक, पारदर्शी और मूल्य आधारित कार्य प्रणाली विकसित करेंगे जिससे सामाजिक उत्तरदायित्वों से ओतप्रोत पीढ़ी तैयार हो सके।  
We will develop a constructive, transparent and value based modus operandi that can inculcate social responsibility in future generations.
5. हम सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को समग्रता और परिपूर्णता के साथ प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्वयं को समर्पित करते हैं।  
We all dedicate ourselves for the effective and complete implementation of the National Education Policy 2020.

# अनुक्रमणिका

(26-27 फरवरी, 2022)

1. **शिक्षा का हेतु सार्थक जीवन का निर्माण-राष्ट्रऋषि श्री नानाजी देशमुख** 9  
(महर्षि दयानन्द सरस्वती महाविद्यालय, अजमेर में आयोजित द्वितीय दीक्षांत समारोह में माननीय नानाजी देशमुख को डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नानाजी द्वारा दिए गए भाषण का संपादित पाठ। मंथन, जुलाई-सितंबर 1998)
2. **शिक्षा का उद्देश्य है मानवीयता का सृजन करना-राष्ट्रऋषि श्री नानाजी देशमुख** 15  
(शैक्षणिक सुधार राष्ट्रीय संगोष्ठी में राष्ट्रऋषि नानाजी देशमुख का उद्बोधन - 14-15 मार्च 2001)
3. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी – रिपोर्ट** 21  
प्रमुख वक्ताओं के उद्बोधन— 31  
श्री प्रदीप जोशी, चेयरमैन – यूपीएससी  
डॉ त्रिलोचन महापात्रा, महानिदेशक – आईसीएआर  
श्री भरत भूषण जी (सामाजिक कार्यकर्ता)
4. **ABSTRACT – EVALUATION** 45  
(Towards a New Era of Vocational Education and Skill-building in India: The NEP-2020 Perspective) 49
5. **Paper Presentation**  
डॉ. आर. एम. चौहान, कुलपति  
Dr. Narendra Singh Rathore, Vice Chancellor  
राष्ट्रऋषि नानाजी देशमुख की परिकल्पना एवं नई शिक्षा नीति में समानता तथा समयानुकूलता:  
ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ में  
NANAJI 'AN INSPIRING SOCIAL ENTREPRENEUR' - Dr.Rajjan Dwivedi  
शिक्षण में उचित वातावरण का निर्माण एवं शिक्षार्थी का सहयोग आवश्यक
6. **समापन सत्र** 82  
पंच सूत्रीय संकल्प  
तुलनात्मक विवेचना  
शिक्षा के संबंध में नानाजी का दृष्टिकोण एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020  
सुप्रसिद्ध भजन गायिका सुश्री मुस्कान चौरसिया के भजनों से माहौल हुआ भक्तिमय  
Draft National Education Policy 2019  
New National Education Policy 2022 नई शिक्षा नीति  
What is NEP 5+3+3+4 Structure

# SKUAST-JAMMU IN THE SERVICE OF FARMING COMMUNITY

(Conferred with Krishi Udyami Krishak Rattan Puraskar 2021 for excellence in academics during Progressive Agri Leadership Summit 2021)

Established in the year 1999, SKUAST-Jammu has been emerging as one of the finest agricultural university of the country, with impact oriented teaching, research and extension programmes.

## Teaching

### 07 Faculties

- § Faculty of Agriculture
- § Faculty of Veterinary Sciences & Animal Husbandry
- § Faculty of Basic Sciences
- § School of Biotechnology

### Recently Approved Faculties

- § Faculty of Horticulture & Forestry
- § Faculty of Dairy Technology
- § Faculty of Agricultural Engineering

### Job and Skill Oriented New Courses

- § Ph.D. Floriculture and Landscape Architecture
- § M.Sc. (Seed Science & Technology)
- § B.Sc. (Hons.) Horticulture.

### 36 Startups under RKVY-RAFTAAR; 75 startups to be promoted by 15<sup>th</sup> August, 2022

- Two startups awarded: Dr. Khalid Masoodi won 1 lakh and Mansi Sharma won Rs. 25000 at IIT Jammu startup competition
- Selection of Students in higher education foreign institutions
- Placements in administrative services and reputed national & international organizations

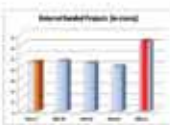


National Agricultural Higher Education Project-Institutional Development Plan (NAHEP-IDP) for supporting infrastructure, faculty and student advancement.



## Research

- Research on speciality agriculture in Jammu region; saffron, Kalazeera, Lavendar, olive etc.
- Research on One District-One Product (ODOP) theme
- National & International external funded projects worth Rs. 60 crores
- Integrated Farming System of 1.0 ha for irrigated belt yielding Rs. 3.04 lakhs per year
- University has released 50 crop varieties, out of which 21 released in last one year
- Newly released early maturing rice variety 'Jammu Basmati 118' is already become popular in North-Western region under Rice-Wheat cropping system
- Released varieties also include first ever variety of pecanutt (SJPP-25) by SKUAST, Jammu



## Extension

- 09 Krishi Vigyan Kendras including 2 new KVKs at Ramban & Kishtwar
- KVK Jammu won Pandit Deendayal Upadhyay Krishi Vigyan Protsahan Puraskar 2016-17
- KVK Jammu also conferred with Krishi Alert Award 2021 for excellence in Food Processing initiatives
- Five KVKs received 'A' ranking by NITI Aayog
- Promotion of Community based processing through KVKs
- Innovative Extension Methodologies (VC to Village Programme, Participatory seed Production Programme)
- Community Radio
- Radio Programmes "Farm to Table-A Week Long Market" on FM Tadka
- SKUAST-Jammu Kisan Call Centre (1800-180-7196)
- e-studio
- Kisan Hiteshi & Dudaaru Mobile APP
- CBBO for Farmer Producer Organizations in Jammu region
- Organization of Five days Kisan Melas including North Zone Regional Agriculture Fair
- Innovative farmers' Conference
- University farmers awarded at national level

## Future endeavours

- Nanotechnology and stem cell research in agriculture & veterinary sciences
- Establishment of Ex-situ Gene bank for preservation of plant genetic resources
- Establishment of Centre for Innovation & Entrepreneurship Development (CIED) for promoting vocational education under National Education Policy
- Creation of modern Seed production infrastructure for enhancing Seed Replacement Rate in J&K
- Expansion of area under Medicinal and Aromatic plants
- Promotion of Organic and natural farming
- MoUs with International Institutes to strengthen Agricultural Research and Extension



Sher-e-Kashmir  
University of Agricultural Sciences and  
Technology of Jammu

# शिक्षा का हेतु सार्थक जीवन का निर्माण

– राष्ट्रऋषि श्री नानाजी देशमुख

सर्वप्रथम मैं उन युवक युवतियों का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ, जिन्होंने स्वयं को उपाधियों से विभूषित कर लिया है। आज एक विशेष बात है, इस विश्वविद्यालय में 82 साल के बूढ़े को उपाधि प्राप्त करने वाले जवानों के समकक्ष खड़ा किया गया है। फलस्वरूप मैं बीती हुई जवानी की अनुभूति कर रहा हूँ। वस्तुतः आज जवानों की ओर देखना और देश के भविष्य की कल्पना करना आवश्यक है। संसार में युग प्रवर्तन का काम कभी भी किसी वृद्ध ने नहीं किया, चाहे वह कितना भी क्षमतावान रहा हो। युग प्रवर्तक अपवादरहित सभी युवक रहे हैं। यह मानव समाज का इतिहास है। इसलिए उपाधि-प्राप्त युवाओं से देश का भविष्य विशेष अपेक्षा कर रहा है।

## महर्षि का योगदान

आज मुझे महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय में उपस्थित होने का सुअवसर प्रदान किया गया है। इसलिए मैं इस विश्वविद्यालय के संचालकों का बहुत-बहुत आभारी हूँ। यह विश्वविद्यालय महर्षि दयानन्दजी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए प्रस्थापित हुआ है। उपाधि प्राप्त युवक-युवतियों से मैं एक ही अनुरोध करूंगा कि महर्षि दयानन्द ने भारत में कौन सी परंपरा प्रचलित करने का प्रयास किया, यह वे समझें। स्वामी दयानन्द छोटी-से-छोटी बात से मूलभूत तत्व की अनुभूति किया करते थे। हम सभी जानते हैं कि जब शिव की पिंडी पर के चावल खाने के लिए पिंडी पर चढ़कर चूहे अपना उदर भरण कर रहे थे तो स्वामी जी को यह सामान्य दृश्य देखकर अनुभव हुआ कि भारत का अद्वितीय जीवन-दर्शन कर्मकांडों में फंसकर गतिहीन हो रहा है। इससे पीड़ित होकर उन्होंने कर्मकांडों से अपने जीवन-दर्शन को मुक्त किया था। यहां से उपाधि प्राप्त युवजन इस तथ्य को समझकर उसे आगे बढ़ाएं, यह स्वामी दयानन्द जी की शरीर छोड़ते समय हम सबसे अपेक्षा रही है।

देश में बहुत विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। विश्वविद्यालय के तहत महाविद्यालयों की संख्या बढ़ रही है। अभी हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने इस संख्या में बढ़ोतरी के बारे में बताया। महिलाओं के भी महाविद्यालयों की संख्या पेश की है। मैं जानना चाहता हूँ इन महाविद्यालयों में बड़ी-बड़ी डिग्रियां प्राप्त युवक और युवतियों को क्या यह पता है कि माता-पिता का दायित्व क्या हुआ करता है? उनके और उनकी संतान के द्वारा इस राष्ट्र का नवनिर्माण किस प्रकार किया जाएगा? विचार करें। असंख्य विद्यालय, विश्वविद्यालय भारत में ही नहीं संसार भर में कार्यरत हैं। अभी-अभी जो पुस्तिकाएं दी गई हैं, उनमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय

की चर्चा है। इस साहित्य को पढ़कर आज के हिंदी समाचार-पत्र संभवतः 'नवज्योति' में एक लेख छपा है, जो मुझे पढ़ने को मिला। किन्तु इतने विश्वविद्यालय खोलकर क्या यह विचार हो रहा है कि मानव के लिए ही शिक्षा की आवश्यकता क्यों है?

### मानव हेतु विद्यालय क्यों

उदर-भरण एवं उपभोग प्रत्येक प्राणी की आवश्यकता है। मानव उसका अपवाद नहीं है। शरीर के बिना आत्मा अपना वैशिष्ट्य प्रकट कर नहीं सकती। शरीर बिना उपभोग के टिक नहीं सकता। अतः आत्मा की विशेषता प्रकट करने के लिए शरीर नितांत आवश्यक साधन है।

मैं देखता हूँ, शिक्षा के बारे में अनेक विद्वान अपने लेख प्रकाशित कराते हैं। शिक्षा के बारे में संसार में अनुसंधान कार्य चल रहा है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मैंने कुछ काल तक रहकर समझने की कोशिश की। केंब्रिज विश्वविद्यालय में भी मैं गया। लेकिन किसी भी विश्वविद्यालय में नई पीढ़ी को यह बताने का प्रयास दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हम शिक्षा ग्रहण क्यों कर रहे हैं? बड़ी-बड़ी बातें होती हैं कि हमने इस नाम से विश्वविद्यालय शुरू किया। प्रत्येक माता-पिता अपनी संतान को बहुत अच्छे नाम से संबोधित करना चाहते हैं। किसी का नाम जीवनप्रकाश है। लेकिन क्या उनके जीवन में प्रकाश प्रकट होता है? संकायों के नाम बड़े-बड़े लोगों के नाम पर रखने भर से वे संकाय बेहतर कार्य नहीं कर पाते। क्षमा करें, मेरा यह कहना जरा अखरेगा-लेकिन किसको क्या अखरता है तथा किसको क्या नहीं अखरता, यह विचार कर अपना मानस प्रगट करना मेरा स्वभाव नहीं है। यह मेरा दोष हो सकता है।

### अनुत्तरित प्रश्न

मानव के अलावा जितने प्राणी हैं, उनमें भयंकर से भयंकर हिंसक प्राणी भी हैं, लेकिन ये प्राणी संसार में असंतुलन पैदा करने की क्षमता नहीं रखते। ये सब प्रकृति के नियमों से बंधे हैं। वे प्राकृतिक बंधनों को कभी लांघ नहीं पाते। विचार करें, उनका उपभोग संसार में न असंतुलन पैदा करता है और न पर्यावरण ही बिगाड़ता है। उनकी उपभोग प्रवृत्ति कभी भी बलात्कार करने का कारण नहीं बनती।

प्राकृतिक जीवनादर्श की अवहेलना से जीवन वासनाप्रधान बनता है। यह क्यों होता है? मानव अन्य प्राणियों से भिन्न है। मानव के लिए कोई प्राकृतिक नियमों की पाबंदी नहीं है। वह अपना जीवन स्वेच्छा से चलाने के लिए स्वतंत्र है। मानव में बड़ी क्षमताएं हैं। उदर भरण एवं उपभोग के अतिरिक्त मानव नव-निर्माण की क्षमता रखता है। उसका मन कल्पना का केन्द्र है। उसका मन सपने देखने की अद्वितीय क्षमता रखता है। सपनों को कार्यान्वित करने

की उसमें बुद्धिमता एवं शारीरिक क्षमता है। फिर मानव असंतुलन क्यों पैदा करता है?

### अनावश्यक संग्रह

संसार में कोई भी प्राणी अपने उपभोग के लिए संग्रह नहीं करता। किंतु मानव करता है। समाज शास्त्र सिखाया जा रहा है। विज्ञान सिखाया जा रहा है। नई से नई विधियों का निर्माण किया जा रहा है। किंतु क्या बड़े, देशभक्त कहलाने वाले नेतागण एवं गुरुजन इस ओर ध्यान दे रहे हैं? कहां से दिशा प्राप्त होगी? भाषणबाजी से संभव नहीं है। अमरीका, जर्मनी आदि से होड़ लगाने से नहीं चलेगा। न एटम बम के द्वारा संभव होगा।

### भौतिकता की सीमाएं

मानव कितना भयंकर कदम उठा सकता है। दूसरे विश्वयुद्ध में अमरीका ने हिरोशिमा व नागासाकी पर बम डालकर पूरी की पूरी आबादियां नष्ट नहीं की थी? क्या मानव के अतिरिक्त अन्य कोई प्राणी ऐसा भयानक अत्याचारी सिद्ध हो सकता है? मानव मानव के नाते इस विश्व में क्या सीख रहा है? मानवीयता की शिक्षा किसी विद्यालय या विश्वविद्यालय में दी जा रही है? मैंने जानने का प्रयास किया कि क्या है मानव? क्या मानव केवल भौतिक प्राणी है? जैसे अन्य प्राणी हैं, जिनके जीवन का लक्ष्य खाना, पीना, भोग भोगना और एक दिन दुनिया से विदा लेना ही है। अन्य प्राणियों का तो इतना ही जीवन है।

### मानव का गुण

मानव ही एक ऐसा प्राणी है, जिसमें संवेदनशीलता है। मानव संवेदनशील है। उसके शरीर में आत्मा विराजमान है। आत्मा का प्रकटीकरण संवेदनशीलता के माध्यम से होता है। वह दूसरे को पीड़ित देखकर द्रवित होता है। किसी को पीड़ामुक्त कर प्रसन्न हो जाता है। क्या इस प्रकार की क्षमता को बढ़ाकर, मानव को मानवीयता से विभूषित करने का प्रयास विश्वविद्यालयों में हो रहा है?

जो लोग सरकार चला रहे हैं, उनके दिल में अभावग्रस्तों के लिए कोई पीड़ा नहीं है। मैं रिपोर्ट पढ़ता हूँ, हिन्दुस्तान के 96 करोड़ में से 36 से 40 करोड़ के बीच ऐसे लोग हैं, जिनके घरों में दोनों समय भोजन उपलब्ध नहीं होता। उनकी पीड़ा किसको है? उन्होंने ऐसे ही विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई है, जहां संवेदनशीलता अर्थात् मानवीयता के विकास की कोई गुंजाइश नहीं, वहां उपभोग प्रवृत्ति बढ़ाने का क्रम चलता है। पिछले 50 साल में हिन्दुस्तान में मानवता से विभूषित नई पीढ़ी के कितने लोग शिक्षा संस्थाओं ने पैदा किये हैं। इसका विचार करने की आवश्यकता है। किन्तु इस ओर ध्यान देने की देश के नेतृत्व को फुरसत नहीं है। दिखावा मात्र शिक्षा का भूषण बना है। शिक्षा में परिवर्तन लाना पड़ेगा। मगर ये परिवर्तन होगा कैसे? इस आवश्यकता की पूर्ति केवल गुरुजन ही कर सकते हैं।

## विश्वविद्यालय का दायित्व

दुर्भाग्य से, आज मैं यह देखकर दुखी होता हूँ कि माता-पिता अपनी संतान को विकसित करने का दायित्व संभालना नहीं चाहते। वे अपने बच्चों के विकास की दुकान खोजते हैं। महंगे से महंगे विद्यालय खुल रहे हैं। ऐसे-ऐसे विद्यालय हैं, जिनमें तीन से पांच हजार रुपये महीना एक-एक बच्चे से लिया जाता है। सरकार इन्हें मान्यता और धन भी दे रही है। मुझे पता है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। ऐसे विद्यालय समाज में विषमता बढ़ाने के कारण बन रहे हैं और बात भारतीय संस्कृति की होती है।

## बस वेतन की चिंता

देश में यूनियन की अंधी दौड़ चल रही है। शिक्षकों ने भी ट्रेड यूनियनिज्म को अपना लिया है। यह वर्ग संगठित है और अपनी मांगे मनवाने के लिए ऐन परीक्षा के समय पर हड़ताल करने में उन्हें संकोच नहीं होता। क्या इस वातावरण में देश के उज्ज्वल भविष्य की आशा की जा सकती है? इस पर कौन सोचेगा?

मेरी बातें संभवतः आप उपाधि प्राप्त युवक-युवतियां पसंद न करें, किंतु यदि आप नई पीढ़ी के पढ़े-लिखे नौजवान भी इस पर ध्यान नहीं देंगे तो देश के नेतृत्व को ठीक दिशा में सोचने के लिए अन्य कौन आगे आएगा? इस दिशा में कम-से-कम महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय विचार कर आवश्यक कदम बढ़ाए, यह मैं इस विश्वविद्यालय के संचालकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ।

## नई दिशा दें

अभी-अभी एक रिपोर्ट छपी है, उसमें बताया गया है कि संपूर्ण विश्व में जितने बच्चे कुपोषण से मरते हैं, उनमें केवल भारत के ही 40 प्रतिशत से अधिक हैं। यदि इस सामाजिक दुर्दशा पर देश के गुरुजन एवं उपाधि प्राप्त युवाजन सोच-विचार कर कदम नहीं बढ़ाएंगे तो देश का भविष्य कैसे बन पाएगा?

गुरुजन समाज की सुरिथिति के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। वे अपने लिए एक छोटा सा क्षेत्र चुन लें तथा अपना परिवार चलाने के लिए नितांत आवश्यक धन अपने परिवार के काम में लाएं और शेष धन से अपने क्षेत्र के अभावग्रस्त बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सुनियोजित कार्यक्रम अपनाएं। यदि ऐसा किया गया तो देश के विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत होगा। इसके नेतृत्व का श्रेय महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय को मिलेगा।

## वसुधैव कुटुम्बकम्

भारतीय परम्परा की विशेषता रही है कि कौटुंबिक जीवन केवल व्यक्तिगत कुटुंब के

सदस्यों तक सीमित नहीं रहा है। वह वसुधैव कुटुम्बकम् की अवधारणा साकार करने का स्रोत रहा है। काल के प्रवाह में यह अवधारणा तिरोहित हो गई है। आवश्यकता है कि देश के शिक्षा-केन्द्र इस अवधारणा को पुर्नजीवित करें।

भारत में प्रारम्भ काल से ही विद्याध्ययन की सर्वाधिक महत्व दिया गया था। केवल लिखना, पढ़ना और हिसाब करने तक भारत की शिक्षा सीमित नहीं थी। पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, शासकीय जीवन और उसमें व्यक्ति-व्यक्ति का योगदान किस प्रकार का हो, यह केवल पढ़ाया ही नहीं जाता था अपितु गुरुजन अपने तथा अपने पारिवारिक जीवन से छात्र-छात्राओं को व्यावहारिक शिक्षण प्रदान करते थे। इसी कारण चीन के ह्वेनत्सांग ने भारत यात्रा के काल में आश्चर्यचकित होकर कहा था, 'यहां के तो किसी घर में ताला लगता ही नहीं।' मेरा विश्वास है कि अजमेर का यह महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय संपूर्ण संसार के लिए इस कार्य का अनुकरणीय नमूना प्रस्तुत करेगा।

भारत ने अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख के स्थान पर 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' का आदर्श इसी प्रक्रिया से प्रस्तुत कर दिखाया था। हजार साल गुलामी में बिताने के बाद हम स्वतंत्र हुए हैं। हमारा अपना इतिहास है। हमारी अपनी सभ्यता है। हमारी अपनी संस्कृति है। तदनुसार हमें स्वतंत्र भारत के नागरिकों का जीवन विकसित करना होगा। यह काम विद्यालय और विश्वविद्यालय ही कर सकते हैं। हमारी संस्कृति यथास्थितिवादी नहीं रहीं। गतिशीलता उसकी विशेषता है। फलस्वरूप विकसित होने वाली तकनीक हमने कभी अस्वीकार नहीं की। उसे अपनी मानवीयता की दिशा में संस्कारित कर अपनाया है।

### आत्मनिर्भरतापूर्ण विकास

हम आजाद हुए। उसके बाद चीन माओ के अधिकार में आया। माओ के पहले चीन पूरी तरह से अमरीकी चंगुल में फंसा हुआ था। उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय थी। परनिर्भरता उसका जीवन बना था। किन्तु आज चीन विश्व की महान शक्तियों में से एक है। कोई वैचारिक साम्य न होते हुए भी आज संसार की सबसे बड़ी शक्ति अमरीका उससे मित्रता करना चाहता है। उसने आणविक शक्ति का विकास किया है किन्तु अमरीका उसका बुरा मान नहीं रहा है। किन्तु हमने कुछ ही विस्फोट किये, अणु शक्ति के शस्त्रों का कोई जखीरा हमने खड़ा नहीं किया। इसके बावजूद अमरीका और अन्य बड़ी शक्तियां हम पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने पर उतर आई हैं। क्या इस वस्तुस्थिति से हमें कुछ पाठ पढ़ने नहीं चाहिए?

देश में एक के बाद एक नई-नई सरकारें बन रहीं हैं। उनमें से किसी ने भारत की वस्तुस्थिति को समझ हर कदम नहीं बढ़ाया। भारत की आबादी आज भी 70 प्रतिशत से ज्यादा गांव में रह रही है। सब प्रकार के प्राकृतिक संसाधन गांव में ही उपलब्ध हैं। वस्तुतः

शहर नहीं, गांव ही उत्पादक है। किन्तु गत 50 साल में गांव की जितनी उपेक्षा हुई है, उसकी सीमा नहीं है। उपभोग करने वाली शहरी आबादी का आकर्षण बढ़ाया जा रहा है। किन्तु जहां उत्पादकता संभव है, उसकी उपेक्षा की गई तो उपभोग कैसे पूरा हो पाएगा - यह देश के नेतागण समझ नहीं रहे हैं। आजादी पाने के बाद विदेशों की नकल करने में ही सार्थकता मानने की जो परंपरा चल पड़ी थी, उसी को नेतृत्व आगे बढ़ा रहा है।

हमें विचार करना होगा। हमारे यहां एक बहुत पुरानी कहावत है, जो व्यक्ति के जीवन का मार्गदर्शन किया करती थी-

## त्यजेदेकं कुलस्यार्थं ग्रामस्यार्थं कुलं त्यजेत। ग्रामं जनपदस्यार्थं आत्मार्थं पृथ्वी त्यजेत॥

अर्थात् संवेदनशील बने रहने के लिए आवश्यकता पड़ने पर शरीर का भी त्याग करो। क्या हमारे नेतागण इस तथ्य की ओर ध्यान दे रहे हैं? क्या ऐसी अवस्था में नई पीढ़ी भारत के आदर्शों के अनुसार देश का निर्माण कर पाएगी।

उपर्युक्त बातों का विचार करना होगा और तदनुसार जीवन की दिशा निश्चित करनी पड़ेगी।

### महाशक्तियों को भय

संसार की महाशक्तियां भारत को आगे बढ़ने देना नहीं चाहतीं। वे जानती हैं कि संसार में भारत ही एक ऐसा देश है, जिसके पास सब प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का अथाह भंडार है। वैज्ञानिक क्षमता के धुरंधर इस में विद्यमान हैं। यदि भारत कहीं आत्मनिर्भर बन गया तो इन महाशक्तियों की महानता टिक नहीं पाएगी। संसार का शोषण करने का उनका एकाधिकार समाप्त होगा। इसलिए संसार की महाशक्तियां भारत के खिलाफ हैं। उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। चीन महाशक्ति बना तो किसी की कृपा से नहीं बना। कम्युनिस्ट विचारधारा का स्रोत रूस से चल पड़ा। उसी को लेकर चीन ने अपने को लाल निशानवाला देश बनाया। किन्तु उसने रूस का पिछलग्गूपन स्वीकार नहीं किया। तब जाकर चीन संसार की महान् शक्ति बन पाया है। इस बात को हमारे देश के नेतागणों को समझना होगा। क्या ये सब नेतागण भारत के उत्थान के लिए आपस में झगड़ने के स्थान पर इकट्ठा आकर देश के लिए समर्पित भाव से काम नहीं कर सकते?

(नोट:-महर्षि दयानन्द सरस्वती महाविद्यालय, अजमेर में आयोजित द्वितीय दीक्षांत समारोह में माननीय नानाजी देशमुख को डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नानाजी द्वारा दिए गए भाषण का संपादित पाठ। मंथन, जुलाई सितंबर 1998)

# शिक्षा का उद्देश्य है मानवीयता का सृजन करना

– राष्ट्रऋषि श्री नानाजी देशमुख

## शिक्षा की आवश्यकता क्यों?

इस अवनी तल पर असंख्य प्राणी हैं। किंतु शिक्षा की आवश्यकता मानव को ही क्यों है? अन्य किसी प्राणी का विद्यालय मैंने तो नहीं देखा। इस पर विचार करना पड़ेगा। मानव तो सभी प्राणियों में अधिक बुद्धिमान है, अधिक संवेदनशील है। वह सभी प्राणियों में अधिक कल्पना-शक्ति रखने वाला प्राणी है। मानव के पास बुद्धि है। फिर किसी प्राणी के लिए जब शिक्षा की आवश्यकता नहीं तो मानव के लिए क्यों? यदि यह चीज हमने समझ ली तो शिक्षा की दिशा निश्चित करने में सहायता मिलेगी। मानव को छोड़ कर संसार का कोई भी प्राणी पर्यावरण बिगाड़ता नहीं, प्रदूषण फैलाता नहीं, जीवन के लिए किसी प्रकार का खतरा पैदा करता नहीं। लेकिन मानव के द्वारा यह खतरे पैदा किए जा रहे हैं। कुछ वर्ष पहले ब्राजील में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें संपूर्ण विश्व के 156 देश उपस्थित हुए। विषय था पर्यावरण और ओजोन के क्षति-ग्रस्त होने की चिंता, उस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में प्रमुख चर्चा का विषय बना कि अमेरिका सबसे ज्यादा प्रदूषण का कारण बना है। ग्रीन हाउस से जैसे निकलती हैं उससे ओजोन क्षतिग्रस्त हो रहा है। सबने मिलकर प्रस्ताव रखा और अमेरिका से कहा कि ग्रीनहाउसेस के कारण जो जैसे निकल रही हैं, जो प्रदूषण हो रहा है, उसमें 20 प्रतिशत कटौती करें। अमेरिका तो अशिक्षित नहीं है, हम सब जानते हैं। उसने कहा, यदि हमने यह किया तो हमारा जीवन-स्तर घट जाएगा। हम अपना जीवन जैसा चला रहे हैं, उसमें कमी करने से हमारा काम नहीं चलेगा। बड़ी मुश्किल से अमेरिका ने 5 प्रतिशत प्रदूषण घटाने के लिए स्वीकृति प्रदान की। ओजोन की क्षति से मानव मात्र के लिए खतरा हो रहा है, मानव मात्र का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है - लेकिन शिक्षा-प्राप्त अमेरिका को उसकी चिंता नहीं।

## लालसा - सभी संकटों की जड़

क्या किसी प्राणी के कारण ऐसा खतरा पैदा हो रहा है। विश्व के प्रारंभ से आज तक मानव को छोड़कर खतरा कोई पैदा नहीं करता। मानव की लालसा (जिसको अंग्रेजी में ग्रीड कहते हैं) के बारे में गांधी जी ने कहा था कि मानव मात्र की आवश्यकताएं पूर्ण होने के लिए इस विश्व में कमी नहीं है। लेकिन मानव की जो लालसा है, लालच है, उसको पूर्ण करने के लिए 7 विश्व भी कम पड़ेंगे। आज मानव संकट का कारण क्यों बन रहा है?

इसलिए बन रहा है कि मानव मानवीयता से वंचित होता जा रहा है। कारण, शिक्षा में मानवीयता की शिक्षा ही नहीं है। केवल मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसको प्रकृति या भगवान ने पूर्ण स्वातंत्र्य दे रखा है। दुनिया के जितने भी प्राणी हैं (मानव को छोड़कर) उनके उपभोग पर प्रकृति ने स्वयं ही सीमा लगा रखी है, चाहे खाने की दृष्टि से हो या पीने की दृष्टि से हो। सब प्रकार के उपभोगों पर सीमा है। उसका उल्लंघन कोई प्राणी कर नहीं पाता। लेकिन मानव चाहे जो खाए, जितना उपभोग करे सब कुछ उसके विवेक पर निर्भर है। फिर भी प्रकृति या भगवान ने स्वतंत्रता देने के साथ ही मानव के पास एक अनोखा गुण प्रदान किया है। यदि मानव चाहे तो अपनी सभी वासनाओं पर संयम रख सकता है।

### संवेदनशीलता विकसित हो

मानव एवं अन्य प्राणियों में दोनों को शरीर है, शरीर का टिकना उपभोग पर निर्भर है, बिना उपभोग के सन्यासी-साधु का शरीर भी टिकता नहीं। खाना व पीना उनको भी पड़ता है। शरीर उपभोग प्रधान है। किंतु इसी के साथ हमको मन दिया है, बुद्धि दी है, आत्मा दी है। मनुष्य एकात्म है। केवल खाने-पीने वाला ही नहीं है। शरीर के कारण वासना है, शरीर के कारण संग्रह की प्रवृत्ति है, शरीर की उपभोक्ता प्रवृत्ति के कारण समाज में विषमता पैदा होती है, यह हम देखते हैं। किंतु इस शरीर के साथ भगवान ने हम को संवेदनशीलता भी दी है। दूसरे की पीड़ा देखकर हमारा हृदय द्रवित हो जाता है और उसकी पीड़ा दूर करने की प्रेरणा भी मिलती है। उन्हें पीड़ा से मुक्त किया तो बड़ा आनंद मिलता है। मानव स्वतंत्र रूप से स्वयं निर्णय करे कि उसके शरीर की उपभोग प्रवृत्ति और उसकी संवेदनशीलता, दूसरों के दुख को दूर करने में किस प्रकार प्रवृत्त हो। इन दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए? यदि यह सामंजस्य न बिठाया तो मानव स्वयं दानव बनता है। शिक्षा जब तक मानव के शरीर की उपभोग प्रवृत्ति और संवेदनशीलता अर्थात् दूसरों की पीड़ा की अनुभूति और उसके निवारण के लिए उपाय योजना की प्रेरक नहीं बनती तब तक उसे शिक्षा कहना ही गलत है।

### उपभोग और संवेदनशीलता का समन्वय हो

आत्मा की संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति शरीर के माध्यम से ही संभव होगी। इसलिए शरीर को बनाए रखना, शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को सबल रखना आवश्यक है। तब ही आत्मा की शक्ति का उपयोग होगा, सब का कल्याण होगा-- मानव दानव न बनकर सर्वकल्याणकारी बनेगा। अन्यथा, हिंदुस्तान में **सर्वे भवंतु सुखिनः** कहा नहीं गया होता। **वसुधैव कुटुंबकम** का उद्घोष नहीं होता। यह साक्षात्कार है मानव का जो भारत भूमि में किया गया। वास्तव में इन दोनों में संतुलन की क्षमता यदि निर्माण की गई तो फिर ओझोन

क्षतिग्रस्त होने का कोई कारण नहीं है, समाज में विषमता आने का कोई कारण नहीं है, समाज में गरीबी आने का कोई कारण नहीं है, समाज में किसी प्रकार की बेकारी आने का भी कोई कारण नहीं है। समाज में न किसी को अशिक्षित रहने का कोई कारण है न किसी को पिछड़ा रहने की आवश्यकता ही है। किसी को भी अछूत बनकर जिंदगी बिताने की जरूरत नहीं। क्या आज की शिक्षा ऐसे संवेदनशील मानव का निर्माण कर पा रही है?

## मानवीयता कैसे विकसित हो

दिन-प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि विषमता बढ़ रही है, अभावग्रस्त और संपन्न लोगों के बीच का अंतर बढ़ रहा है। बेकारी बढ़ रही है परेशानी बढ़ रही है, रोग बढ़ रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है? अखबार पढ़ो तो कहीं दहेज के कारण युवतियां जलाई जा रहीं हैं या आत्महत्या के लिए प्रेरित की जा रही हैं। 8-8 साल की लड़कियों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं और हम कहते हैं कि शिक्षा बढ़ रही है। साक्षरता के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं फिर यह गड़बड़ क्यों बढ़ रही है। आध्यात्मिक देश कहलाने वाला भारत आज नैतिकता की दृष्टि से कहां पहुँच रहा है? क्योंकि शिक्षा में मानव को मानवीय बनाने की गुंजाइश नहीं है। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि इस शिक्षा को मानवीय कैसे बनाएं? दूसरी बात आदमी सीखना कब से शुरू करता है इसका विचार करना होगा। शिक्षाविदों की यह धारणा कि हम लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, सही नहीं लगती। मुझे यह बताइए की छोटे बच्चों को बोलना कोई सिखाता है क्या? छोटे बच्चे बोलते हैं और बिना गलती के पूरा वाक्य बोलने लग जाते हैं। कहां क्रिया पद, कहां नाम सर्वनाम रहना चाहिए अपने आप सीख लेते हैं। ज्ञानार्जन बच्चे का शुरू से होता है। उसे आंख मिली है, उसे श्रवण शक्ति मिली है। आप लोग तो शिक्षाविद हैं - मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि बच्चा अपने दिमाग का कंप्यूटर पहले 5 वर्ष में 85 प्रतिशत पूर्ण कर डालता है। देखकर और सुनकर शिक्षा केवल विद्यालय में होती है, ऐसा नहीं है। शिक्षा परिवार में होती है। समाज के प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति क्या करते हैं- वह देखता है बड़ी पैनी दृष्टि होती है, बड़ी अच्छी श्रवण शक्ति होती है। उससे वह बराबर सतत् ज्ञान ग्रहण करता है।

## अध्यापक का दायित्व

मानव शिशु जन्म से ही अपने परिवार और परिजनों से शिक्षा ग्रहण करता है पर हम समझते हैं यह तो विद्यालय में ही पढ़ता है। इस दृष्टि से आवश्यकता है परिवार और समाज को प्रबुद्ध बनाने की। आबादी में मनुष्य कभी भी अकेला नहीं रहता। परिवार में उसकी नजर में कौन-कौन सी बातें आनी चाहिए, उसके कान पर कौन-सी बातें सुनाई देनी चाहिए जिससे इसका व्यक्तित्व सबके लिए कल्याणकारी बनेगा? जिस आबादी में वह रहता है उस

आबादी के लोगों का परस्पर व्यवहार क्या है? उसका व्यक्तित्व इन बातों से बनता है- विद्यालय में नहीं बनता। विद्यालय का काम है उसको लिखना पढ़ना सिखाए। परिवार और आबादी इन दोनों में जो बातें सामने आती हैं या कानों पर पड़ती हैं वे उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। उसे मानवीयता से संपन्न करने के लिए इन दोनों की परस्परपूरकता का दायित्व निभाने का काम विद्यालय एवं अध्यापक का है।

### अध्यापक कर्मचारी नहीं-गुरु

मैकाले को दोष देने की क्या आवश्यकता है? 53 साल हो गए आजादी को, हम क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ी गड़बड़ अंग्रेजों ने यह करके रखी है कि आज अध्यापक या अध्यापिका कर्मचारी बन गए हैं। वे स्वयं को गुरु मानते ही नहीं, कर्मचारी मानते हैं। परीक्षा के दिनों में हड़ताल करने की चाह? बच्चों पर क्या संस्कार होगा? सरकार ने भी उसको कर्मचारी बनाया, वह भी स्वयं को कर्मचारी समझता है। यूनियन बनाता है और वेतन बढ़ाने के लिए कुछ भी करता है। जब तक अध्यापक कर्मचारी के स्थान पर मार्गदर्शक, गुरु बनेगा नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। बड़े-बड़े कमीशन बिठाए जाते हैं, नीतियां तय की जाती हैं किंतु अध्यापक-अध्यापिका का छात्रों से निकट का संबंध लाने के लिए क्या हो रहा है? प्रत्येक विद्यालय में बच्चे आते हैं, विभिन्न घरों से विभिन्न संस्कार प्राप्त करके, विभिन्न आर्थिक स्तर के, विभिन्न शैक्षणिक स्तर के। हर एक विद्यार्थी के लिए क्या-क्या करने की आवश्यकता है? अध्यापक यदि गुरु के नाते नहीं करेगा तो कर्मचारी के नाते कर ही नहीं सकेगा। यह मानसिकता सरकार को भी बदलनी पड़ेगी, अध्यापकों को भी बदलनी पड़ेगी। किंतु दुर्भाग्य से सब कुछ उसी पुराने ढर्रे पर चल रहा है। बिचारा अध्यापक अपनी स्वतंत्र बुद्धि से कुछ नहीं कर सकता जबकि वही बच्चों के भी संपर्क में, उनके परिवारों के बीच संपर्क में और बच्चे जिस आबादी से आते हैं, उस आबादी के संपर्क में वही केवल रहता है। वही मानसिकता समझता है। जब तक कर्मचारी भावना हटेगी नहीं, तब तक बात भी बनेगी नहीं।

### सामाजिक दायित्व बोध जगाएं

एक अंतिम बात। समाज है- समाज के घटक हैं। यह समाज के घटक कहां से आते हैं यह शिक्षाविदों को विचार करना चाहिए। यह समाज के घटक हर परिवार में पैदा होते हैं। विभिन्न परिवारों से आते हैं। माता-पिता उन्हें जन्म देते हैं। लेकिन जो समाज के घटक परिवारों में जन्म पा रहे हैं क्या उस परिवार के माता-पिता या पूरा परिवार अपने घर में पैदा हुए बच्चे को सामाजिक-दायित्व का बोध कराने का दायित्व निभाते हैं? नहीं निभाते। जब समाज के घटकों में जन्म से ही सामाजिक दायित्वबोध न होगा तो वे समाज में मानव

के नाते व्यवहार क्यों करेंगे? जिसको जितनी शक्ति मिलेगी क्षमता मिलेगी, अधिकार मिलेगा, उतना ही वह अपने स्वयं के लिए जुटाने के लिए कोशिश करेगा, संग्रह करेगा। शरीर है उपभोग प्रधान तो उपभोग संग्रह के लिए प्रवृत्त करेगा। किंतु सामाजिक संस्कार उसके जन्म से ही नहीं है तो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप चाहे जैसी शिक्षा दीजिए, सामाजिक जीवन का दृष्टिकोण नहीं होगा तो समाज से विषमता कैसे दूर होगी या मानव मानव के नाते कैसे जिएगा? मानवीयता का उसके अंदर कहां से अंकुरण होगा? शिक्षा के इन पहलुओं की ओर ध्यान देना होगा।

### **सभी पहलुओं पर चिंतन ही**

हमारी आजीविका का प्रश्न है, हम अपने परिवार के सब लोगों के पालन पोषण के लिए आवश्यक धन कहां से जुटा सकते हैं? हमारी आजीविका क्या अपने बलबूते पर चलती है? हर एक की आजीविका तब पूर्ण होती है जब वह व्यक्ति समाज की कोई ना कोई आवश्यकता पूरी करता है। यदि लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं है तो क्या कोई अध्यापक के नाते अपनी आजीविका चला सकता है। यदि कोई बीमार ही ना पड़े तो क्या डॉक्टर की आजीविका चलेगी? किसी को बर्तन ही ना खरीदने हो तो क्या बर्तन तैयार करने वाले की आजीविका चलेगी? मानव की आजीविका चलने के लिए यह आवश्यक है कि वह समाज की कोई न कोई आवश्यकता पूरी अवश्य करता हो। इसलिए मानव को मानवीय बनना नितांत आवश्यक है। यह जो समस्याएं दिखती हैं वह इसलिए दिखती हैं कि शिक्षा क्षेत्र में इन बातों का विचार नहीं किया जाता। यदि शिक्षा में संवेदनशील प्रवृत्ति का विकास नहीं हुआ तो शिक्षा किस काम की? इसका विचार करना होगा

मुझे आप जैसे शिक्षाविदों के सम्मुख शिक्षार्थी के नाते विचार प्रकट करने के लिए कहा गया इसके लिए हार्दिक धन्यवाद।

(शैक्षणिक सुधार राष्ट्रीय संगोष्ठी में राष्ट्ररूषि नानाजी देशमुख का उद्बोधन - 14-15 मार्च 2001)

**National Seminar**  
**on**  
**“Nanaji’s Vision of Nation Building**  
**Context: National Education Policy 2020**  
**26-27 February, 2022**  
**Seminar Schedule**

| Date                      | Time                 | Details of the activities   |   |  |
|---------------------------|----------------------|---|---|--|
| 26 <sup>th</sup> February | 09.00 AM to 10.00 AM | <b>Registration</b> (Vivekanand Sabhagar)   |   |  |
| 26 <sup>th</sup> February | 10.00 AM to 11.00 AM | <b>Inaugural Session</b> (Vivekanand Sabhagar)  |   |  |
| 26 <sup>th</sup> February | 11.00AM to 11.30AM   | High Tea  |   |  |
| 26 <sup>th</sup> February | 11.30AM to 2.00PM    | <b>Technical Session 1<sup>st</sup></b> (Vivekanand Sabhagar)<br>➤ Holistic and Multidisciplinary Education<br>➤ Optimal Learning Environments and Support for Students |   |  |
| 26 <sup>th</sup> February | 2.00PM to 3.00 PM    | Lunch Break   |   |  |
| <b>Parallel Sessions</b>  |                      |   |   |  |
| 26 <sup>th</sup> February | 3.00 AM to 4.15 PM   | <b>Technical Session 2<sup>nd</sup>:</b><br>(Lohiya Sabhagar, Basement)<br>➤ Equity and Inclusion in Higher Education   | <b>Technical Session 3<sup>rd</sup> :</b><br>(Lohiya Sabhagar, Ground Floor)<br>➤ Natural farming & NEP | <b>Technical Session 4<sup>th</sup> :</b><br>(Lohiya Sabhagar, 1 <sup>st</sup> Floor)<br>➤ Technical Education |
|                           | 4.15 AM to 4.45 PM   | Tea Break   |   |  |
| 26 <sup>th</sup> February | 4.45 PM to 6.00 PM   | <b>Technical Session 5<sup>th</sup> :</b><br>➤ Promotion of Indian Languages, Arts and Culture  | <b>Technical Session 6<sup>th</sup> :</b><br>➤ Life Long Learning                                       | <b>Technical Session 7<sup>th</sup> :</b><br>➤ Reimagining Vocational Education                                |
| 26 <sup>th</sup> February | 6.00 PM to 6.30 PM   | High Tea Break  |   |  |
| 26 <sup>th</sup> February | 6.30 PM to 7.30 PM   | <b>Technical Session 8<sup>th</sup>:</b> (Vivekanand Sabhagar)<br>Open Discussion   |   |  |
| 26 <sup>th</sup> February | 7.30 PM to 9.00 PM   | <b>Cultural programme:</b> (Vivekanand Sabhagar)  |   |  |
| 26 <sup>th</sup> February | 9.00 PM to 10.30 PM  | Dinner  |   |  |
| 27 <sup>th</sup> February | 9.30 AM to 11.00 AM  | Plenary Session : (Vivekanand Sabhagar)   |   |  |

## उद्घाटन सत्र - 26 फरवरी 2022

भारत रत्न नानाजी देशमुख की 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर चित्रकूट में दीनदयाल शोध संस्थान एवं महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के संयोजन में दीनदयाल परिसर के विवेकानंद सभागार में नानाजी की दृष्टि में राष्ट्र निर्माण: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ।

जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इंद्र सिंह परमार, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री प्रदीप जोशी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और भारत में कृषि शिक्षा के सचिव डॉ त्रिलोचन महापात्रा के साथ प्रदेश के अनेक विश्वविद्यालयों के कुलपतियों सहित मध्य प्रदेश से बाहर के 12 राज्यों के कुलपतियों ने उद्घाटन सत्र में सहभागिता की। हाईब्रिड मोड में प्रारंभ इस संगोष्ठी में प्रख्यात चिंतक श्री ए. बी.एम.राजू, ग्रामोदय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं संयोजक राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रो. एनसी गौतम, ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. भरत मिश्रा, दीनदयाल शोध संस्थान के प्रधान सचिव श्री अतुल जैन और संगठन सचिव श्री अभय महाजन उपस्थित रहे।

मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि श्रद्धेय नानाजी का शैक्षिक चिंतन उनके अन्य सामाजिक आयामों के चिंतन की तरह अति विशिष्ट था, नयापन लिए हुए था। देश में जिस महत्वकांक्षी दस्तावेज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत निर्माण के लिए आवश्यक शिक्षा का सपना देखा, उसे नाना जी ने चित्रकूट में वर्ष 1991 में सोच रखा था। यह जानकार सुखद अनुभूति होती है कि नाना जी के शैक्षिक चिंतन पर आधारित नवाचार और अभिनव प्रयोग चित्रकूट के ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए हैं। आज मध्य प्रदेश सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को पूरी तत्परता और समर्पण के साथ प्रतिबद्धता पूर्वक लागू करने वाले राज्यों में सबसे आगे है। नाना जी के चिंतन के विचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाहित हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान प्रभावी ढंग से लागू होते हैं तो नानाजी का शैक्षिक चिंतन भी देश के कोने कोने में पहुँचेगा। अतः हमारे लिए महत्वपूर्ण अवसर है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समग्र रूप में लागू किए जाने की जो चुनौतियां सम्मुख हैं उन पर विचार विमर्श कर उन्हें एक रोडमैप, एक ब्लूप्रिंट बने यही इस संगोष्ठी का प्रमुख लक्ष्य है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. त्रिलोचन महापात्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज जो शिक्षा के किसी भी आयाम पर देश सोच रहा है उसे नाना जी ने तीन दशकों पहले ही क्रियान्वित करना प्रारंभ कर दिया था, यह उनकी दूरदृष्टि थी। नाना जी का चिंतन सदैव समग्रता पर रहा और इसलिए उन्होंने ग्रामोदय विश्वविद्यालय की परिकल्पना की। जिसमें ग्रामीण जीवन के बहुआयामी जीवन के समस्त पक्षों को प्रधानता मिल सके।

संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री प्रदीप जोशी ने नानाजी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आयोजन को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि मैं विविध सेवाओं के लिए चयन हेतु देश की सर्वोच्च संस्था के प्रतिनिधि के रूप में मंच पर हूँ, इसलिए इस देश के युवाओं की नौकरी के प्रति आकर्षण का प्रत्यक्ष गवाह हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी आत्मनिर्भर भारत का स्वर सबसे मुखर है मुझे विश्वास है कि संगोष्ठी के निष्कर्ष पूरे देश को दिशा देने वाले होंगे।

विषय प्रवर्तन करते हुए ग्रामोदय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और राष्ट्रीय संगोष्ठी के संयोजक प्रो नरेश चंद्र गौतम ने आयोजन की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और नाना जी के विचारों को गौर से देखें तो लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नाना जी की अभिलाषा और अपेक्षाओं का जीवंत दस्तावेज है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सम्मुख उपस्थित चुनौतियों का सर्व सम्मत समाधान खोजने की दिशा में यह एक दूरगामी और निर्णायक पहल है।

स्वागत उद्बोधन में दीनदयाल शोध संस्थान के प्रधान सचिव श्री अतुल जैन ने अतिथियों का शब्द सुमन से स्वागत किया, उन्होंने कहा नाना जी के संकल्पों को साकार करना ही उनको दी गई सच्ची श्रद्धांजलि है। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में आप सभी विद्वानों के अभिमत से जो रूपरेखा तैयार होगी। वह चित्रकूट घोषणा के नाम से संगोष्ठी के निष्कर्षों में अभिव्यक्त होगी।

उद्घाटन सत्र का आरंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ, इस दौरान दीनदयाल शोध संस्थान के उपाध्यक्ष श्री निखिल मुंडले और कोषाध्यक्ष श्री वसंत पंडित द्वारा मंचासीन अतिथियों का शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। संचालन दीनदयाल शोध संस्थान के महाप्रबंधक श्री अमिताभ वशिष्ठ द्वारा किया गया।







## 12 राज्यों से 33 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की रही सहभागिता

- हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय हिसार से कुलपति प्रोफेसर बीआर कंबोज
- छत्तीसगढ़ के अटल बिहारी वाजपेई हिंदी विश्वविद्यालय से कुलपति प्रोफेसर एडीएन बाजपेई, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से प्रोफेसर आलोक चक्रवाल
- गुजरात के कृषि विश्वविद्यालय बनासकांठा से डॉक्टर रवि चौहान
- जम्मू कश्मीर के राज्य कृषि विश्वविद्यालय जम्मू से प्रोफेसर जेपी शर्मा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से डॉक्टर संजीव जैन
- मणिपुर से केंद्रीय विश्वविद्यालय, इंफाल के कुलपति डॉक्टर अनुपम मिश्रा
- राजस्थान राज्य के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के प्रोफेसर एनएस राठौर
- उत्तर प्रदेश राज्य के विश्वविद्यालय में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से प्रो मुकेश पांडे, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा से प्रोफेसर नरेंद्र प्रताप सिंह, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से प्रो निर्मला मौर्य, जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट से प्रो योगेश चंद्र दुबे, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से डॉ. के.के. सिंह
- मध्य प्रदेश राज्य के इंदिरा गांधी ट्राईबल विश्वविद्यालय अमरकंटक से प्रोफेसर प्रकाश मणि त्रिपाठी, ए पी एस विश्वविद्यालय रीवा से डॉक्टर राजकुमार आचार्य, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से प्रो भरत मिश्र, पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मुकेश कुमार तिवारी, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से डॉक्टर प्रदीप कुमार विशेन, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर से डॉक्टर एसपी तिवारी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से प्रोफेसर कपिल देव मिश्रा, डॉ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से प्रोफेसर नीलिमा गुप्त, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर विश्वविद्यालय महु से डॉक्टर दिनेश शर्मा, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से डॉ एसके राव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल से प्रोफेसर आरजे राव, राजा मानसिंह संगीत कला विश्वविद्यालय ग्वालियर से डॉ. साहित्य कुमार नाहर, ए.के.एस. विश्वविद्यालय सतना से प्रोफेसर अनंत सोनी, महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय, छतरपुर प्रोफेसर टीआर थापक
- अरुणाचल प्रदेश से राजीव गांधी विश्वविद्यालय से प्रोफेसर साकेत कुशवाह
- महाराष्ट्र के महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से प्रोफेसर रजनीश शुक्ला
- कर्नाटक के वैल्लूर तकनीकी विश्वविद्यालय बेलगावी से डॉक्टर करीसिद्धप्पापा
- नई दिल्ली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शांतिश्री पंडित
- नागालैंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय शिलांग से डॉ प्रभाशंकर शुक्ला प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

# केंद्रीय मंत्री, श्री प्रहलाद पटेल ने आजादी का अमृत महोत्सव प्रदर्शनी का किया उद्घाटन

**कृषि एवं स्वावलंबन के साथ इलेक्ट्रिक चाक रहा प्रदर्शनी में आकर्षण का केंद्र**

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत रत्न राष्ट्रऋषि नानाजी देशमुख की 12 वीं पुण्यतिथि एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी के अवसर पर दीनदयाल परिसर चित्रकूट में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिसमें देशभर के प्रमुख क्रांतिकारियों सहित स्थानीय क्रांतिवीरों को प्रदर्शनी के माध्यम से रेखांकित किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ भारत सरकार के जल शक्ति राज्यमंत्री श्री प्रहलाद पटेल एवं मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने भारतमाता व नानाजी देशमुख के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्चन कर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया।

प्रदर्शनी के माध्यम से औद्योगिक विकास के नवीनतम क्षेत्रों में जिला वार कृषि विस्तार करके कर्मियों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने के साथ साथ उन्नतशील बीजों के क्षेत्र पर उत्पादन तथा बीज ग्राम कार्यक्रम के माध्यम से किसानों के खेतों पर उत्पादन एवं आय वृद्धि हेतु अन्य कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की गई तथा स्थान विशेष के लिए नई तकनीक, बीज एवं रोपण सामग्री को किसानों के खेत पर परीक्षण, किसानों के खेतों पर विभिन्न फसलों, पशुपालन एवं अन्य कृषि आधारित उद्योगों की उत्पादन क्षमता के प्रदर्शन का आयोजन करना, साहसिक प्रवृत्तियों का विकास कर सृजनशीलता के प्रति विश्वास में बढ़ोतरी करके स्वरोजगार को बढ़ावा देना जिससे उसके स्वयं के स्वावलंबन के साथ-साथ वह देश के आर्थिक विकास की वृद्धि में सहभागी बन सके। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरी ताजी औषधियों के माध्यम से आजीवन स्वास्थ्य सम्वर्धन की दृष्टि से रसशाला द्वारा उत्पादों का प्रदर्शन किया किया।

इस प्रदर्शनी में कृषि विज्ञान केंद्र, मझगवां, नौगांव, पन्ना, टीकमगढ़, रीवा के साथ-साथ सदुगुरु सेवा संघ ट्रस्ट, जानकी कुण्ड, जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, खादी ग्राम उद्योग विभाग सीधी, ए.के.एस. विश्वविद्यालय सतना, आरोग्यधाम, रसशाला, उद्यमिता विद्यापीठ तथा कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित जन शिक्षण संस्थान द्वारा अपनी अपनी प्रदर्शनी के स्टॉल लगाकर लोगों को अपने जीवन में अपनाने हेतु प्रेरित किया गया।





# प्रमुख वक्ताओं के उद्बोधन

# प्रो. प्रदीप जोशी

अध्यक्ष, संघ लोकसेवा आयोग



**वि**राट व्यक्तित्व के स्वामी नानाजी देशमुख को प्रणाम करता हूँ उनकी यह 12 वीं पुण्यतिथि है और 12 वीं पुण्यतिथि पर दीनदयाल शोध संस्थान एवं चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के संयोजन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में जो संविमर्ष आयोजित किया गया यह बहुत महत्वपूर्ण एवं मील का पत्थर साबित होगा और सम विमर्श के पूर्ण होने के उपरांत यहां से जो घोषणा होगी वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी ऐसा पूर्ण विश्वास है। पूज्य नाना जी के शिक्षा के संबंध में, कृषि के संबंध में, ग्रामीण स्वावलंबन के संबंध में जो एक परिकल्पना थी उस परिकल्पना को डीआरआई के द्वारा उन्होंने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। इससे चित्रकूट ही नहीं गोंडा बलरामपुर, बीड़ एवं अन्यान्य स्थानों पर रहने वाले सैकड़ों हजारों परिवारों के जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। शिक्षा से उनका बहुत पुराना संबंध था जैसा की प्रोफेसर

गौतम साहब ने भी यहां पर बताया कि जब वह गोरखपुर में काम के लिए भेजे गए तो उन्होंने वहां पर सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की जो आज विशाल वटवृक्ष के रूप में खड़ा होकर देश के विभिन्न स्थानों पर समाज परिवर्तन और राष्ट्रियता की भावना को प्रबल करने के काम को बहुत प्रभावी ढंग से कर रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यदि सार रूप में हम देखें उसके शिक्षा से समाज परिवर्तन और राष्ट्रवाद किस प्रकार से प्रबल हो सकता है नई शिक्षा नीति में इसका समावेश है। शिक्षा की पहली नीतियों का 1986 और 1992 और जिसको हम 1986 की नीति पर एक संशोधन मानते हैं प्रमुख रूप से उसका उद्देश्य यह रहा कि शिक्षा का व्यापीकरण हो और प्रत्येक छात्र को शिक्षा मिल सके। लेकिन सत्र 2020 के द्वारा शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण करना और स्वावलंबन युक्त करना इसमें अधिक प्रयास है।

व्यावसायिक शिक्षा में नैतिकता हो,

इंजीनियरिंग प्रबंधन वास्तुकला टाउन प्लानिंग इन सभी में एथिकल वैल्यूज नैतिकता का समावेश हो, जिसमें महत्वपूर्ण

**जैसा कि हम जानते हैं कि अध्यापक का शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और अध्यापक के उस मर्म को नई शिक्षा नीति में स्थापित करने की कोशिश की गई है और मैं समझता हूँ कि वह सफल भी होगी। पिछले वर्षों में हम देखते हैं कि शिक्षकों को किन-किन नामों से संबोधित किया गया है, क्या-क्या प्रकार के काम उसको दिए जाते हैं। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में अध्यापक के स्थान को महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया है और अध्यापक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी है।**

यदि हम आज कहीं पर भी किसी से बात करें किसी परिवार में जाते हैं और उस बच्चे से हम यह पूछते हैं कि तुम आगे चलकर क्या बनना चाहते हो तो बहुत कम प्रतिशत ऐसा निकलेगा यहां पर बालक बचपन में यह कहेगा कि मैं अध्यापक बनना चाहता हूँ वह बताएगा कि मैं प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, लेकिन अध्यापक बनना चाहता हूँ यह मुश्किल से कहेगा।

मैं जब विद्यालय शिक्षा में था तब उस समय के एक अध्यापक मेरे रोल मॉडल हैं, उनकी उम्र 94 वर्ष है। और वे अभी भी हैं, जब भी मैं कानपुर जाता हूँ उनको प्रणाम

करने अवश्य जाता हूँ। जब मैं दसवीं कक्षा में था तो एक बार कक्षा में ऐसी चर्चा चली कि कौन सा बालक आगे चलकर क्या कार्य करना चाहता है तो जब मेरे सामने यह प्रश्न आया तो मैंने खड़े होकर के उत्तर दिया कि मैं भविष्य में अध्यापक बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि यहां पर जो डिबेट होती है और अन्य परिचर्चाएं होती हैं उनमें तुम्हारा रोल देखता हूँ तो तुम्हें आगे चलकर प्रशासनिक सेवा की तैयारी करनी चाहिए। मैंने कहा लेकिन मैं आपको पिछले 4 वर्षों से देख रहा हूँ 4 वर्षों से मैं आपसे अंग्रेजी की कक्षा में पढ़ता हूँ और आपको देखकर मुझे लगता है कि मुझे भी अध्यापक बनना चाहिए। आपकी कई चीजें यह हममें आत्मसात हो गई हैं। आपके पेन रखने का ढंग, आपकी किताबे रखने का ढंग, आपके चलने का ढंग इन सबको हम आत्मसात करते हैं नकल करते हैं।

**अध्यापक का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसको मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल उदाहरण से बताता हूँ और इसलिए नई शिक्षा नीति के अंदर अध्यापक का रोल बहुत प्रभावी है। आप में से यहां बैठे हुए बहुत से लोगों ने प्रोफेसर रघुनाथ अनंत माशेलकर का नाम अवश्य सुना होगा। कई सम्मानित वाइस चांसलर हैं, जो प्रोफेसर माशेलकर से मिले भी होंगे। प्रोफेसर माशेलकर सीएसआईआर के डायरेक्टर जनरल रहे, प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे।**

1999 में मेरा लखनऊ जाना हुआ कोई कार्यक्रम भी था, मेरे साथ में लगभग 21 नौजवान विद्यार्थी भी थे और मेरा प्रोफेसर माशेलकर से मिलना हुआ। जब उनसे मिले और उन्होंने हमें एक बड़े कमरे में बैठाया। मैंने प्रोफेसर माशेलकर से कहा कि आप इन नौजवानों को अपने जीवन की स्टोरी के बारे में बताइए, उन्होंने कहा ठीक है उन्होंने जब वार्तालाप प्रारंभ किया वह सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक प्रेरणादायी रहा। सभी विद्यार्थियों में से 20 में से 15 विद्यार्थी आज देश के बहुत महत्वपूर्ण स्थानों पर विद्यमान हैं।

प्रोफेसर माशेलकर ने कहा कि मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ जब मैं पढ़ता था तो मेरे बचपन में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। मेरी मां ने लोगों के घरों में बर्तन मांज कर किसी तरह मुझको पाला पोसा। गांव के जिस विद्यालय में मैं पढ़ना चाहता था मैं यह सोचता था कि मैं आठवीं तक वहां शिक्षा प्राप्त कर पाऊंगा, क्योंकि गांव में आठवीं तक का ही विद्यालय था। इसके आगे की शिक्षा की व्यवस्था गांव में नहीं थी। लेकिन वहां के जो प्रधानाध्यापक थे वह हमको विज्ञान पढ़ाते थे और जब वह हमको विज्ञान पढ़ाते थे तो वह सभी विषयों को प्रैक्टिकल करके पढ़ाते थे। अर्थशास्त्र भी प्रैक्टिकल करके पढ़ाया जा सकता है, समाजशास्त्र भी और इतिहास को भी प्रैक्टिकल करके पढ़ाया जा सकता है कॉमर्स और प्रबंधन को तो पढ़ाया ही जा सकता है।

उनके अध्यापक ने बताया कि जब सूर्य की निर्जीव किरणें एक स्थान पर एकत्रित हो जाती हैं और वे एक जगह एकत्रित होकर कितनी बड़ी शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है कि वह घास में भी आग लगा देती है और भयंकर ऊर्जा भी पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा इतना ही नहीं तुम यह समझ लो यदि तुमने अपने शरीर की सारी ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा कर दिया तो तुम क्या नहीं कर सकते, तुम्हारे मन के अंदर जो कुछ भी आता है तुम दुनिया में वह सब कुछ कर सकते हो।

प्रोफेसर माशेलकर कहते हैं उस दिन मैं चुपचाप खड़ा होकर अपने अध्यापक की उन बातों को सुन रहा था कि जब तुम अपने सजीव शरीर की सभी शक्तियों को इकट्ठा कर लो तो तुम जो चाहे वह कर सकते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है **‘जो इच्छा करियो मन माही प्रभु प्रताप कुछ दुर्लभ नाही।’**

तो उस बालक के मन में आया कि अब मेरी शिक्षा आठवीं तक ही नहीं रुकेगी, विज्ञान की आखिरी स्तर तक की जो शिक्षा होगी उस स्तर तक की मैं शिक्षा प्राप्त करूंगा और विज्ञान का मैं मर्मज्ञ विद्यार्थी बनूंगा यह संकल्प लिया।

कहने का तात्पर्य यह है कि एक अध्यापक की भूमिका ने प्रोफेसर माशेलकर जैसे इतना बड़ा वैज्ञानिक खड़ा किया, तो हम जिस भी विश्वविद्यालय से आते हैं हम यह देखते हैं कि अध्यापक की भूमिका वहां

पर कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है और अध्यापक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका से कितना बड़ा विद्यार्थी, कितना बड़ा वैज्ञानिक बना सकता है। तो ऐसे ही जो सामने युवा शक्ति बैठी है उन सभी छात्रों से यह कहना चाहूँगा कि यदि हम अपने अध्यापक की एक कक्षा भी मिस कर देते हैं या छोड़ देते हैं तो हम कितनी बड़ी पूंजी खो देते हैं, यह समझना चाहिए। इसलिए नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर अध्यापकों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह हमको यहां पर देखने को मिलता है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात उसमें यह है कि मातृभाषा में शिक्षा। मातृभाषा में शिक्षा का होना यह किसी को भी बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। 2004 में मेरी भेंट हिरोशिमा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से हुई, वहां वाइस चांसलर को प्रेसिडेंट बोलते हैं, प्रोफेसर शिंजो आबे से हुई। मैं उस समय नीपा में डायरेक्टर था। हम लोग वहां पर गए। वहां के कार्यक्रम को भारत में आयोजित करने की जिम्मेदारी थी और वहां के सहयोगियों ने बताया कि यहां के लोगों को जापानी के अलावा और दूसरी कोई भाषा आती ही नहीं। लेकिन वह विश्व के प्रमुख चार बड़े वैज्ञानिकों के अंदर गिने जाते हैं और वह भी नाभिकीय वैज्ञानिक न्यूक्लियर साइंटिस्ट के अंदर। तो हम अपने मन का यह भ्रम भी निकाल लें कि जिसको मातृभाषा के अलावा

दूसरी भाषा का ज्ञान नहीं है वह अच्छे स्तर तक नहीं जा सकता। मातृभाषा के अंदर हमारे हृदय के विचार प्रस्फुटित होते हैं। इसका भी यहां बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।

नई शिक्षा नीति के अंदर विभिन्न विचारक आज यहां बैठेंगे, विभिन्न सत्रों के अंदर विभिन्न विषयों के ऊपर विचार करेंगे, निश्चित रूप से इस विषय के ऊपर भी उसमें विचार होगा कि विश्वविद्यालयों से, विद्यालयों से निकलने वाला विद्यार्थी इस बारे में भी चिंतन करता है कि मेरे बड़े होने में, मेरे संपूर्ण विकास में, मेरे बनने में इस पूरे समाज का योगदान रहा है। हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कई संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, तमाम संस्थाएं हैं और उन संस्थाओं के खर्च कैसे चलते हैं, विश्वविद्यालयों के खर्च कैसे चलते हैं, सरकार द्वारा दिए गए अनुदान से चलते हैं और यह सरकार अनुदान कहां से लाती है। जब समाज के गरीब से गरीब घर का भी, एक रिक्शा चलाने वाला भी, एक कुली भी धनिया-मिर्चा-हल्दी खरीदता है जिसमें वह जीएसटी देता है, टैक्स देता है तब जाकर यह बड़ा स्वरूप टैक्स के रूप में एकत्रित होकर सरकार के पास एकत्रित हुआ है और उसमें से संस्थाओं को देकर शिक्षा के विकास की चिंता की है।

# डॉ. मोहन यादव

उच्च शिक्षा मंत्री मध्यप्रदेश शासन



**ह**म जिस क्षेत्र से आते हैं आमतौर पर राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी सीमा बंध जाती है कि हमको बोलने में एक भाव को समझने की आवश्यकता पड़ती है कि जिस विषय से हमको जोड़ा है। लेकिन मुझे इस बात का संतोष भी है, ये जिस शिक्षा की बात करने के लिए आज खड़े हैं उस शिक्षा का अहंकार भी कई बार बहुत तकलीफ दे जाता है। हम जिससे बात करते हैं पहले उसका क्वालिफिकेशन पूछ लेते हैं कि कहां तक पढ़ा है उससे बात करने के पहले अपना चश्मा विशेष नंबर का सेट कर लेते हैं कि वह जिस लेवल की बात कर रहा है वह कहां तक पढ़ा है, तो आज जो सेमिनार यहां पर आयोजित हो रहा है तो मुझे इस बात का भी संतोष है कि हमारे नानाजी ने उस मिथक को तोड़ा है कि स्वयं जिन्होंने केवल दसवीं तक विद्यालय शिक्षा ग्रहण की है लेकिन सारे पढ़े-लिखे लोगों के सामने उन्होंने कैसा मार्ग

प्रशस्त किया है, ये सर्वोत्तम उदाहरण हमारे ग्रामोदय विश्वविद्यालय, समग्र ग्राम की धारणाएं, स्वावलंबन की धारणा या शिशु मंदिर की लंबी कतार हम सबको उसका परिचय कराती हैं।

एकलव्य का उदाहरण हमें कहीं ना कहीं ध्यान में आता है। एकलव्य के जीवनकाल का वह दृश्य भी याद करेंगे जिसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए दरवाजे के अंदर नहीं जाने को मिला, पढ़ने पढ़ाई की कठिनाई उस समय पर भी थी लेकिन अच्छी बात जो थी वह महत्व की थी कि उसको अंदर आने की व्यवस्था नहीं थी, यह दिक्कत समझ में आती है कि किसी ना किसी कारण से एकलव्य को रोका गया, लेकिन पाठ्यक्रम कितना सरल था कि वह अपने घर पर बैठा हुआ अर्जुन से भी बेहतर पढ़ गया और उसको हस्तसिद्ध कर पाया और हमने इसको समझ लिया तो हमें पूरी शिक्षा नीति समझ में आ जाएगी कि हम जो पढ़ रहे हैं

एकलव्य को रोका गया, लेकिन पाठ्यक्रम कितना सरल था कि वह अपने घर पर बैठा हुआ अर्जुन से भी बेहतर पढ़ गया और उसको हस्तसिद्ध कर पाया और हमने इसको समझ लिया तो हमें पूरी शिक्षा नीति समझ में आ जाएगी कि हम जो पढ़ रहे हैं और हम जो कर रहे हैं और उसके उपयोग क्या है उसके तरीके क्या हैं इस पर ध्यान देना चाहिए।

और हम जो कर रहे हैं और उसके उपयोग क्या है उसके तरीके क्या हैं इस पर ध्यान देना चाहिए।

यह बात भी सही है कि आजादी के पहले के विश्वविद्यालयों की तरफ निगाहें बढ़ाएं तो हमको काशी हिंदू विश्वविद्यालय ध्यान में आता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कौन-कौन से संकाय थे, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय भी कमोबेश उसी प्रकार का था और आज जब हम बात कर पा रहे हैं तो एक अच्छा तुलनात्मक विश्लेषण भी सामने आया कि **शिक्षा का स्तरीकरण कैसा होना चाहिए तो यह बात भी सही है कि शिक्षा का स्तरीकरण प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक का एक साथ होना चाहिए। यह नानाजी का दृष्टिकोण है जो हमारी शिक्षा नीति भी यही कहती है।**

लेकिन वास्तव में ये जो 30-40 वर्ष का समय हमारा गया वह तो वापस नहीं आ सकता नाना जी ने जब बोला तो अब जो यह 30-40 वर्ष का समय चला गया उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती।

मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, क्षेत्रीय

भाषा में शिक्षा होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, आज भी कितना दम लगाना पड़ता है यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम अपनी शिक्षा की बात कर रहे हैं लेकिन भाषा के विवाद में झगड़ते हैं। भाषा को लेकर विवाद खड़े होते हैं। कमोबेश प्रजातंत्र के अंदर हमें अच्छे परिणाम मिले हैं किंतु हमारे अपने दायरों में कहीं ना कहीं हमको जो व्यवस्था को समझने में अंतर पड़ा है वहीं कष्ट हुआ है उसी प्रकार हम आपने जो कहा कौशल शिक्षा को लेकर की शिक्षा में कौशल होना चाहिए। धीरुभाई अंबानी से लेकर बहुत सारे उदाहरण हैं राजू जी स्वयं उपस्थित हैं।

मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए प्रोत्साहन चाहूँगा तालियां चाहूँगा कि जिन्होंने लकीर को तोड़ा और ऐसी शिक्षा नीति प्रस्तुत की जो राष्ट्र के समक्ष है और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए भी तालियां चाहूँगा जिन्होंने सर्वप्रथम पूरे प्रदेश में इसे लागू किया। अपने राज्य में उच्च शिक्षा विभाग को अपने कार्यों को करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। जिसके बलबूते पर आज हम अपनी

बात रख भी पा रहे हैं और यह बात भी सही है कि हमने जो अपनी बात रखी है इन सभी त्रुटियों को ध्यान में रखकर हम देश को लाभान्वित कर सकते हैं और इसके आधार पर जो नई शिक्षा नीति के अंदर बहुत सारी नई बातें भी जुड़ रही हैं उसको समाविष्ट करने का रास्ता भी ढूंढ रहे हैं।

ऐसे ही जो हम शिक्षा की बात करते हैं तो हम अपने अतीत काल में देखते हैं तो हमारे यहां तो पंचतंत्र की कहानियों से शिक्षा की व्यवस्था थी। हम सबको मालूम है कि पंचतंत्र के आचार्य विष्णु शर्मा जी किस ढंग से अपनी बात कहते हैं या मैं जहां से आता हूँ सम्राट विक्रमादित्य की 32 पुतलियों की कहानी याद करें तो उन 32 पुतलियों की कहानी में शिक्षा के आयाम तो है ही एक से बढ़कर एक, सारी कहानियों के सिंहासन तो एक सिंबॉलिक है प्रतीकात्मक है, लेकिन शासन में बैठने वाले की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए इससे अच्छा उत्कृष्ट उदाहरण क्या हो सकता है। जो आज नहीं 2000 साल पुरानी बात करता है। सिंहासन बत्तीसी और राजा भोज दोनों में 1000 साल का अंतर है पर दोनों के मापदंड समान है।

हमारे प्राचीन आयुर्वेद का ज्ञान भी हमको मालूम है कि कोरोना के समय में चिकित्सा की पद्धतियों की जो बात है तो वापस नानाजी का वह दादी मां का बटुआ याद आ जाता है जो गांव गांव के अंदर उन्होंने कल्पना की थी। जरूरी नहीं कि सब एलोपैथी पर आधारित हो, एलोपैथी में भी क्या-क्या हो सकता है। अभी हमको कोरोना के काल में सबसे पहले अगर कुछ याद आया तो वह काढ़ा के अलावा और क्या मिला था। सारी की सारी एलोपैथी हाथ टेक चुकी थी लेकिन आयुर्वेद के दम पर, नेचुरोपैथी के दम पर हमारा समाज खड़ा रहा और सफल बना रहा और वह प्राचीन ज्ञान जो हमारी रसोई में भी उपलब्ध है उसके कारण हम सब सफल बने रहे। यह बात भी सही है कि एलोपैथिक की चुनौती भी मिली तो टीका में भी भारत पीछे नहीं रहा, ऐसे सारे के सारे एलोपैथी वालों को भी धन्यवाद कि हमारे एक निश्चित समय में 8-9 महीने के अंदर हमने दुनिया को वह सब कुछ करके दिखाया जिसके बलबूते पर भारत की एक और साख नए रूप में भी बनी।

# डॉ. त्रिलोचन महापात्रा

महानिदेशक- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद



**म**हान व्यक्तित्व श्री नानाजी की पुण्यतिथि पर उनके योगदान, उनकी सोच व राष्ट्र निर्माण के लिए उस दिशा में सोचना, चर्चा करना और उनके सोच का क्रियान्वयन करना हर एक व्यक्ति का दायित्व बनता है और आज के विशेष दिन हम सब लोग एकत्रित हुए हैं कि किस तरीके से उनकी सोच को एक उत्सव के रूप में व्यवहार करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो निर्माण किया गया है, हम सब के लिए गौरव की बात है और यह दो दिवसीय कार्यक्रम में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है उसके लिए मैं

दीनदयाल शोध संस्थान के समस्त कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसके बारे में विस्तारित रूप से चर्चा होगी और आप सब लोग उस में भाग लेंगे संक्षिप्त में दो बात करना चाहूँगा एक है कि शिक्षा नीति 2020 भारतीयता के ऊपर आधारित है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है धीरे-धीरे हम सब लोग जितने आज यहां उपस्थित हैं और नहीं भी हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं हम लोग कितने शिक्षित हैं यह एक बहुत बड़ा प्रश्न बाकी है।

जो चर्चा आज जो शुरू हुआ और कल

भारत में पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा है लेकिन शिक्षा दान के कार्यक्रम कितनी सफलतापूर्वक चल रहा है? यह हम सब को गहराई से सोचना चाहिए और चर्चा भी करना चाहिए। जिस दिशा में नानाजी ने सोचा और जिस दिशा में हमारे ऋषि-मुनियों ने सोचा था और जिस दिशा में हमारे पारंपरिक शिक्षा पद्धति चलते आ रही थी और कई विदेशियों के कारण जिस तरीके से हमारे सोसाइटी में डिस्ट्रक्शन आया और वह पुरातन पद्धति धीरे-धीरे विलुप्त होने लगा। जिससे हम शिक्षित नहीं बन पाए लेकिन हम पढ़े-लिखे जरूर बन पाए। पढ़ना लिखना आता है लेकिन वास्तव में हम शिक्षित नहीं हैं।

तक चलेगा और डिक्लेरेशन भी आएगा, चित्रकूट डिक्लेरेशन और इसमें मैं समझता हूँ शिक्षा ग्रहण कैसे होना चाहिए, शिक्षक किसको बोलते हैं जिस शिक्षक के जीवन में कोई आदर्श नहीं वह शिक्षक काम नहीं कर सकता। कैसे पढ़ाया जाता है कैसे सिखाया जाता है, अक्षर कैसे लिखते हैं वह सब बता देगा लेकिन शिक्षा दान नहीं कर सकता। जो अपने जीवन में कभी डिसिप्लिन नहीं बनाया वह किसी को डिसिप्लिन क्या सिखाएगा और डिसिप्लिन होने के लिए डिसाइपल बनना पड़ता है।

भारतीयता केवल संस्कृत को आधार करके भारतीयता नहीं बन सकता, संस्कृत माध्यम है। संस्कृत माध्यम व्यवहार करने के लिए किस तरीके से वास्तव रूप में भारतीयता को अपनाया जा सकता है इस पर चर्चा होना चाहिए और जितना गहराई से हम चर्चा करेंगे बहुत सारे मूल्य, आदर्श, बातें, तथ्य हमारे सामने आएंगे और हम सब लोगों को इसमें से जैसे नाना जी बताए थे हमारे ऋषि-मुनियों ने बताए।

स्वामी जी की एक बात याद आती है कि हम सब लोग शिक्षा और सूचना दोनों में विस्मृत होने लगे हैं और हम यह जानने लगे हैं कि जिसके पास ज्यादा सूचना है वह ज्यादा शिक्षित है, अगर ऐसा होता तो जितनी लाइब्रेरी हैं वह सब सेठ बन जाते हैं और जितने इनसाइक्लोपीडिया हैं वह सब ऋषि मुनि हो जाते अर्थात् यह नहीं है।

हम किताब पढ़कर किताब बन गए हैं लेकिन उसके एसेंस को आत्मसात करना या एसेंस है तो मेरे ख्याल में हमारी जो चर्चा उसी दिशा में होगी और हम सब लोग नई दिशा देकर जाएंगे और इस पेशावर तरीके से हम अपनी पुरातन शिक्षा पद्धति और हमारी सोच में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं और बचपन से शिक्षा मात्र गर्भ से शुरू हो जाता है।

ऋषि मुनियों की बातें हैं और विज्ञान उसी को प्रमाणीकरण कर रहा है और यहां कैसे परिवर्तन होगा, हमारे संस्कार क्या हैं और उनके अंतर्गत कैसे मातृ गर्भ से शिक्षा प्रदान होती हैं तो उसी प्रकार पहले की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, वहां से कैसे परिवर्तन होगा। ताकि बेसिक शिक्षा पर आमूलचूल परिवर्तन लाया जा सकता है और नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई है उसको ध्यान में रखते हुए हमने भारत का कृषि शिक्षा नीति बनाई हैं।

कृषि आधारित पूरे देश में लागू करने के लिए माननीय मंत्री जी द्वारा सभी राज्य सरकार को लिखा गया है और उसका पूरा डॉक्यूमेंट दिया गया है और हमारी तरफ से सारे चीफ सेक्रेट्रीज को इसके बारे में लिखा गया है कि कृषि शिक्षा नीति 2020 ऐसी शिक्षा नीति के तहत क्या-क्या होना चाहिए और क्या-क्या करना चाहिए तो इसका इंप्लीमेंटेशन हो इसके बारे में चर्चा होगी उदाहरण बनाना होगा।

# डॉ. भरत शरण सिंह

अध्यक्ष, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय  
विनियामक आयोग



**स**म्माननीय मंच एवं आत्मीय विद्वत जन सबसे पहले मैं भारत रत्न राष्ट्रऋषि नानाजी देशमुख के प्रति समर्पण भाव अर्पित कर रहा हूँ, कल 27 फरवरी को उनकी पुण्यतिथि है। विश्व को एक नई आईडियोलॉजी दिए एकात्म मानववाद की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, इस प्रकार से यह जो परिसर है दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा जो एक एकात्म मानववाद की कल्पना की गई इसका जो व्यवहारिक स्वरूप धरातल पर प्रारंभ किया गया उसका यह एक जीता जागता प्रकल्प है। जो भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल के रूप में है।

यह दोनों ही महापुरुष जिस प्रकार से भगवान राम ने समाज के लिए वनवास गमन किए, इस समाज के लिए भगवान कृष्ण ने अनेकों कष्ट उठाए, महाराणा प्रताप वन वन भटके, गुरु गोविंद सिंह ने अपने पुत्रों का समाज की रक्षा के लिए जीते जी दीवारों में चुनवा दिया। जहां इतने त्याग

बलिदान हुए महापुरुषों द्वारा, सुखों का त्याग कर और समाज की ही चिंता करना और समाज के प्रति समर्पित हो जाना ऐसा उदाहरण भी हमें दीनदयाल उपाध्याय जी और नाना जी देशमुख में परिलक्षित होता है। अभी प्रारंभ के सत्रों में काफी कुछ चीजें विस्तार से आए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति वास्तव में एक ऐतिहासिक कदम है और 2020 में सर्वाधिक चर्चा होने वाला विषय रहा है। क्योंकि यह ऐसी शिक्षा नीति है जो वास्तव में भारतीय परिवेश की दृष्टि से भारत की जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है भारतीय जनमानस का चिंतन है उस को ध्यान में रखकर बनाई गई है अन्यथा इसके पूर्व जो भी नीतियां बनी हैं विशेष रूप से शिक्षा नीति व एक प्रकार से टेली फॉरवर्डिंग होती रही यह।

75वां अमृत महोत्सव चल रहा है और एक विचार आया, भारत 1947 में स्वाधीन हो गया लेकिन हमें स्वतंत्रता से अग्रसर होना है स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर लेकिन जो हमारे परिवेश में हमारे द्वारा हमारे लोगों के लिए बनाया गया तंत्र हो तब

हम स्वतंत्र कहलाएंगे। वह कितना प्रभावी हुआ है उसके चिंतन करने की बात है। जब स्वतंत्रता की बात करें तो वह सामाजिक क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र हो उदाहरण के लिए 1947 में हम स्वाधीन हो गए और उच्च शिक्षा व्यवस्था वही रही जो स्वतंत्रता के पूर्व थी तो यानी कहीं ना कहीं हम स्वाधीन हुए पर स्वतंत्र नहीं हुए। अब हमारे द्वारा बनाई गई हमारे लोगों के लिए बनाई हुई शिक्षा नीति है अब हम स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं।

एक चिंतक ने यह भी कहा कि यदि समाज में गलत भाषा बोली जाएगी तो गलत सुना जाएगा तो उसका पालन भी गलत होगा और जिस भाषा के कारण हमारी कृति गलत होगी तो उसका परिणाम भी गलत होगा। इसीलिए प्राथमिक भाषा मातृभाषा में शिक्षा होने चाहिए। मस्तिष्क में भाषा का विकास उसी उम्र तक हो पाता है

उसके पश्चात तो हम वातावरण से सीखते जाते हैं। इसमें मुझे एक संस्मरण ध्यान में आता है परम पूज्य सुदर्शन जी का वह भी हमारे भारतवर्ष के एक महान चिंतक और विचारक थे वह एक उदाहरण देते थे की मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा क्यों होना चाहिए थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मध्यप्रदेश में जो टास्क फोर्स बनी हुई है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावीकरण के बारे में कैसे पेपर होंगे मेजर, माइनर, ऑप्शनल, वोकेशनल ट्रेनिंग आदि कैसे होंगे वह सब दिखाई दे रहे हैं। वह सब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में रखा जाएगा लेकिन मेरी बात बहुत स्पष्ट है कहीं भी इसमें भय नहीं होना चाहिए।

अभी तक हम लोग जो पढ़ाते थे कि मेरिट इसकी बात कर रहे हैं एक फाउंडेशन कोर्स होता था जो अनिवार्य होता था और तीन ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे कल्पना करिए। फाउंडेशन कोर्स में तीन, ऑप्शनल

वे कहते थे मीरा जी का भजन मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई हम जैसे ही मीराबाई जी का नाम सुनते हैं तो उनके समर्पण उनके भक्ति भाव कृष्ण के प्रति उनका प्रेम ध्यान में आता है कि एक रानी भी समाज के लिए कैसे अपना कार्य करती हैं और जब वह गिरधर कहती हैं तो कृष्ण जी की गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए छवि ध्यान में आती है यदि हम इसी को mountain bearer कह देंगे तो वह छवि नहीं बनेगी अर्थ तो समझ जाएंगे पर कृष्ण जी का ध्यान नहीं आएगा। गोपाल कहने पर जो आकृति बनती है अन्य कुछ कहने पर अर्थ तो समझ में आएगा लेकिन उनकी छवि नहीं बनेगी वैसे ही टेंपल कहने पर मंदिर का भाव नहीं आएगा तो इस प्रकार से मातृभाषा जो बाल्यकाल में अत्यावश्यक है उसके पश्चात सभी विकल्प खुले हुए हैं। आप कुछ भी पढ़िए कैसे भी पढ़िए।

के तीन जिसके दो दो पेपर होते थे। अब उसको वर्तमान परिवेश के हिसाब से और आवश्यकता के हिसाब से अपनी डेमोक्रेसी को किस प्रकार कौशल से जोड़ सकते हैं कक्षा छठवीं के बाद सही मेक इन इंडिया के लाइन में आ सकते हैं उन चीजों को जोड़ते हुए और क्रेडिट सिस्टम दिया गया और मेजर में दो पेपर है माइनर में एक पेपर है कुल 3 पेपर हो गए। वोकेशनल ऑप्शनल इसमें 25 समूह बनाए गए हैं इसमें विस्तार से चर्चा होगी। वह अलग विषय है लेकिन यह भारत केंद्रित पाठ्यक्रम, भारत केंद्र विज्ञान की बात इसमें सम्मिलित है सनातन संस्कृति की बात भी सम्मिलित है, संस्कार पक्ष भी सम्मिलित है।

सोचिए भारत का ज्ञान विज्ञान परंपरा कितना समृद्ध था उसका यदि उसके प्रति यदि हमारा दुर्लक्ष्य नहीं होता तो हो सकता है अनेको वैज्ञानिकों की सूची में भारतवंशियों के नाम होते, भारत के ऋषि मुनियों के नाम होते, यदि हम उस दिशा में दुर्लक्ष नहीं होते मैक्स मूलर ने बहुत सारी चीजें यहां की ट्रांसलेट करके बाहर ले गए और वहीं कहीं ना कहीं शोध के बाद वैज्ञानिक और आविष्कारक हो गए। हम दो चीजें बताते हैं आप हिमाचल में जाइए, आप उत्तराखंड में जाइए आपने देखा होगा कि पहाड़ों का आइस मिनरल वाटर नीचे आता है और लोग उसको बोनेलाइज करके टरबाइन लगा देते हैं टरबाइन से वह क्या-क्या नहीं चलाते पवन चक्की, आटा चक्की, तेल चक्की, धान

की चक्की, पनबिजली और यह सब जमाने से चलाते आ रहे हैं लेकिन टरबाइन का आविष्कारक किसे कहा जाता है 1849 में जेंट्स गूगल में देखें। अब उसमें आविष्कारक जैसा क्या था जो हमारा समाज हमेशा से उपयोग करता आया है आप पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में जिस प्रकार चाहे बदल सके अब हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में हजारों सालों से ऐसा उपयोग होता है लेकिन वह वैज्ञानिक नहीं कहलाए हम कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन करने में पीछे रह गए।

कोई भी फल ऊपर से नीचे ही गिरता है न्यूटन से पहले भी गिरता था, न्यूटन के बाद भी गिरता है, जेम्स वाट के पहले भी भाप में ताकत होती थी, केटली का ढक्कन पहले भी उछलता था आज भी उछलता है लेकिन उसकी दृष्टि नहीं थी। जिस प्रकार भारत में तमाम ग्रंथों में यह सब चीजें लिखी हुई हैं उन्हें हम किस प्रकार से अपने पाठ्यक्रम में, ज्ञान के साथ जोड़ करके हम डॉक्यूमेंटेशन कर प्रमाण के साथ आगे ला सकते हैं।

अभी भी बहुत कुछ करने को बाकी है और सबसे बड़ी चीज कि हम डॉक्टर के साथ इंजीनियर एक अच्छा इंसान भी बना रहे हैं कि नहीं वह भी एक आवश्यक बात है यह भी विषय उद्घाटन सत्र में आया कि हम इसके साथ एक अच्छा व्यक्तित्व ही बनाना है कि डॉक्टर से चूक होगी तो एक इंसान की जान जाएगी, एक वकील से चूक होगी तो एक अपराधी सजा से मुक्त हो

जाएगा या निर अपराधी सजा पाएगा एक इंजीनियर से चूक होगी तो एक पुल गिर जाएगा और यदि शिक्षक से चूक होगी तो देश का भविष्य गिर जाएगा। तो इस प्रकार से शिक्षक कैसा होना चाहिए यह विषय भी आ चुका है इस बारे में एक मुझे छोटी सी घटना ध्यान में आ रही है।

एक गुरु थे और उनके चार शिष्य थे शिक्षा पूर्ण हुई दीक्षा का समय आया, तय हुआ कि कल दीक्षा का कार्यक्रम होगा पर आज कुछ कार्यक्रम कर लिया जाए। साथ में भोजन कर लिया जाए तो गुरु जी ने एक शिष्य को कहा कि जाकर पहाड़ से सूखी लकड़ियां ले आओ दूसरे को बुलाया तुम पानी ले आओ तीसरे को बुलाया तुम पत्ता ले आओ चौथे को बुलाया बोला कि तुम फूल ले आओ और चारों जंगल की तरफ चले जाते हैं। इसी बीच गुरुजी उसी मार्ग पर किसी पेड़ की ओट में छुप जाते हैं और छुपने से पहले उसी रास्ते पर खूब सारे कांटे बिखरे देते हैं अब शाम हुई और समय भी यह तय हुआ कि संध्या के पूर्व सभी को आ जाना है गुरुजी छुप जाते हैं संध्या हुई पहला शिष्य आया लकड़ियां लेकर के और देखा कि इस मार्ग में कांटे भी खड़े हुए हैं।

उसने कहा मुझे क्या पड़ी है मैं तो जवान हूँ छलांग लगा करके जा सकता हूँ और मुझे समय से पूर्व पहुँचना है वह कांटो से बच के निकल गया। दूसरा आया दूसरा भी यही सोच कर के और बच के निकल गया। तीसरे ने भी दाएं बाएं से निकलकर और पहुँच

गया। चौथा आया उसको लगा कि अरे रास्ते में कांटे बिखरे हुए हैं अब यहां से अभी कोई निकलेगा तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा तो उसने अपना सामान नीचे रखा सभी कांटे साफ किए और कांटे साफ करते करते उसको विलंब भी हो गया और जब वह पहुँचा तो देखा कि गुरु जी और अन्य तीनों शिष्य समय पर बैठे हुए थे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे।

गुरुजी ने उससे कहा कि तुम्हें विलंब कैसे हो गया तुमने गुरु आज्ञा की अवहेलना की। समय पर आने के लिए कहा गया था तो उसने बताया कि गुरुदेव मार्ग पर कांटे बिखरे हुए थे तो गुरु जी ने कहा उससे क्या फर्क पड़ता है तो शिष्य ने कहा नहीं गुरुदेव वह तो आम मार्ग भी है वहां बड़े बूढ़े भी निकलते हैं बच्चे भी निकलते हैं माताएं बहनें भी निकलती हैं रात में भी लोग यात्रा करते हैं अतः मैं उसे साफ करके आया हूँ गुरुजी ने कहा की अति उत्तम शाबाश।

तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई तुम अब घर की ओर प्रस्थान करोगे। कल यह तीनों अभी कुछ दिन और आश्रम में रुकेंगे तो इस प्रकार से ऐसी चीजों का भी समावेश हुआ है। हमारा समाज के प्रति धर्म संघ संस्कार पक्ष भी मजबूत हो।

नई शिक्षा नीति में हमें इस प्रकार की शिक्षा परिलक्षित हो रही है जो युग दृष्टा नानाजी देशमुख जी ने आज से अनेकों वर्षों पूर्व प्रारंभ कर दिया था और प्रारंभ इसी मार्ग पर किया था जो कि एक नया विचार

आधार जिसमें ना तो पूंजीवाद ना ही साम्यवाद दोनों को एकात्म मानववाद जिस का समावेश इसमें है।

एक छोटा सा उदाहरण जमशेदपुर में टाटा लेलैंड, टाटा सफारी गाड़ी भी बनती है खेती फावड़ा कुदाली भी बनती है और पूरे भारत में यदि उनकी कुदाली फावड़ा हम ना भी खरीदें तो उनका काम टाटा सफारी आदि गाड़ियों से चल जाएगा। लेकिन हम फावड़ा वहीं का खरीदेंगे या जो फुटपाथ पर लोहा पीटते हैं उनका खरीदेंगे तो उनका भी गुजर बसर होता रहेगा। इसीलिए कहा गया की स्वदेशी जो अपने आसपास अपने गांव अपने शहर में बना हुआ है। वही स्वदेशी उसको और थोड़ा सा काल सुसंगत बनाकर यही अपनी थ्योरी है और उन्हीं पर हमारा आश्रय अधिक से अधिक हो ताकि समाज का तारतम्य बना रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों की अधिक जवाबदारी है कि हमारे जो और विद्यार्थी हैं जो अंतिम वर्ष में हैं जो यहां से समाज जीवन में जाने वाले हैं एक माइंडसेट बनाने की आवश्यकता है कि पढ़ने के बाद हमको किधर जाना है, विदेश जाने की इच्छा पैदा कर देना, अच्छे से अच्छे ज्यादा से ज्यादा पैकेज के लिए मल्टीनेशनल कंपनी में जाना, फिर कॉरपोरेट्स, सरकारी परीक्षाओं की तैयारी।

इसके बाद जो बचते हैं फिर जो सोचते हैं कि क्या करना जब की पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को जोड़ दें तो यह रोजगार की संख्या 7 प्रतिशत से ज्यादा नहीं

है ज्यादा से ज्यादा 10 प्रतिशत मान लीजिए तब भी 90 परसेंट लोग पढ़ाई पूरी करने वाले हैं। उन्हें एमएसएमई की ओर अग्रसर करना चाहिए। जिससे व्यक्ति समष्टि की परिकल्पना साकार हो जाएगी। किस प्रकार हमें स्माल प्रोजेक्ट बनाना है बैंक गारंटी है करोड़ों के पैकेज हैं उनको कैसे जागरूकता उत्पन्न हो, नौकरी मांगने वाले नहीं नौकरी देने वाले बने।

शिक्षा और संस्कार युक्त शिक्षा। एक उदाहरण ध्यान में आता है कि एक बहुत योग्य शिक्षक थे और निशाना लगाना सिखाते थे। 2 विद्यार्थियों को बहुत अचूक निशाना लगाना सिखा दिया उसमें से एक विद्यार्थी भटक गया और क्राइम की दुनिया में चला गया और एक रक्षा सेवाओं में सेना में चला गया। अब दोनों का काम निशाना लगाना ही था, गोली चलाना ही था। जो सेना में गया उसने भी निशाना लगाया कहीं दुश्मनों को मार गिराया और उसको इनाम मिल गया और जो अपराध की दुनिया में चला गया था उसने भी निशाना लगाया उसने भी कुछ वही काम किया लेकिन इसको मृत्यु दंड मिल गया।

अब शिक्षक वही शिक्षा वही, शिक्षार्थी विद्यार्थी वही, काम वही, लेकिन एक को इनाम और एक को दंड। अंतर इतना कि एक के साथ ज्ञान था शिक्षा थी लेकिन दूसरे के साथ संस्कार युक्त शिक्षा और ज्ञान था इतनी बात कह कर मैं अपनी बात पूर्ण करूंगा। जय हिंद जय भारत।

# ABSTRACT – EVALUATION

## Towards a New Era of Vocational Education and Skill-building in India: The NEP-2020 Perspective

**B.R. KAMBOJ** (Vice-Chancellor)

CCS Haryana Agricultural University and

Guru Jambheshwar University of Science & Technology, Hisar, Haryana, India

As per the 12<sup>th</sup> Five-Year Plan (2012–2017), <5% of the Indian youth (19-24 yrs.) gets formal vocational education unlike other countries *viz.*, Germany (75%) and South Korea (96%). This emphasizes the need of reimagination of vocational education in India. Reimagination is also required to eliminate perception of vocational education being inferior to mainstream education. One of the primary reasons for the small numbers (<5%) is lack of proper implementation of vocational education programmes in the schools. NEP-2020 aims to overcome the social status hierarchy connected with vocational education by amalgamation of vocational education into mainstream education. The National Curriculum Framework (NCF) 2005 also aims to bridge the gap between academic and vocational streams. For its success, collaboration between secondary schools and ITIs, Polytechnics, Local Industry etc. is must. Skill labs would also be set up in the schools in a Hub and Spoke model for sharing this facility with other schools. Higher education institutions will also contribute to it in their own way.

It is expected that by 2025, at least 50% of students shall have vocational acquaintance. Every child is supposed to acquire practical know-how of at least one vocation and be exposed to many more.

There will be no demarcation among 'curricular', 'extracurricular', or 'co-curricular', among 'arts', 'humanities' and 'sciences' or between vocational or academic streams.

Universal access will be feasible to all children to quality holistic education - including vocational education with flexibility and choice of subjects. School students will have at least 10 bagless days in a year, during which they are to be exposed to a vocation of choice. The vocational courses may be short (embedded in the degree programmes) to long (independent degree or diploma courses) and embedded or independent.

**Adequate recruitment of teachers of vocational subjects as well as hiring a local eminent person or expert as a master instructor in various subjects to benefit students and help preserve and promote local knowledge(Lok Vidya) needs special emphasis.**

---

**KEY WORDS:** Vocational Education, Skill-building, NEP-2020, Reimagination, NCF, Holistic education, Recruitment, Lok Vidya

# Implementation of Right to National Education Policy in India: Issues and Concerns

DR. LAXMI DWIVEDI<sup>1</sup> and PROF. S. K. TRIPATHI

Department of Physical Sciences, Faculty of Science and Environment, Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya, Chitrakoot, Satna-485334, M.P., India

[laxmidwivedi73@gmail.com](mailto:laxmidwivedi73@gmail.com) [tripathi.shashikant@gmail.com](mailto:tripathi.shashikant@gmail.com)

**Abstract :** In the present age of globalization and technological developments, the paramount prerequisite for endurance in society is education as it plays pivotal role in the process of overall growth of human beings. Thus to strengthen the position of education in a more organized manner, the government of India took an essential initiative through the enactment of the 86th Constitution Amendment Act. This attempt aimed to achieve and facilitate the realization of free and compulsory education to children between the age of 6 and 14 years as a fundamental right. Despite the amendment, the present system is facing wide ranging problems, which in turn is hampering the spirit of enactment. The article analyzes and evaluates the initiative of Right to Education in India, with the compliance of the 86th Constitutional Amendment Act. The article finds that although this attempt has shown benefits, there are serious barriers and roadblocks in way to desired objectives of 86<sup>th</sup> Constitutional Amendment Act. These issues need to be addressed on an urgent basis to strengthen the scene of education at the grassroots level.

**Keywords:** Education, fundamental right, right to education, constitutional amendment.

## Indigenous Knowledge for Protection of Seed, Practices Utilized in Chitrakoot area

Navin Kumar<sup>1</sup> S.S Singh<sup>2</sup> Arjun Sharma<sup>3</sup>

Department of Genetics & Plant Breeding

Zila Parishad Krishi Mahavidyalaya Banda & Department of Crop Sciences

M.G.C.G.V Chitrakoot

Correspondence address: [navinkumarseedtechno@gmail.com](mailto:navinkumarseedtechno@gmail.com)

**Abstract:** The farmers of Chitrakoot have traditionally known about how to protect their seed from insect pests and how to conserve them. Chitrakoot area is referred to as rainfed region . Local seeds are more adaptive to drought and biotic stresses comparison to hybrids. In traditional system of agriculture, local seed material of traditional crop varieties play an important role for future needs is very paramount significance. By using indigenous plants material & other research articles are very useful, eco friendly & sustainable. In the present study, the investigators have surveyed the entire Chitrakoot for documenting the indigenous seed & grain protection practices of the farm households. The present investigation was undertaken with aim of objective to provide protection to the knowledge of local farmers and document it before it's lost. Another important objective was to pave the way for value addition in the indigenous knowledge by the scientists, researchers & development workers for sustainable development in the field of agriculture.

**Key word:** Indigenous knowledge, seed, conservation, pest.

# Constraints And Solutions In Implementing NEP

**ANJALI KUMARI**, Research Scholar

Department of Energy & Environment, Faculty of Science & Environment,  
Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya, Satna, M.P. 485334  
[anjalikdur@gmail.com](mailto:anjalikdur@gmail.com)

## Abstract :

National Education Policy (NEP) ensures inclusive and equitable quality education and promotes lifelong learning opportunities for all by the year 2030. Since India has ratified and subscribed to (Sustainable Development Goals) of the 2030 Agenda for Sustainable Development in 2015, the entire education system needs to re-engineered and tailored, if such a lofty goal has to be achieved.

The highest quality, equity and integrity required into the system must be actuated and realized by bridging the gap between the current architecture and infrastructure of education system in India and what is actually expected out of it. It may require efforts from early childhood care and education through higher education with equitable access to the highest- quality education for all learners regardless of their social or economic background. This National Education Policy 2020 is the first education policy of the 21st century and aims to address the long gap between the current state of education and the desired output. This Policy proposes the revision and revamping of all aspects of the education structure, including its regulation and governance in order to create a new system that is aligned with the aspirational goals of 21st century education, including SDG4 (Equitable and Quality Education), while building upon India's traditions and value systems.

During pre-independence era, the education system in India was under the complete control of the "Masters, the British Empire." The education policies, like the one drawn by Macaulay, as would be obvious, were not for providing any quality education to the Indians, but to churn out the "Babus;" clerks and bureaucrats, to serve the masters, pure and simple. Post independence, the society went through a series of changes, policies were charted and certain reforms were introduced, but the impact was still not achieved.

The NEP 2020 aims at making "India a global knowledge superpower".

The higher education and the means of implementation garners the major limelight of the policy. Due importance also has been accorded to other issues such as vocational education, research and online and digital education to mention a few. Overall, it is a commendable and a very positive step forward on the part of the government. It entirely depends upon the track of time which would actually judge the aggregate output achieved out of policy. Most of the substantive recommendations of the NEP for school education like the expansion of physical infrastructure, hiring of teaching and non-teaching staff, increasing resource allocation for schemes, and creation of funds for innovation and inclusions will have to be postponed to some indefinite future keeping the current infrastructure and scenarios in mind.

## Challenges in National Education Policy and Service Provision in India

ROSHANI PANDEY (Research Scholar) and Prof. S.K. Tripathi  
Department of Physical Sciences, Faculty of Science and Environment,  
Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya  
Vishwavidyalaya, Chitrakoot, Satna-485334, M.P., India  
roshanipandey1506@gmail.com tripathi.shashikant@gmail.com

### Abstract:

Despite government efforts to provide services for children with disabilities in line with recommendations from international aid agencies, the 2003 Census of Individuals with Disabilities found that over 90% remain unserved. This paper identifies some of the limitations of these efforts in the context of the census findings, with particular reference to the issues of under-representation of specific groups and identification. The 2003 Education For All (EFA) programme and recent policy initiatives, the Right to Education Bill 2005, the Action Plan for Inclusion in Education of Children and Youth with Disabilities (IECYD) 2005 and the National Policy for Persons with Disabilities 2006, are examined for their responsiveness to these concern.

# राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिपेक्ष में कृषि शिक्षा में नये आयामों की संकल्पना

डॉ. आर. एम. चौहान, कुलपति

सरदार कृषिनगर, दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, सरदार कृषिनगर -385506, जिला-बनासकांठा (गुजरात)

## प्रस्तावना :-

भारत देश में 1970 के दशक तक खाद्यान्न उत्पादन की अल्पता थी। जिसके निदान के लिये हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति तथा अन्य कृषि में हुये तकनीकी विकास के फल स्वरूप वर्तमान समय में भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ शुद्ध निर्यातक देश है। भारत की लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर हैं। वर्तमान स्थिति में कृषि क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद में 14.4 प्रतिशत का हिस्सा है, लेकिन पिछले 25 से 30 वर्षों में कृषि क्षेत्र का हिस्सा सकल घरेलू उत्पाद सतत घट रहा है। इस परिपेक्ष में भी कृषि क्षेत्र पर लोगों की निर्भरता में ज्यादा कमी नहीं आई है अपितु कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लगभग 80 प्रतिशत किसान सीमांत एवं छोटे किसान हैं।

इस स्थिति में कृषि क्षेत्र के द्वारा किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आह्वान पर राज्यों एवं केंद्र की सरकार के द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 'जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान' का आह्वान किया गया है।

एक राष्ट्र के रूप में भारतवर्ष की प्राथमिकता विकास के क्रम में परिवर्तनशील रही है। आजादी के तुरंत बाद देश में खाद्यान्न उत्पादन की विकट स्थिति थी इस समस्या को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में 1965 के समय में राष्ट्रीय योजनाओं में समायोजित किया गया था एवं इस स्थिति को समस्या मानते हुए समग्र भारत में 1965 के बाद भगीरथ प्रयास किए गए एवं इन प्रयासों के ही परिणाम स्वरूप देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई और इसी क्रम में देश में उन्नत बीजों पर अनुसंधान का कार्य समग्र देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नेतृत्व में विभिन्न संशोधन संस्थानों एवं कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा किये गये एवं इसके परिणाम स्वरूप भारत में उन्नत किस्मों के बीजों का उत्पादन हुआ एवं इसी क्रम

में रासायनिक खादों, कीटनाशकों एवं कृषि उपकरणों के प्रयोग से देश खाद्य उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भर बना बल्कि शुद्ध निर्यातक के रूप में विश्व पटल पर उभरा। आज भारत ना केवल खाद्यान्न बल्कि अन्य कृषि उत्पादों में भी विश्व में अग्रणीय स्थान है। और देश ने यह लक्ष्य सिर्फ चार दशक के समय में ही प्राप्त किया है। लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये अत्यधिक रासायनिक खादों, कीटनाशकों एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया है जिसके परिणाम स्वरूप आज देश को कृषि क्षेत्र में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि मृदा की गुणवत्ता, जलस्तर, खाद्य सुरक्षा, खाद्यान्न की गुणवत्ता एवं जैव विविधता में कमी हो रही है। इसके साथ-साथ जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। मूल रूप से इन विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक एवं तकनीकी जानकारी के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन जब तक मूल समस्या को हल करने के लिए उसके उद्गम स्तर पर ही समस्या के समाधान के प्रयास नहीं किया जाये, तब तक समस्या के समाधान के प्रयास अपनी पूर्णता को सिद्ध नहीं कर सकते।

इसके लिए प्राकृतिक खेती एक अत्यंत आवश्यक युक्ति है जो कि समस्या के मूल स्वरूप पर कार्य करती है। कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को अपनाने से खेती-किसानों से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जो अन्य कृषि पद्धतियों की तरह वैज्ञानिक तरीके से करने की एक विधा है। इस पद्धति को खेतों पर पूर्ण रूप से आत्मसात करने के लिए इसका पूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन की आवश्यकता है। जब तक प्राकृतिक खेती को पूर्ण वैज्ञानिक तरीके से नहीं अपनाया जाता तब तक प्राकृतिक खेती की पद्धति से उचित परिणाम प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं।

### **राष्ट्रीय शिक्षा नीति : 2020 की संरचना एवं कार्यनीति :-**

आजादी के बाद देश की प्राथमिकताओं एवं समस्याओं के अनुरूप शिक्षण क्षेत्र में विविध नीतिगत सुधार हुए हैं। इसी क्रम में वर्ष 2020 में शिक्षण क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति को 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति: 2020' के रूप में चरितार्थ किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के द्वारा वर्तमान 'इंडिया' की संकल्पना को 'भारत' के रूप में स्थापित करना है इसके द्वारा सभी भारतवासियों का समतामूलक एवं न्याय संगत समाज निर्माण की परिकल्पना को शिक्षा के द्वारा स्थापित करना है। साथ ही साथ सभी को गुणवत्तापूर्ण एवं विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए जरूरी व्यवस्थाओं का विकास करना भी है। मूल रूप से नई शिक्षा नीति देश के जनमानस में उनके मौलिक कर्तव्य एवं संवैधानिक मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था को सुदृढ़ करने की

है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही रूप में देश में लागू करने के लिए इस नीति को संकल्पित किया गया है। प्राथमिक स्तर पर विद्यालय शिक्षा है और विद्यालय शिक्षा को मुख्य रूप से चार भागों में विभाजित किया गया है। इस क्रम में बुनियादी शिक्षा (कक्षा 1 से 2), प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 3 से 5), पूर्व माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 6 से 8), एवं माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 9 से 12), व्यवस्था को 5 +3+3+4 शिक्षण व्यवस्था के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाहित किया गया है।

उच्च शिक्षा को नए आयाम प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अनेकों प्रावधान किए गए हैं। 21वीं सदी के अनुरूप उच्च शिक्षा में नए आयामों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छात्रों को अधिक से अधिक विभिन्न विषयों को पढ़ाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस नीति का उद्देश्य न केवल शिक्षा प्रदान करना है बल्कि कौशल विकास करना भी है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का कार्य भी करती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शैक्षणिक डिग्री की संरचना एवं समयकाल को वर्तमान समय की जरूरत के अनुरूप रखा गया है।

स्नातक डिग्री कार्यक्रम का समय 3 अथवा 4 वर्ष का रखा गया है। साथ ही अध्ययन पूर्ण करने के लिए अलग-अलग विकल्प दिए गए हैं। जिससे छात्र अपनी रुचि के अनुसार 1 वर्ष का अभ्यास पूर्ण करने के बाद सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। और यदि कोई छात्र 2 वर्ष का कोर्स पूर्ण करता है तो उसे डिप्लोमा दिया जा सकता है तथा 3 वर्ष का अभ्यास पूर्ण करने पर डिग्री प्रदान करने का प्रावधान है। इसी नीति के अंतर्गत 4 वर्ष तक बहुआयामी विषयों का अभ्यास करने पर बहुआयामी स्नातक डिग्री देने की व्यवस्था है। यदि 4 वर्ष के अभ्यास में छात्र अनुसंधान करता है तो 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम के आधार पर छात्र को बहुआयामी स्नातक डिग्री (अनुसंधान) देने का भी प्रावधान है। देश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप परिवर्तित करने से उच्च शिक्षा अधिक व्यवहारिक एवं रोजगारोन्मुखी होगी।

### **राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिक्षेय में कृषि शिक्षण का वर्तमान स्वरूप :-**

कृषि क्षेत्र से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए कृषि शिक्षण की एक महत्वपूर्ण भूमिका है कृषि शिक्षण का कृषि क्षेत्र के टीकाऊपन, विविधता एवं पूर्ण क्षमता को उपयोग में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका है कृषि शिक्षण 'भूमि अनुदान' व्यवस्था पर आधारित होने से कृषि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कुशल मानव संसाधन के रूप में छात्रों को प्रशिक्षित करना है। वर्तमान कृषि शिक्षा का शिक्षण अमेरिका की शिक्षण व्यवस्था पर आधारित है जो कृषि शिक्षण में छात्रों को विविध

प्रकार के कृषि विषयों के ज्ञान के साथ साथ प्रायोगिक शिक्षा का ज्ञान भी प्रदान करने का कार्य करती है।

देश में कृषि शिक्षण की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये देश में विभिन्न कृषि महाविद्यालयों के डीनस की कमेटी के द्वारा कृषि संकायों में संचालित कृषि विषयों के पाठ्यक्रमों में समय-समय पर सुधार एवं सुझाव दिये जाते हैं। इसी के अनुरूप कृषि महाविद्यालयों में पाठ्यक्रमों का अभ्यास कराया जाता है।

कृषि शिक्षण को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संकल्पना के अनुरूप बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार नवीनतम विषयों एवं संरचना को कृषि शिक्षण में समाहित करने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कृषि शिक्षण विभाग द्वारा छठवीं डीनस कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी कृषि एवं संलग्न विषयों के पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप नवीन कृषि पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में सुझाव एवं जरूरी बदलाव के लिये सिफारिश करेगी तदनुसार देश के सभी कृषि महाविद्यालय नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार कृषि शिक्षण में इसकी अनुपालना करेंगे।

कृषि संकायों से उत्तीर्ण स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्र कृषि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण मानव संसाधन के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इस परिपेक्ष में छात्रों को प्राकृतिक कृषि वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कराने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के द्वारा प्राकृतिक खेती को एक पाठ्यक्रम के रूप में कृषि संकायों में समाहित करने की अनुशंसा की गई है। छठवीं डीनस कमेटी के द्वारा प्राकृतिक खेती को स्नातक स्तर पर अध्यापन कराने के लिए पाठ्यक्रम बनाने के संबंध में सुझाव दिए जाएंगे एवं इस अनुरूप कृषि पाठ्यक्रमों में प्राकृतिक खेती के कृषि स्नातक शिक्षण में समाहित किया जाएगा।

## **राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझावों को वर्तमान कृषि शिक्षण में समाहित करने के रोडमैप:-**

भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस क्षेत्र में व्यवसाय एवं रोजगार की अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। इसलिये प्रारंभिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षण पाठ्यक्रमों में कृषि विषय के अध्यापन की आवश्यकता है। इस दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 5+3+3+4 की संरचना के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक स्तर तक कृषि विषयों का अध्यापन कराने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

- प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर छात्रों को कृषि से संबंधित जल, मृदा, उर्वरक, फसलों, वनस्पतियों, दुधारू पशुओं एवं किचन गार्डनिंग जैसे व्यावहारिक विषयों की प्रारंभिक

जानकारी को अधिक से अधिक प्रायोगिक रूप में जीवन में उपयोगिता एवं व्यावहारिकता के रूप में अभ्यास कराने की आवश्यकता है।

- माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्रों को निम्नानुसार विषयों का शिक्षण कराने की आवश्यकता है।
  - ❖ मृदा के भौतिक गुणों, वर्गीकरण एवं संरक्षण
  - ❖ कृषि के उपयोग में आने वाले यंत्र एवं अभियंत्रों का उपयोग
  - ❖ बीजों की बुवाई करने की पद्धतियां
  - ❖ रासायनिक एवं जैविक उर्वरकों का उपयोग
  - ❖ अनाजों, दालों, तिलहनों, मसालों, नगदी फसलों की खेती के सम्बन्ध में प्रारंभिक जानकारी
  - ❖ सूखी खेती
  - ❖ सिंचाई के विभिन्न साधनों एवं पद्धतियों का उपयोग
  - ❖ जल संरक्षण
  - ❖ जैविक एवं प्राकृतिक खेती
  - ❖ बागवानी एवं औषधीय फसलों की खेती का प्रारंभिक ज्ञान
  - ❖ ग्रीनहाउस एवं पॉलीहाउस प्रारंभिक ज्ञान
  - ❖ कृषि अर्थशास्त्र एवं कृषि विस्तार शिक्षा का प्रारंभिक ज्ञान
  - ❖ कृषि क्षेत्र में उद्योगों एवं रोजगारों के अवसर

### **कृषि शिक्षण में प्राकृतिक खेती के अध्ययन के लिये पाठ्यक्रम के संबंध में सुझाव:-**

कृषि में उच्च शिक्षण में प्राकृतिक खेती की उपयोगिता का वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक रूप से अपनाने के लिए निम्न विषयों की जानकारी छात्रों को स्नातक स्तर पर देने की आवश्यकता है।

- प्राकृतिक खेती के मूल्य, महत्व एवं उपयोगिता
- प्राकृतिक खेती का परिस्थिति तंत्र एवं उसकी संकल्पना
- प्राकृतिक खेती करने की विविध पद्धतियों का अलग-अलग कृषि जलवायु क्षेत्र में उपयोग
- भूमि को विश्राम देना, बिना जुताई की खेती एवं मृदा संस्कार
- प्राकृतिक खेती में मृदा द्वारा फसलों का पोषण

- प्राकृतिक खेती में पोषक तत्वों की उपलब्धता
- हरी खाद, सूक्ष्म जीवों का उपयोग एवं जैविक खाद
- बीजामृत एवं जीवामृत
- जल संरक्षण की तकनीकें
- प्राकृतिक खेती में कीटों, परजीवियों, रोगों एवं खरपतवारों का प्रबंधन
- बीज संस्कार, कंपोस्टिंग, मल्विंग (पुआल, भूसा, सूखी घास, पत्तियां एवं फसल अवशेष)
- प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने वाली केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाएं
- प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाली विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों एवं सामाजिक संस्थानों के द्वारा किए गए प्राकृतिक खेती से सम्बंधित प्रयासों का अध्ययन
- प्राकृतिक खेती से उत्पादित खाद्य पदार्थों का विपणन एवं निर्यात

### सारांश :-

गत 100 वर्ष के आधुनिक कृषि के कालखंड में कृषि के प्रति हमारे दृष्टिकोण में बदलाव आया है। इस से हमारी कृषि आज चिंताजनक स्थिति में पहुँची है। अभी उचित समय है कि हम भारतीय कृषि चिंतन को एवं प्राकृतिक खेती की संकल्पना को यथोचित रूप से पुर्नस्थापित करें। केवल कृषक ही नहीं, सभी भारतवासियों की भागीदारी से यह जन अभियान सफल होगा।

# Agricultural Education and National Education Policy 2020

**Dr. Narendra Singh Rathore**, Vice Chancellor

Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur, Rajasthan

## Introduction

National Education Policy was approved by the **Union Cabinet of India** on 29 July 2020, which outlines the vision of India's new education system. The new policy replaces the previous **National Policy on Education, 1986**. It means Government of India has launched New National Education Policy after 34 Years. The policy is a comprehensive framework for elementary education to higher education as well as vocational training in both rural and urban India. The policy aims to transform India's education system by 2040.

## Salient Features of NEP 2020

The main aim of this policy is to federate Students into business group and make them job provider rather than job seeker. The policy's vision includes the following 20 key changes to the current system:

1. Creation of multidisciplinary universities and colleges in their educational offerings: Each university or College can start any course as per their available infrastructural facilities.
2. Multidisciplinary undergraduate education locally engaged and globally networked: A provision will be made at undergraduate level to have more flexibility or choices of subjects. Student-centric with a flexible curriculum tightly integrated with out- of- class learning.
3. Faculty and institutional autonomy: It is up to each institute to grow their field according to required infrastructure and governance required.
4. Revamping curriculum, pedagogy, assessment and student support for enhanced student experiences having innovation and entrepreneurship as major driver.
5. Merit appointments of faculty and career progression. Mitigating faculty shortage and increasing competency through reshaping HRM and HRD components.

There is a need of change in the recruitment policies in Universities (Tenure track system).

6. Promoting higher quality research: Establishment of a National Research Foundation to fund outstanding peer-reviewed research and to actively seed

research in universities and colleges.

Research in Agricultural Universities will have to focus on research on FAITH and (1) Frontier areas of research (2) Greater Academic- industry linkages (3) Innovation by setting up start-up Incubation centres (4) Technology development centres and (5) Humanities and Social Sciences Interdisciplinary research.

Emphasis should be given on research and its social relevance on local problems. For this, dual programs should be taken up with foreign institutes (Respond, Reset and Rebound concept for converting research output into business outcome).

Academia-industry interaction in our education system is very weak & therefore now through new education policy, there is a need of greater emphasis on industry based vocational & specialized courses like in USA and Canada. Hub for industrial R&D with corporate engaging academia on a collaborative relationship model rather than on a transactional model.

7. Governance of HEIs by high qualified independent boards having academic and administrative autonomy; strengthening governances and leadership.
8. “Light but tight” regulation by a single regulator for higher education.
9. Increased access, equity, & inclusion, expected to have fund flow to the extent of 6 % of GDP. Research & Innovation investment in India is 0.69 % of GDP, where as in China (2.1%), USA (2.8%), Israel (4.3%), South Korea (4.2%). In the policy, it is proposed to increase it by 6 % for bringing excellence in research field.

It is proposed to setup National Research Foundation (NRF) in Ministry of Education, Govt of India. Agricultural Universities will have to gear up for competitive funding based on peer reviewed proposals and linkages.

10. Common entrance exam (CEE) for admission to higher education through National Testing Agency (NTA). The National Testing Agency will now be given the additional responsibility of conducting entrance examinations for admissions to universities across the country, in addition to the JEE Main and NEET.
11. No separate Governing bodies for higher education: everything will be in umbrella of HECI, higher education commissions of India. A Higher Education Council of India (HECI) will be set up to regulate higher education. The council’s goal will be to increase gross enrolment ratio.

The HECI will have 4 verticals, responsible for Regulations, Accreditation, Funding and Standard setting:

- National Higher Education Regulatory Council (NHERC), (a common, single point regulator for the higher education sector) to regulate higher education, including teacher education, while excluding medical and legal education.
- National Accreditation Council (NAC), a “meta-accrediting body”. The Agricultural Universities will have to prepare for undergoing accreditation procedure prescribed by the new accreditation body, the National Accreditation Council in place of present accreditation and ranking system of ICAR
- Higher Education Grants Council (HEGC), for funding and financing of universities and colleges. This will replace the existing National Council for Teacher Education, All India Council for Technical Education and the University Grants Commission.
- General Education Council (GEC), to frame “graduate attributes”, namely to frame expected learning outcomes for higher education. It will also be responsible in framing a National Higher Education Qualification Framework (NHEQF). The National Council for Teacher Education will come under the GEC, as a Professional Standard Setting Body (PSSB).

Other PSSBs will include professional councils such as Veterinary Council of India, Council of Architecture, Indian Council of Agricultural Research and National Council for Vocational Education and Training.

12. Rationalized institutional architecture: Research intensive university, Teaching intensive university and Autonomous degree granting colleges.
13. Diminishing compartmentalization between disciplines (no rigid separation), students can select subjects of their liking across the streams.
14. Multiple entry and exit and establishment of Academic Bank of Credits (ABC).
15. Promotes Digital learning in teaching learning process and assessment procedure (National Educational Technology Forum). Practical aspects of agriculture in value chain should be integrated in the vocational courses. New areas like artificial intelligence, block chain technology, smart agriculture should be thought of in designing of new curriculum at different levels in education system. The slogan of agriculture study should be “Job provider not the job seeker” and it should be made practical.

SWAYAM “Study Webs of Active-Learning for Young Aspiring Minds” is an Indian Massive open online course has been launched & integration technology in education has to go in big for development. We should emphasize on learn to click, how, when &

where for knowledge, information & innovations to make each University a global University.

Agricultural Universities should also contribute in SWAYAM portal. Up to 40% of online credit can be done on SWAYAM portal. Reading material/audio/video should be given in advance to students.

Already MOOC (Massive Open Online Courses), PROCOOL (Promoting Cooperative Learning System) Learning (any time, any one and any where concept) is already available in agriculture field.

16. Multidisciplinary Education and Research Universities (MERUS) setting at par with IIT and IIMs. There is need to set up Indian Institute of Agriculture on pattern of IITs and IIMs etc to check brain drain.

17. Performance Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development (PARAKH): It is a National Assessment centre for assessing students.

18. Teacher Student Ratio: It shall range from 1:10 to 1:20 depending on the program.

19. Promotion of Indian Arts and Culture.

- ❖ Under NEP 2020, numerous new educational institutes, bodies and concepts have been given legislative permission to be formed. These include:
- ❖ National Education Commission, headed by the Prime Minister of India
- ❖ Academic Bank of Credit, a digital storage of credits earned to help resume education by utilizing credits for further education
- ❖ National Research Foundation, to improve research and innovation
- ❖ Special Education Zones, to focus on the education of under represented group in disadvantaged regions
- ❖ Gender Inclusion Fund, for assisting the nation in the education of female and transgender children
- ❖ National Educational Technology Forum, a platform to facilitate exchange of ideas on technology usage to improve learning

20. The policy proposes to internationalize education in India. Foreign universities can now set up campuses in India. The fees of both private and public universities will be fixed.

For quality assurance AU should move for national and international ranking.

Internationalization of Agricultural education through call for international community for coming in India and stressing more on unique courses like Community Science, AIT, REE, ABM and Food Nutrients and Dietetics etc. Motivating, attracting and retaining foreign students in some of unique courses should be priority in order to initiate internationalization of agriculture education. Internationalization describes designing our courses in a way that it may be readily consumed across multiple countries. This process should be strengthened by our AU's looking to expand their global footprint beyond their own domestic sectors understanding stakeholders abroad may have different requirement and prospectus.

### **New Setup Proposed for Higher Education**

It proposes a 4-year multi-disciplinary bachelor's degree in an undergraduate program with multiple exit options. These will include professional and vocational areas and will be implemented as follows:

- ❖ A certificate after completing 1 year of study
- ❖ A diploma after completing 2 years of study
- ❖ A Bachelor's degree after completion of a 3-year programme
- ❖ A 4-year multidisciplinary Bachelor's degree (the preferred option)

Designing course for certificate, diploma, degree and degree plus research based on tradition, technology, talent and trading incorporating knowledge (what to do), skill (how to do), ability (how to simplify and conveniently mould up) and efficiency (how to reduce losses and enhance efficiency) is needed in present context. Professional Standard Setting Body (PSSB) will have to take it on priority and initiate this task.

Introducing trimester system (12 weeks/ 3 months each semester) instead of semester system (16-18 weeks per semester) viewing to introduction of professionalism at different stage of entry and exit.

Introduction of 10: 90 course of theory: practical for certificate course, 20: 80 course of theory: practical for diploma course, 30: 70 course of theory: practical for degree course and 40: 60 course of theory: practical for degree plus research aptitude proficiency course.

Agriculture at UG level has 11 different disciplines plus 3 more are in pipe lines. There are total 125 sub subject of skilling and entrepreneurship development in different sector of Agriculture for livelihood options.

First year certificate should be based on Ist Semester 4 credits theory plus 10 credits

practical, second semester 14 credits Hands on Training (HOT) training and finally third semester 14 credits of either options of Curricular Practical Training (CPT) or Optional Practical Training (OPT).

Second year diploma should be based on Ist Semester 8 credits theory plus 6 credits practical, second semester 14 credits RAWE and finally third semester 14 credits of either options of Curricular Practical Training (CPT) or Optional Practical Training (OPT).

Third year degree should be based on Ist Semester 14 credits total theory, second semester 14 credits experiential learning and finally third semester 14 credits of Implant training/ HOT training.

Fourth year degree plus research should be based on Ist Semester 14 credits total theory, second semester 4 credits theory plus 10 credits practical and finally third semester 14 credits of Student Research Project.

Masters of Philosophy (MPhil) courses are to be discontinued to align degree education with how it is in Western models.

# राष्ट्ररूषि नानाजी देशमुख की परिकल्पना एवं नई शिक्षा नीति में समानता तथा समयानुकूलता: ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ में।

\* डॉ. सन्तोष कुमार अरसिया, सहायक प्राध्यापक, म.गॉ.चि. ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना, म.प्र.

\*\* डॉ. अबधेश प्रसाद पटेल, सहायक प्राध्यापक, म.गॉ.चि. ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना, म.प्र.

\*\*\* डॉ. पुरुषोत्तम सिंह, सी.एम.सी.एल.डी.पी. म.गॉ.चि. ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना, म.प्र.

## सारांश

आज से नहीं, अपितु प्राचीनकाल से ही भारतीय शिक्षण पद्धति का ग्रामीण एवं शहरी विकास में वैश्विक स्तर पर अद्वितीय योगदान रहा है। शिक्षा पद्धति, इन्टरनेट के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण, अत्यधिक तीव्र गति से परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। कोविड 19 महामारी के बढ़ते प्रभाव के बावजूद भी, समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत भी बहुआयामी शिक्षा पद्धति में नित नये आयामों को शैक्षणिक गतिविधियों में समाहित कर रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है जो समीचीन है। किसी भी राष्ट्र का सर्वोपरि विकास तभी सम्भव होगा जबकि वहाँ शिक्षा पद्धति वैश्विक मानकों के अनुरूप हों। नई शिक्षा नीति उच्चशिक्षा में छात्रों के मध्य तर्कसंगतता, नव-विचार, बुद्धि-विकास, व्यवहार, कौशल एवं मूल्यों का विकास करने में सक्रिय सहभागिता प्रदान करने में सक्षम होगी।

**शब्द कुंजी-**नई शिक्षा नीति 2020, ग्रामीण विकास, नानाजी देशमुख, उच्च शिक्षा और कोविड 19

## प्रस्तावना-

स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति, 34 वर्षों के अन्तराल के बाद 21वीं सदी में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020, 29 जुलाई 2020 को लम्बे समय से शिक्षाविदों और वर्तमान में बेरोजगारी की समस्या को दृष्टिगत रखते हुये नई शिक्षा नीति लागू किया जो युगानुकूल एवं समसमायिकी है। उचित बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है।

एक श्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए उच्च शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति स्वयं, परिवार, समाज और देश का विकास करता है। नानाजी की शिक्षा क्षेत्र की परिकल्पना एवं नई शिक्षा नीति के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि

## “नई शिक्षा नीति करेगी नवयुग का निर्माण, आने वाला समय देगा इसका प्रमाण”

वर्तमान शिक्षा नीति शिक्षा में सुधार, नवाचार व नवीन शिक्षण पद्धति ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर विशेष बल प्रदान करेगी। महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय राष्ट्रऋषि नानाजी देशमुख की ग्रामोदय परिकल्पना जीवन्त स्वरूप है इस विश्वविद्यालय का बोध वाक्य **विश्वम् ग्रामे प्रतिष्ठितम्** अर्थात् ग्राम विश्व का लघुरूप है इस विश्वविद्यालय का ध्येय कौशल एवं उद्यमिता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास करना है। जो कि नयी शिक्षा की अवधारणा के अनुरूप है।

### शिक्षा क्या है?

शिक्षा का शाब्दिक अर्थ सीखने एवं सिखाने से है। पूर्व में संचालित शिक्षा नीति सीखने एवं सिखाने की प्रविधि की कमी के इतर छात्रों में विषय वस्तुओं को रटने एवं डिग्री प्राप्त कर नौकरी प्राप्त करने को प्रोत्साहित किया गया।

वर्तमान नई शिक्षा में कौशल तथा उद्यमशीलता की प्रमुखता परिलक्षित होती है। यह नीति शिक्षा के शब्दिक अर्थ को सार्थक करते हुए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

### नई शिक्षा नीति की आवश्यकता-

कहीं न कहीं हमारी पूर्व प्रचलित शिक्षण पद्धति शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण करने में सक्षम नहीं रही क्योंकि उसके द्वारा विद्यार्थियों का आकलन उनके द्वारा अर्जित अंको के आधार पर किया जाता था जो मैकाले शिक्षण पद्धति पर आधारित था।

नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के अलावा व्यावहारिक ज्ञान को भी समझने व सीखने पर निहित तथा वह अपनी रुचि अनुसार विषयों पाठ्यक्रमों तथा भाषा का अध्ययन कर सकता है।

इस तरह सीखने वाले अपने लक्ष्य और अपनी क्षमताओं के अनुसार सक्षम होंगे। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति को लागू करने की आवश्यकता महसूस की गई।

नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। इस योजना के माध्यम से महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर के नीतिगत बदलाव को

लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। जिनको नयी शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पूरा किया जाना है। इन कार्यों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सब्जेक्ट ऑप्शन, रीजनल लैंग्वेज बेस्ड एजुकेशन, यूनिवर्सिटी डिग्री में प्रवेश एवं निकासी की सुविधा, क्रेडिट बैंक सिस्टम मल्टीपल इन्ट्री एण्ड एगिजट आदि शामिल है। इसमें एक इंप्लीमेंटेशन एंड रिव्यू कमेटी का गठन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत किया जा गया। इसको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाएगा। इस कमेटी के माध्यम से इस पॉलिसी की सफलता का मूल्यांकन किया जायेगा। इसके अलावा क्रेडिट बैंक प्रणाली एवं आईआईटी को बहु विषयक संस्थान में परिवर्तित करने के लिए एक और टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। यदि इस योजना के कार्यान्वयन में विलंब किया जाएगा तो संबंधित राज्य एवं जिला स्तर के अधिकारियों को जवाब देना होगा।

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एनसीसी को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूजीसी एवं एनआईसीटी द्वारा एनसीसी को विश्वविद्यालयों में एक वैकल्पिक विषय के रूप में चुनाव किए जाने का निर्णय लिया गया है। एनसीसी के माध्यम से देश के विद्यार्थी अनुशासित एवं देश भक्ति की भावना का विकास किया जायेगा। एनसीसी के लिए एक सामान्य वैकल्पिक क्रेडिट पाठ्यक्रम होता है। जिसकी जानकारी एन.सी.सी. निदेशालय के कमांडिंग अफसर द्वारा सभी विश्वविद्यालयों तथा टेक्निकल संस्थानों के कुलपतियों को प्रदान की गई है। इस पाठ्यक्रम के बारे में भी कमांडिंग अफसर द्वारा विस्तृत जानकारी प्रोजेक्शन एवं ब्रीफिंग के द्वारा प्रदान की गई है।

- ❖ इस शिक्षा नीति को एक समावेशी, भागीदारी और समग्र विकास के दृष्टिकोण को अपनाते हुए परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया गया है।
- ❖ जिसमें विशेषज्ञों की राय, क्षेत्र के अनुभव, अनुसंधान, हितधारक प्रतिक्रिया आदि को ध्यान में रखा गया है।
- ❖ इस नीति को 22 भाषाओं में प्रकाशित किया गया है।

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए छात्रों एवं शिक्षकों का समग्र विकास (सार्थक) योजना देश में बेरोजगारी में कमी लाने तथा देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी।

नई पीढ़ी के छात्रों को अधिक शिक्षा सक्षमता प्रदान के लिए 2 दशकों के लिए बनाया गया है। इस शिक्षा नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

## नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 का उद्देश्य

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रदान की जाने वाली शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लाना है। जिससे कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो और बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें।

## एजुकेशन पॉलिसी के सिद्धांत

- ❖ विद्यार्थियों की क्षमता की पहचान एवं क्षमता का विकास करना तथा उसके अनुसार शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना।
- ❖ साक्षरता एवं संख्यामकता के ज्ञान को बच्चों के अंतर्गत विकसित करना।
- ❖ शिक्षा को लचीला बनाना।
- ❖ एक सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में निवेश करना।
- ❖ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विकसित करना।
- ❖ बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना एवं राष्ट्रभक्ति की भावना का विकास करना।
- ❖ उत्कृष्ट स्तर पर शोध कार्यों को बढ़ावा देना।
- ❖ बच्चों को सुशासन सिखाना एवं सशक्तिकरण करना एवं अपनी कौशल अनुरूप शिक्षा ग्रहण करना।
- ❖ शिक्षा नीति को पारदर्शी बनाना तथा समय-समय पर यथासम्भव मूल्यांकित करना।
- ❖ तकनीकी यथासंभव उपयोग पर बढ़ावा देना।
- ❖ विद्यार्थियों का समग्र मूल्यांकन पर जोर देना।
- ❖ विभिन्न प्रकार की भाषाएं सिखाना
- ❖ बच्चों की सोच को रचनात्मक एवं तार्किक करना।

नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का ग्राउंड वर्क आरंभ हो गया है और इसे एकेडमिक ईयर 2021-22 में विकसित किया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत कुछ विवरण भी दिया गया है जो कि कुछ इस प्रकार है:-

- ❖ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को भी महत्व दिया जा रहा है। इसके लिए एक इनिशिएटिव लांच किया गया है जिसका नाम मनुदर्पण है। इस इनिशिएटिव के माध्यम से छात्रों को परामर्श तथा भावनात्मक सहायता प्रदान की जा रही है। इसी मनुदर्पण इनिशिएटिव के अंतर्गत नेशनल टोल फ्री नंबर ऑनलाइन चैट नेशनल लेवल डायरेक्टरी एंड डाटाबेस ऑफ काउंसिल्लर्स विकसित किया जा रही है।

## पर्सनल एजुकेशन पॉलिसी शिक्षक प्रशिक्षण

- ❖ नई शिक्षा नीति भारत के विद्यार्थियों को ग्लोबल सिटीजन बनाएगी और इसी के साथ यह नई शिक्षा नीति उन्हें अपनी सभ्यता से भी जोड़े रखेगी।
- ❖ इस नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से छात्रों को अपने पेशन को फॉलो करने का एक अवसर प्रदान किया जाएगा।
- ❖ छात्रों को अपनी इंटरेस्ट, एबिलिटी और डिमांड की मैपिंग करनी चाहिए।
- ❖ छात्रों को क्रिटिकल थिंकिंग को डिवेलप करने की आवश्यकता है।
- ❖ हम ऐसे युग में प्रवेश करने जा रहे हैं एक इंसान कोई एक प्रोफेशन अपनी पूरी जिंदगी फॉलो नहीं करेगा तो यह नई शिक्षा नीति इस बात को ध्यान में रखते हुए भी आरंभ की गई है।
- ❖ एजुकेशन पॉलिसी व्हाट यू थिंक पर फोकस करती थी लेकिन यह नई शिक्षा नीति अब हाउ टो थिंक पर फोकस करेगी।
- ❖ इस नई एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा। टीचर्स ट्रेनिंग पर भी खास ध्यान देने की बात की है।

## आईआईटी बहु विषयक संस्थान

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आईआईटी जैसे इंजीनियरिंग संस्थानों को मानविकी छात्रों के लिए दरवाजे खुलेंगे। आईआईटी बहु विषयक शिक्षा की ओर आगे बढ़ेगा।

## नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना

नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करी जाएगी। जिसके माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाया जाएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना से शोधकर्ताओं को बढ़ावा दिया जाएगा। जिससे नई नई रिसर्च सामने आएंगी जो देश की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगी।

## नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पाठ्यक्रम

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत पाठ्यक्रम को भी कम किया गया है। केवल इतना ही पाठ्यक्रम रखा जाएगा जो अनिवार्य है। इसी के साथ क्रिटिकल थिंकिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत टेक्नोलॉजी के माध्यम से जैसे कि टीवी चैनल, ऑनलाइन बुक, एप आदि से भी पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाएगा।

## नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उच्चतर शिक्षा के कुछ घटक, गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देश के विकास के लिए एवं बेरोजगारी दर को घटाने के लिए उच्चतर शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उच्चतर शिक्षा विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रदान की जाती है। ऐसे में विश्वविद्यालयों की शिक्षा में सुधार करने के लिए एवं शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण बढ़ाने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाएंगे। जिससे कि देश के युवा सक्षम बन सकें एवं उनका समग्र विकास हो सके। इस योजना के माध्यम से ऐसी उच्चतर शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाएगी जिसमें बहु विषयक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय होंगे।

### संस्थागत पुनर्गठन और समेकन

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बड़े एवं बहु विषयक विश्वविद्यालय, कॉलेज आदि में स्थानांतरित करना है। जिससे कि उच्च शिक्षा की विखंडता को समाप्त किया जा सके। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान का लक्ष्य लगभग 3000 या फिर उससे अधिक छात्रों का उत्थान करना होगा। इन संस्थानों के माध्यम से छात्रों का सामाजिक एवं मानसिक विकास किया जाएगा।

इस पॉलिसी के माध्यम से सार्वजनिक एवं निजी दोनों संस्थानों का विकास किया जाएगा। यह विकास करने के लिए एक निष्पक्ष प्रणाली का उपयोग किया जाएगा।

### समग्र एवं बहु विषयक शिक्षा

समग्र एवं बहु विषयक शिक्षा का तात्पर्य है मनुष्य की सभी क्षमता जैसे कि सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक, नैतिक आदि को एकत्रित करके विकसित करना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में छात्रों को सामग्र एवं बहु विषयक शिक्षा प्रदान करने का भी प्रावधान रखा गया है। जिससे कि बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके। इसके लिए लचीले पाठ्यक्रम को विकसित किया जाएगा। उच्चतर शिक्षा में कई प्रवेश और निकास बिंदुओं का विकल्प होगा। जिससे कि बच्चे अपने रुचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकें। एग्री कार्यक्रम की अवधि में भी आवश्यकता अनुसार बदलाव किए जा सकते हैं।

### सीखने के लिए सर्वोत्तम वातावरण एवं छात्रों का सहयोग

छात्रों को प्रभावी ढंग से शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण होना आवश्यक है। जिसमें उपायुक्त पाठ्यक्रम, आकर्षक शिक्षण, निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन, छात्रों का पर्याप्त सहयोग शामिल होता है। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी छात्रों की बेहतरी के लिए कुछ अन्य क्षमताएं जैसे कि फिटनेस, अच्छा स्वास्थ्य, नैतिक मूल्य का

आधार आदि भी छात्रों को सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सभी चीजें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शामिल की गई हैं। जिससे कि छात्र अपनी पढ़ाई गुणवत्ता पूर्ण ढंग से कर सकें। इसके अलावा इस पॉलिसी के अंतर्गत शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण भी किया जाएगा। जिससे कि भारत में पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या बढ़े और भारत के छात्रों को विदेशी संस्थानों में शोध करने का मौका मिल सके। इस पॉलिसी के माध्यम से छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का भी प्रावधान रखा गया है।

## व्यवसायिक शिक्षा

हमारे देश में व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बहुत कम है। व्यवसायिक शिक्षा को भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बढ़ावा देने का प्रावधान है। जिससे कि बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके। व्यवसायिक शिक्षा को हमारे देश में कम महत्व की शिक्षा माना जाता है। इस नीति के माध्यम से व्यवसायिक शिक्षा से जुड़ी सामाजिक धारणा को दूर करना है और अधिक से अधिक छात्रों तक व्यवसायिक शिक्षा का ज्ञान पहुँचाना है। इस योजना के माध्यम से वर्ष 2025 तक उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

## नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 की कुछ मुख्य बातें

- ❖ उच्च शिक्षा के लिए उपयुक्तप्रमाणीकरण के साथ कई प्रविष्टियां और निकास बिंदु होंगे।
- ❖ स्नातक कोर्स 3 या 4 साल के हो। जिसमें कई सारे एग्जिट ऑप्शन होंगे। जोकि उचित सर्टिफिकेशन के साथ है। जैसे कि यदि छात्र ने 1 साल स्नातक कोर्स में पढ़ाई की है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल के बाद एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 साल के बाद डिग्री दी जाएगी और 4 साल के बाद रिसर्च के साथ बैचलर की डिग्री दी जाएगी।
- ❖ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का गठन किया गया है। जिसमें छात्रों द्वारा अर्जित किये गए डिजिटल अकैडमी क्रेडिट हो विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से संग्रहित किया जाएगा और इसे अंतिम डिग्री के लिए स्थानांतरित किया जाएगा और मूल्यांकन किया।
- ❖ ई लर्निंग पर जोर देकर पाठ्य पुस्तकों पर निर्भरता को कम करना भी इस नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य है।

- ❖ राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा की पेशकश करेगी।
- ❖ 2030 तक हर जिले में कम से कम एक बड़ी बहु विषयक उच्च शिक्षा संस्थान का निर्माण किया जाएगा।
- ❖ 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बहु विषयक संस्थान बनाने का लक्ष्य इस नई शिक्षा नीति में रखा गया है।
- ❖ भारतीय उच्च शिक्षा आयोग संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए एकमात्र निकाय होगा। (चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर)
- ❖ भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के पास चार वर्टिकल होंगे जो कि नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल, हायर एजुकेशन काउंसिल तथा नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल होगा।
- ❖ शिक्षा नीति के अंतर्गत सरकारी तथा प्राइवेट शिक्षा मानक एक समान होंगे। तथा दिव्यांग जनों के लिए शिक्षा में बदलाव किया जाएगा।

### नई शिक्षा नीति के लाभ

**नई शिक्षा नीति के बहुआयामी लाभ नियमानुसार हैं—** पढ़ाई में संस्कृत और भारत की अन्य प्राचीन भाषाएं पढ़ने का विकल्प रखा गया है। छात्र अगर चाहे तो यह भाषाएं पढ़ सकते हैं।

- ❖ पढ़ाई को आसान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी किया जाएगा।
- ❖ हायर एजुकेशन से एमफिल की डिग्री को खत्म किया गया।
- ❖ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को मैन सिलेबस में रखा गया है।
- ❖ छात्रों को 3 भाषा सिखाई जाएंगी जो कि राज्य अपने स्तर पर निर्धारित करेंगे।
- ❖ इस नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कई सारे संस्थान स्थापित किए जाएंगे जिससे कि यह पॉलिसी सुचारू रूप से चल पाए।
- ❖ नई नेशनल एजुकेशन पालिसी के अंतर्गत बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ उनके कौशल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- ❖ नई शिक्षा नीति के अंतर्गत यदि कोई छात्र कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहता है तो वह पहले कोर्स से निश्चित समय तक ब्रेक ले सकता है और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है।

## निष्कर्ष-

नई शिक्षा नीति में अनेक विधाओं को समाहित किया गया है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा प्रणाली को समग्र, लचीला, बहुविषयक कौशलयुक्त एवं रोजगार परख बनाना है, जिसमें नीति का आशय कई मायनों में आदर्श स्थापित कर सकें।

यहाँ यह उद्धृत करना आवश्यक है कि केवल नई शिक्षा नीति लागू करने मात्र से किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति सम्भव नहीं होगी। अपितु लक्ष्य प्राप्त हेतु नीति के अनुरूप नीति क्रियान्वयन हेतु उचित योजना एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु उद्देश्यों के आधार पर प्रबन्धन करना आवश्यक है।

नीति का क्रियान्वयन जितनी द्रुत गति से होगा राष्ट्र उतना ही जल्द विश्वपटल पर राष्ट्रऋषि नानाजी देशमुख की ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा की परिकल्पना एवं नई शिक्षा नीति के उद्देश्य साकार हो सकेंगे।

## संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय 2020 रिपोर्ट आफ द न्यू इजुकेशनल पॉलिसी नई दिल्ली।
2. भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय 2021 रिपोर्ट आफ द कैब कमेटी आन हायर एजुकेशन एण्ड द कामन एजुकेशन सिस्टम नई दिल्ली।
3. भारत सरकार कानून न्याय एवं कम्पनी मामला मंत्रालय 2021 द रिहैबिलिटेशन काउन्सिलिंग आफ इण्डिया नई दिल्ली भारत।
4. एच.ई.सी.आई. भारत का उच्चतर शिक्षा आयोग नई दिल्ली।
5. एच.ई.जी.सी. उच्चतर शिक्षा अनुदान परिसर नई दिल्ली।
6. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली।
7. एम.एच.आर.डी. मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार।
8. एम.ई.आर.यू. बहु विषयक शिक्षा और अनुसन्धान विश्वविद्यालय।
9. यू.जी.सी. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार।
10. यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन।
11. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार।

# NANAJI “AN INSPIRING SOCIAL ENTREPRENEUR”

**Dr. Rajjan Dwivedi**, Department of sociology and social work.

Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P)

“I do not stand for myself but for my kith and kin... my kith and kin are those who are oppressed and neglected” - **Nanaji Deshmukh**

Chandikadas Amritrao Deshmukh who is popularly known as Nanaji Deshmukh was born on October 11<sup>th</sup> 1916 into a Marathi-speaking family at Kadoli, a small town in the Hingoli district of Maharashtra though losing his parents at a very early age and confronted severe poverty he acquired his education by selling vegetables to raise money for his education. Then he went to high school in Sikar, where the Raoraja of Sikar gave him a scholarship. Further he studied in the prestigious Birla Institute of Technology and Science in Pilani (BITS Pilani).

In the same year, he also joined the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). He was inspired by Bal Gangadhar Tilak and his nationalist ideology as well as showing an acquired interest in social services and activities. His family was in close contact with Keshav Baliram Hedgewar, was a regular visitor to Deshmukh’s family, who discern potential in Nanaji and encouraged him to attend RSS shakhas. Though born in Maharashtra, the field of his activities were Rajasthan and Uttar Pradesh, the RSS chief M. S. Golwalkar sent him to Gorakhpur(U.P) as a Pracharak, rose as the Saha Prant Pracharak of the whole of Uttar Pradesh where he took great pains to introduce Sangh ideology in the eastern Uttar Pradesh. It was not an easy task at that time as the Sangh had no funds to meet even day to day expenses, he had to stay in a Dharamshala but had to keep on changing Dharamshala as no one was allowed to stay there for more than three days consecutively, ultimately he was given shelter by Baba Raghav Das on the condition that he would also cook meals for him. He stayed there for almost three years, his hard work bore fruits and almost 250 Sangh Shakhas commenced in and around Gorakhpur. He always laid great emphasis on education, so he established India’s first Saraswati Shishu Mandir at Gorakhpur in 1950. The ideology behind the establishment of Shishu Mandir was to promote moral values among the society so that upcoming generation can become cooperative, helpful as well as kind towards society and according to him this can only be possible by right education. According to him, only education is not enough to build a developed society, it is important to teach the moral duties and ethics, as well its duty of every teacher to provide proper guidance for a better tomorrow.

Now more than 17,000 schools are running on the same ideology of Nanaji Deshmukh. Later when in 1947, the RSS decided to launch two journals Rashtradharma,

Panchjanya and a newspaper called Swadesh, he was made Managing Director of all three. Though it was a challenging task as the organisation was hard up for money to bring out the publication, yet it did never dampen their spirits and these publications gained popularity and recognition because of their strong nationalistic content, but unfortunately Mahatma Gandhi's assassination led to imposition of ban on the RSS and publication work came to a grinding halt, where keeping in mind about ban. Nanaji adopted a different strategy to do underground publication work those days.

He took his retirement at the age of 60 years from politics and started serving the Dendayal Research Institute that he himself had established way back in 1969. He did work towards the anti-poverty and minimum needs programme other areas of his work were agriculture, cottage industry, rural health and rural education.

He assumed chairmanship of the institute after leaving politics, he devoted all his time for building up the institute. This research institute is an integrated and holistic model for the development of rural India, based on the principles outlines in Pt. Deendayal Upadhyaya's Integral Humanism to create a society based on the complimentarity of the family, primary school and the local population.

It is a self-reliance campaign that was launched on 26<sup>th</sup> January 2002 and had covered 500 villages around Chitrakoot. This campaign had also started in the villages covered by the institute in Gonda and Beed districts. It covers all aspects of individual, family and societal life of the villagers. The key to the campaign was the concept of Samaj Shilpi Dampati (SSD), 'graduate' couples that lives within the villages itself and are responsible for motivating and guiding a cluster of 5 villages, foremost among the aspects covered is income generation and this is achieved by introducing watershed and soil management techniques were necessary; new and improved farming technologies through 2.5 and 1.5 acre model farms that enable small and marginal farmers, these farmers constitute 80% of the rural population to look after the family needs plus save and by increasing Non-Farm Sector incomes through entrepreneur training and the formation of income-generating Self Help Groups (SHGs) that are both stand alone, and vertically integrated. Issues of health and hygiene are the second most important aspect of the campaign, as an unhealthy individual is incapable of working to improve his/her economic condition, this project looks to Ayurveda and Naturopathy to keep villagers healthy, locally available herbs and nutritional vegetables gardens are the key interventions used in this area, including Dadi Ma Ka Batua, a collection of 34 Ayurvedic local herbs and preparations that can be used to treat common ailments, where Ayurveda is not applicable, as for example in Dentistry, state of the art facilities have been provided at Arogyadham. Illiteracy and social consciousness is the third area covered by the campaign - 'functional literacy campaign'

developed by Tata Consultancy Services is being conducted for the villagers by the Samaj Shilpi Dampati- Educational Research Centre and the 4 schools that operate within the project area, as well a unique museum- 'Ram Darshan' that highlights socially relevant aspects of lord Rama's life helps villagers inculcate human values to encourage them to live in a spirit of co-operation and harmony with each other.

Immediately he started his next project in Gonda. Keeping Motto:- "Har hath ko denge kaam, Har khet ko denge paane, namely 'Gramodaya Project' inaugurated in 1978 basically he was inspired by the thought of "Purna Swaraj" but he felt like its only possible when there will be "Gram Swaraj", thus he did a unique experiment in integrated rural development to achieve total transformation through holistic development with people initiative and participation. The objectives proclaimed and set for the rural development programme were:-To develop modern science and technology in accordance with Indian conditions to increase agriculture and industrial production. And -To bridge economic and social disparities to build self-sufficient and prosperous rural communities and popularizing cottage industries, to meet these objectives Nanaji worked on several areas of Gonda and started sub-projects like JSS Gonda, Chal Chikitsalay, Imlia Kodar, Ramnath Arogyadham Gramoday Rasshala, Udaymita Vidyapeeth (TPC) Chinmay Gromodaya Vidya Mandir, Intercollege Trifed Vanvasi Hostel for Tribal boys KVK Gopalgram Gonda, Trifed Junior High School, Bhaktidham, Grammin Shwasthya Matra Shishu Kalyan Kendra (MSKK) Udhyan, Deendayal Industrial Training Institute. "It is true to his words and thinking"...in words its just a project but to carry the objectives of that project there were several other projects with only those other sub-projects the Gramodaya project of Gonda got its true success, and this only can be possible by dedication.

Once successfully completed his work in Gonda he moved towards the Beed backward district of Maharashtra situated in Marathwada region. In 1987 DRI under supervision of Nanaji Deshmukh started working over the restoration of Sondara Tank of Beed. Due to poor or negligible rainfall of about 15-20 cms per annum, the Beed district faces drought every year. It was the main problem of people in Beed due to no or less rainfall they were not capable of doing farming or any other agricultural or industrial work that leads to poverty and other problems, through a detailed survey of the area they understood their problem and worked on it by the programme carried away by Nanaji which includes:- conservation of water desilting of tanks, digging of new percolation tanks and planting of trees in catchments area to increase rainfall etc. After solving the water problem of Beed district Nanaji initiated other projects for the people of Beed to solve their other problems Shishuvatika, JSS Beed (Jan Shikshan Sansthan) KVK Ambajogai.

Nanaji, settled down at the picturesque Chitrakoot, a holy place on the borders of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, it was in 1969 that Nanaji first time visited Chitrakoot and saw the pathetic condition of the society in the Karmabhoomi of '**Sri Ram**' it is the place where Lord Shri Ram spent 12 out of the 14 years in exile. He sat by the holy River Mandakini and resolved to change the face of Chitrakoot during his lifetime. While in exile, he started working for the upliftment of the downtrodden here with this important historical and inspiring background. Nanaji made Chitrakoot the centre of his social work. He choose to serve the poorest among the poor so he decided to work on aborigine area (Vanvasi) at that time he made a development model with the objective of health, hygiene, education, agriculture, income generation, conservation of resources and social conscience that is both sustainable and replicable with the aim of achieving self-reliance for these villages. Many of the hundreds of villages that have come under what is now popularly known as Chitrakoot project."One such experiment in project was in Satna district of Madhya Pradesh there is a region of aborigines (Majhgawa). He opened a special girl child school namely "Krishna Devi Vanvasi Aavashiya Balika Vidhyalay on 22<sup>nd</sup> July 1994, when he was the Chitrakoot he came to know that these aborigines don't allow there children's to go school and study at that time, Nanaji made them convince to allow their children's to study but still they were not agreed for sending their daughters at that time he showed his magnetical magical skills and manipulated their thoughts and make them agree. This school is not just for the education purpose but for the overall development of girl child like decoration, Rangoli, Mahendi, dancing, singing, and other sports activity, now with increasing technology, these schools are adopting new concepts of studies.

Later Nanaji established Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramoday Vishvavidyalaya (MGCGV) is India's first rural University on 12 February 1991 by a separate MP Government Act (9,1991) and was the first Vice Chancellor of Chitrakoot University. The university is dedicated for teaching, learning, research and extension focus on rural development, it creates human resources, develops appropriate technologies, conducts research and extension in sustainable agricultural techniques for rural livelihood and proper management of rural resources. It also imparts mass education for the awareness of the rural population including women and supports the exploration of alternative sources of energy. This university is divided into a vast academic of 5 Departments and 1 inter faculty centre like Science and Environment, Agriculture, Engineering and Technology, Rural Management, and Education aiming to provide higher education to the people living in the rural areas, to make them self-reliant. For fulfilment of the conceptual goal of "self-reliance", industrial training facilities were established by Deendayal Research Institute for people of the Chitrakoot

region. Basically in rural area of india, there main livelihood dependents upon agriculture and concerned activities related to it. But due to lack of knowledge these activities were carried with hard work and with very less economic benefits, till Nanaji took initiative to reduce the pain and pressure on agriculture by introducing new opportunities to youth of the villages by providing them training in their interested field related to agriculture activities. After getting trained they starts their own work and get employed and became “entrepreneur”. As well womens of such areas were given training related to their interest work to start their own small scale production units and become as “women entrepreneur”.

At present Udyamita Vidyapeeth provides following training like fruit and vegetable processing, poha and lai productions, mills establishment training like dal, flour, oil, rice, sugar etc, garment manufacturing like cotton, dairy product manufacturer like bakery , soap and detergent production etc. He was the person who knows the reality of the grounds of agriculture and difficulties faced by these poor and illiterate farmers, even after the hard work of them, they were incapable of getting the economical benefits, thus with introducing these training programme the rural people will get “self-reliance”.

At the age of 93 years on 27th February 2010 he took his last breath in Chitrakoot, which was his “karmabhoomi”, but before his death he made his “Will Letter “that his body will be donated to medical research institute as well he paid all the transportation as well other expenses. In 1999 he was awarded by “Padma Vibhushan” for his dedicated work towards the development of society, later posthumously he was awarded by “**Bharat Ratna**” in 2019.

## Reference:-

- 1- “Who was Nanaji Deshmukh”? - The Indian Express. Retrieved 11 October 2017
- 2- Architect of A Philosophy Bhartiya Sahitya by preeti Trivedi Retrieved 1st December 2017 (ISBN-9781613016381) p-37
- 3- Pt. Deendayal Upadhyay- Prabhat Prakashan by Anil Kumar ‘salil’ Retrieved 10th October 2014 (ISBN-9789351863519)p-5
- 4- “Religion, Caste, and Politics in India” Primus Book by Christophe Jaffrelot (2010) (ISBN-978-1849041386)p.193,194
- 5- Virat Purush Rajnitigya Nanaji–Prabhat Prakashan, Delhi 2016 (ISBN-9789351860815)p-27,68,131
- 6- Virat Purush Shikshavid Nanaji –Prabhat Prakashan, Delhi 2010 (ISBN-10-9351860787) p-77,109,124
- 7- Virat Purush Samajshastri Nanaji–Prabhat Prakashan, Delhi 2010 (ISBN-10-9789351860778) p-166,227
- 8- Virat Purush Sakshat Nanaji-Prabhat Prakashan, Delhi 2017 (ISBN-9351860760)p-79,135
- 9- Pt. Deendayal Upadhyay - An Inquest, introductory part by Dattopant Bapurao Thengadi 1988 (ISBN-9781849041386) p-9
- 10- BJP today volume 14, 2005 p-459

श्री गणेशाय नमः

# जे कृष्णमूर्ति के विचारों में निहित शांति शिक्षा की प्रासंगिकता का सृजन

शोध निर्देशिका

डॉ. नीतू तिवारी, सहायक आचार्या

शिक्षा विभाग ज.रा. द्वियांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट

शोध छात्र

दिलीप कुमार सिंह, (शिक्षा शास्त्र)

ज.रा.भ. द्वियांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट उ.प्र.

## सारांश—

ज्ञान का उद्देश्य समाज के अनुकूलन स्थापित बनाने के लिए अभिप्रेरित करना है और न के बराबर नकारात्मकता लाने के लिए है। आध्यात्मिक तथा परमजीवन मूल्यों को लाकर जीवन के परम उद्देश्य को अंगीकार कर सकते हैं। शिक्षा स्वयं को जागृत करती है और इसमें आभाव हो तो स्यं अहंकार बन जाता है।

## प्रस्तावना :

वर्तमान भूमण्डलीकर विपदा में शिक्षा की भूमिका क्या हो इसे अन्तं भूमि करना आवश्यक है। यह अशांति की विपदा कसे प्रकट हुई है इसे समझना आवश्यक है। इस इसमें दो विचारों के रूप में सहमत तथा असहमत हो सकते हैं। अगर विचारों में नकारात्मकता होगी तो शांति की कल्पना कैसे की जा सकती है। यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न पैदा करता है। शिक्षा में शांति का होना आवश्यक है जो हमें यह ज्ञात कराता है कि जीवन की वास्तविकता क्या है।

शांति क्या है यह मन की एक मात्र कल्पना है। जो हम किसी भी संगठन से रहित

होकर कर सकते हैं। समाज में परस्पर दीमनस्य पाली समाज व्यवस्था रहेगी तब तक इसे आन्तरिक खुशहाल नहीं रख सकते। जे. कृष्णमूर्ति जी के विचारों में निहित शांति की शिक्षा में घर समुदाय, परिवार एवं राष्ट्र तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व की कल्पना का उल्लेख किया गया है। इन्होंने विश्व की संकल्पना को समझाने का प्रयास किया है। शांति किसी विचार उपभागों से नहीं निकलती है और यह नियम बद्धता की कानून व्यवस्था पर आश्रित भी नहीं है। शांति शिक्षा तभी संभावित होती है जब मानक के रूप में हम स्वयं अपनी मनोविश्लेषणात्म प्रक्रिया में अन्तर्भूति करने लगे। शांति स्थापित स्वयं करने के लिए कार्य करने के अपने बोल से बचकर किसी नई समाज व्यवस्था के केवल दास बनकर न रह जाएं। शिक्षा व्यवस्था में शांति के लिये कृष्णमूर्ति जी व्यापारी, उपभोगतावादी मानसिकता से शिक्षा को बचाना होगा जो अपने आप में संघर्ष करने जैसा है। अधिनायक तंत्र अपने आप में बहुत ही कठिन कल्पना है जो हमें कठिनाई के मार्ग से हमें बचाती है। जे. कृष्णमूर्ति जी की शांति की संकल्पना एवं अनोखी प्रक्रिया है जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृष्णमूर्ति जी भय को अन्दर से भगाकर शांति की कल्पना को अपनाना होगा।

### **समस्या औचित्य/शोध की आवश्यकता :**

इस आधुनिकता के युग में स्वयं की शांति व प्रसन्नता के अभाव में आज मूल रूप से समाज में परस्पर विरोध एवं अलगाव की स्थितियां बन गयी हैं। समुदाय में संघर्ष उत्पन्न सा दिखाई दे रहा है मानव-मानव में प्रेम का अभाव दिखाई दे रहा है। एक शिक्षार्थी को भोजन, कपड़ा आवास मिलने पर यह अपने मन-चित्त सारी दैनिक चीजें मिलने पर यह खुश रह सकता है। यह कहना एक आवश्यक बिन्दु नहीं दिखाई देता है।

**समस्या कथन :-** जे. कृष्णमूर्ति के विचारों में निहित शांति शिक्षा की प्रासंगिकता -

**शोध के उद्देश्य :-**जे. कृष्णमूर्ति के विचारों में निहित शांति शिक्षा की प्रासंगिकता -

**शोध विधि :-**दार्शनिक एवं ऐतिहासिक अनुसंधान विधि प्रयोग में ली गयी है।

### **जे. कृष्णमूर्ति जी के विचारों में शांति शिक्षा के विचार :-**

विश्वास विचारमत तथा समायोजित धर्म हमारे आस-पास के लोगों में संघर्ष पैदा करती है। शांति के लिए संघर्ष विभिन्न समाजों में नहीं दिखती अपितु विभिन्न समूहों में भी दिखलाई पड़ती है। जब तक धर्म के पीछे चिपके रहेंगे तो हम बिना तर्क किये अपने धर्म

को सर्वश्रेष्ठ ही मान लेते हैं। अमर उजाला समाचार पत्र के एक सन्दर्भ के अनुसार कक्षा की भीतर की शक्ति को जागृत करे सब कुछ बचेगा। महाभारत काल में अश्वत्थामा ने पांडवों पर एक अत्यन्त शक्तिशाली अस्त्र से प्रहार किया था। जिसका पूरे विश्व में कोई प्रतिकार नहीं कर सकता था। कोई उसको काट नहीं सकता था। इस अस्त्र के बचाव के लिए भगवान श्रीकृष्ण ने एक सुझाव भी दिया था कि जब अस्त्र परमशक्तिशाली हो तो सब कुछ छोड़ शांत चित्त से हाथ जोड़कर खड़े रहना चाहिए इसी में सबकी भलाई है।

अज्ञान में जो संसार है, शान में यही परमात्मा है। जो बुद्धि और मन से परे है यह रहस्यमय है। आज पूरा विश्व रहस्यमय अतिसूक्ष्म कोरोना विषाणु से भयभीत है। ऐसे में प्रत्येक इन्सान के अंतर्मन में स्थित परमात्मा की शक्ति मानव कल्याण का सेतु है। ईश्वर अनादि और अनन्त है क्योंकि उसका न कोई प्रारम्भ है और न कोई अंत। आराधना से सूक्ष्म जीव को उसके अनुरूप विधि से परास्त किया जा सकता है। प्राचीन धर्म ग्रन्थों मानव शरीर एक नहीं तीन माने जाते हैं जिस शरीर को हम देखते हैं यह स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर और शरीर भी विद्यमान है। सर्वप्रथम मन-मस्तिष्क से कोरोना महामारी का भय और जीवन में आई हताशा, निराशा को दूर करना होगा, ताकि प्रकृति की मदद से प्राप्त हो सके।

**नीरज गोपाल जी ने कहा है—**सृजन शांति के वास्ते है जरूरी है कि हर द्वार पर रोशनी के गीत गाएं तभी मुक्ति का यज्ञ यह पूर्ण होगा। जब प्यार की तलवार से जीत जाए। घृणा बढ़ रही है आभा चढ़ रही है तो **मनुज को जिलाओ, दनुज को मिटाओ।**

- गोपाल दास नीरज

**महात्मा बुद्ध ने भी कहा है :-**अच्छा सोचो, अच्छा करो और अच्छे लोगो का संग करो। विचारों का संयंत चित्त को शांति और संतोष देगा।

इस प्रकार ही जे. कृष्णमूर्ति जी मानव जीवन में शांति के उद्देश्य को समझाया है संयंत चित्त बड़ा ही चंचल है जो अज्ञानता की भांतियों दूर तक ले जाने का प्रयास करता है मन की शांति की बहुत बड़ी शांति का एक प्रतिबिम्ब है।

**सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने कहा है कि :-** डर का जीवन की वास्तविकताओं से कोई लेना-देना नहीं होता। मनुष्य तभी डरता है, जब यह जीवन की वास्तविकता से जुड़ा न

होकर अपने मस्तिष्क पर निर्भर रहता है।

वर्तमान में रहते हुए आप भविष्य में नहीं जा सकते, भय से बाहर निकलने के लिए हमें जीवन से उसकी संपूर्णता में जुड़ना होगा। अगर आप सिर्फ आज के बारे में सोचेंगे, तो भय से बाहर निकल आएं। शांति यही आनन्द है, यही नैतिकता है जो अपने मूल में छिपा हुआ पूरा संसार के सुख-दुःख लपेटे हुए हैं। आप में आनन्द की अनुभूति होती है।

**रमण महर्षि** :—यह आत्मा स्वयं आनन्द है अज्ञान बीच में आकर पर्दा डाल देता है, आत्मा को गलती से देह-मन के एकरूप मान लेना मिथ्या ज्ञान है कोई भी आत्मा का निषेध नहीं कर सकता। जिसका प्रारम्भ है उसका अन्त भी है। जब शाश्वत चेतना का साक्षात्कार होगा, तो यही केवल स्थायी होगा। चैतन्य सदैव हमारे साथ है, आत्मा शुद्ध चैतन्य है कोई भी कभी भी आत्मा से दूर नहीं करा जा सकता है।

शिक्षा में शांति शिक्षा का एक सजीव प्रभाव आध्यात्मिकता में छुपा रहता है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिन्दु बना होता है शांति की तलाश में हर आदमी भटक रहा है यह कहाँ मिलेगी? और कैसे मिलेगी? यह जटिल प्रश्न समझ में आता इसके बिना मन में भय तथा आक्रांत भी दिखलाई देता है यह कैसा भय है. जो एक-दूसरे को डराता रहता है।

शांति के लिए एवं सीखने के लिए भी विनम्रता आवश्यक है।

**जे. कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि** :—मैं तुम्हें आश्चर्य करता हूँ कि जब तुम पूर्ण नग्न होते हो तब पूर्णतः निराश होते हो तब उस प्राणपूर्ण असुरक्षा के पल में परम प्रकाश की ज्योति जलती है, सत्य का आनन्द जन्मता है।

जे. कृष्णमूर्ति जी कहते हैं अटूट ज्ञान की ज्योति तभी जलती है जब सत्य की प्रकृति को समझा जाय कि यह क्या है? यह कैसे होगा? इसी में अपने आप को पाने की बात की जाए।

**जे. कृष्णमूर्ति जी अपने मैत्री संवाद में कहते हैं** :—अमीर लोग रात को क्लबों में, मनोरंजन में, कारों में और यात्रा में खुद को भूलना चाहते हैं। इसलिए ये असाधारण मान्यताओं की खोज करना प्रारम्भ कर देते हैं। बेवकूफ लोग खुद को भूलना चाहते हैं और इसलिए ये अमीर लोगों का अनुसरण करते हैं। उनके पास गुरु होते हैं जो बताते हैं कि क्या करना है? महत्वाकांक्षी भी कुछ करने में खुद को भूलना चाहते हैं। इसलिए हम सभी

जैसे-जैसे बड़े हो जाते हैं, अपने आप को भूलना चाहते हैं और इसलिए इन्हें बड़ा करने की कोशिश करते हैं। जिसकी पहचान की जाए।

### अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ :

1. जीवन में फैली अशांति को दूर करने में जे. कृष्णमूर्ति की शिक्षा सहायक हो सकती है।
2. जे. कृष्णमूर्ति शिक्षा, स्कूली वातावरण में शांति मूल्य को बनाये रखने में सहायक।
3. जे. कृष्णमूर्ति जी स्वयं के अनुशासन की बात करते हैं।
4. जे. कृष्णमूर्ति जी मनोवैज्ञानिक समस्याएं यथा भय, कुण्ठा, हिंसा के न होने पर जो व्यवहार मनुष्य करता है उसको नैतिक विचार कहा गया है। बालक के विकास में इन बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। इससे शैक्षिक जगत सृजित होगा।

### शोध की परिसीमाएं :

1. यह शोध कार्य जे० कृष्णमूर्ति के विचारों में निहित शांति शिक्षा की प्रासंगिकता तक सीमित है।
2. यह शोध कार्य प्राथमिक स्रोत जे. कृष्णमूर्ति द्वारा रचित पुस्तकों तथा द्वितीयक स्रोत जे० कृष्णमूर्ति पर अन्य लेखकों द्वारा लिखी गयी पुस्तकों पर आधारित है।

### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. कुमार डा० गुप्ता Volume-8 / Issue-8 August 2019 Paripex Indian Journal of Research जे० कृष्णमूर्ति के शैक्षिक विचारों की वर्तमान में प्रासंगिकता
2. कृष्णमूर्ति जे० पुनः मुद्रित फरवरी 2011 शिक्षा एवं जीवन का तात्पर्य प्रकाशक- कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इंडिया राजघाट फोर्ट, वाराणसी
3. कृष्णमूर्ति जे. अगस्त 2011 जीवन और दर्शन प्रकाशक- कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इण्डिया राजघाट फोर्ट वाराणसी
4. ब्रह्म कुमारी शिवानी (10.12.2020) सुख-शांति जन्म सिद्ध अधिकार दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, प्रकाशन- चन्दाली पृ.सं. 2
5. भिन्या राजी गिरिराज ( अप्रैल 2019) भारतीय आधुनिक शिक्षा, त्रैमासिक पत्रिका, वर्ष 39, अंक-4, INSSN0972-5636 एन.सी.ई.आर.टी. विद्यालयी शिक्षा में शांति शिक्षा पृ०सं०-35

# शिक्षण में उचित वातावरण का निर्माण एवं शिक्षार्थी का सहयोग आवश्यक

— नीलिमा गुप्ता, विद्यार्थी प्रतिनिधि

सीखने के लिए सर्वोत्तम वातावरण व छात्रों का सहयोग यह सत्र इस पर आधारित था और इस सत्र पर हम लोगों ने बेसिकली दो चीजों पर चर्चा की है कि सीखने के लिए हमें एक एनवायरमेंट कैसा मिलना चाहिए और उसमें स्टूडेंट सपोर्ट कैसा मिलना चाहिए यह हाल की एक विस्तृत टॉपिक है और सभी ने प्रकाश डाला भी है लेकिन यदि हम वातावरण की बात करें तो वातावरण किसी भी छात्र के लिए या किसी शिक्षक के लिए भी तो सबसे पहले छात्र के घर के वातावरण से प्रारंभ होता है घर के साथ साथ समाज का वातावरण और समाज के साथ-साथ विद्यालय और विश्वविद्यालय का वातावरण इन सभी जगह वह जो भी सीखता है वही उसके व्यक्तित्व को गढ़ता है।

इन 2 वर्षों में हमने देखा कि शिक्षा का एक नया वातावरण तैयार हो गया जब यह शिक्षा नीति बन रही थी। कई बैठके हुई, चर्चाएं हुई वह महामारी के हालातों में बिल्कुल फिट बैठे। आज नानाजी की 12 वीं पुण्यतिथि है मैं उनको नमन करती हूँ। यह भी एक संयोग है कि एक तरफ नाना जी की जो शिक्षा नीति थी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस पर कार्य होने लगा था और साथ में कोविड आ गया। तीनों बिंदुओं पर हमने देखा कि हम कैसे फिजिकल से डिजिटल मोड में चले गए।

लॉकडाउन में हम पूरे डिजिटल मोड में चले गए लेकिन तब हमने सोचना शुरू किया कि हम पूर्ण रूप से ना तो डिजिटल हो सकते हैं और ना ही फिजिकल। यूजीसी का पूरा प्रारूप बनाया इस ब्लैंडर्ड मोड ऑफ टीचिंग के साथ कोरोना के भी कई वेव आये और पूरा शिक्षा का पैटर्न बदल गया, ऑफ ट्रेक हो गया पुनः पटरी पर लाने के लिए बार-बार हम डिजिटल मोड पर चले जाते थे बार-बार हमें याद आता था कि पूरा डिजिटल मोड पर हम ना पढ़ा सकते हैं ना बच्चे सीख सकते हैं तो अल्टीमेटली मोड बना फिजिकल।

वेबीनार होते थे और आज जो इतने लोगों से सभी से सामने साक्षात भेंट हुई सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति गण से भेंट हुई तो सबसे जानकारी मिली कि किसके विश्वविद्यालय में क्या चल रहा है, फिजिकल मोड का यही फायदा है ज्ञान और जानकारी का आदान-प्रदान हो पाता है।

क्वालिटी ऑफ टीचर की हम एक तरफ चर्चा कर रहे हैं हमें क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी चाहिए। इसी तरह शिक्षक की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी प्रयास होना चाहिए कोई भी शिक्षक आजकल नेट क्वालिफाइड करके और सीधे क्लास रूम में एंटर कर जाता है उसे बच्चों को फेस करना पड़ता है और वह पढ़ाते पढ़ाते सीखता है जबकि उसकी ट्रेनिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

हम ऑफलाइन से सीधे ऑनलाइन मोड में चले गए क्लास रूम में हम बच्चों को मोबाइल चलाने से मना करते थे और अब बिना मोबाइल के कोई क्लास नहीं होती सारे मैटेरियल ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी में आ गए।

शिक्षकों का कर्तव्य है छात्र पर निगरानी रखना उसको परखना समाज को परखना उनकी इयूटी थी। समाज के प्रति और अपने विषय के प्रति और स्वयं के प्रति भी क्योंकि उसके स्वयं के आचरण से ही छात्र सीखने वाला है। हम क्लास रूम से जूम पर आ गए। यह चर्चा भी हो रही थी कि हमारे छात्र खासतौर पर अच्छे छात्र बाहर चले जाते हैं क्या हमने कभी गणना करने का प्रयास किया कि जो हमारे छात्र बाहर चले जा रहे हैं उनके ऊपर हम कितने करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं।

हर साल 700000 विद्यार्थी विदेशों में चले जाते हैं पढ़ने के लिए और करोड़ों रुपए जो वहां पर वह खर्च करते हैं उसमें से हम 7 आईआईटी प्रतिवर्ष भारत में खड़े कर सकते हैं। यह सोचने की आवश्यकता है कि हम जो लोन छात्रों को देते हैं विदेशों में पढ़ने के लिए बैंक लोन देते हैं उन पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि क्यों हमारे छात्र छात्राएं बाहर जाते हैं तो ध्यान में आएगा की शिक्षा का एक वातावरण है वहां पर मैंने भी अनुभव किया कि एक विश्वविद्यालय में पूरा टाउनशिप रहता है बच्चों को एक संपूर्ण वातावरण शिक्षा का दिया जाता है।

क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं। हमें इन बिंदुओं पर बहुत गहरा विचार करना है और हमें ऐसा ही एक वातावरण क्रिएट करना होगा जिससे कि हमारा बच्चा उस वातावरण में इतना खुश हो जाए कि वह बाहर जाने की सोचे ही नहीं। आज हम लोग आईटी एजुकेशन सिस्टम से जुड़ाव हो हमें याद है अपने प्रधानमंत्री जी के शब्द आईटी. आईटी = आईटी

इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी. इंडियन टैलेंट = इंडिया ऑफ टुमारो। हम अपने बच्चों को भी इस तरह से सिखाएं इस तरह से सपोर्ट दें एक ऐसा वातावरण क्रिएट करें जो उनके बेहतर भविष्य के लिए साथ ही साथ देश का भविष्य निर्माण करें।

मैं आशा करती हूँ कि हमारी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस तरह से निखर कर आएगी कि हम सब उस में सहयोग करेंगे और आने वाले कल को हम बेहतर शिक्षा वातावरण दे सकेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

## समापन सत्र

# राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समग्रता और प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के पंच सूत्रीय संकल्प के साथ हुआ संगोष्ठी का समापन

नानाजी देशमुख के शैक्षिक चिंतन पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी और पूर्ण रूप से लागू करने के लिए पंचसूत्रीय संकल्प के साथ हुआ।

समापन सत्र की अध्यक्षता मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने की। संतोषी अखाड़ा के महंत राम जी दास जी महाराज मार्गदर्शक उत्प्रेरक के रूप में उपस्थित रहे। मध्यप्रदेश शासन एवं सतना जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय शाह एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री कमल पटेल, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रामखेलावन पटेल, खजुराहो से सांसद और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री बीडी शर्मा, सतना के सांसद श्री गणेश सिंह, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ त्रिलोचन महापात्रा, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर भरत मिश्रा, पूर्व कुलपति एवं संगोष्ठी के कन्वेनर प्रो नरेश चंद्र गौतम, दीनदयाल शोध संस्थान के प्रधान सचिव श्री अतुल जैन एवं संगठन सचिव श्री अभय महाजन मंच पर उपस्थित रहे। सभी विशिष्ट जनों ने नाना जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व पर अपने-अपने क्षेत्रों में समाज और राष्ट्र के कार्य करने का आह्वान किया।

अध्यक्षीय उद्बोधन में विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने कहा कि बहुत वर्षों की प्रतीक्षा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह महत्वपूर्ण नीति बनी है। अब यह हम सब के ऊपर है कि हम सब दृढ़ता से और परिपूर्ण रूप में लागू करें। यदि हम पीछे रह जाते हैं तो हमें पहले की तरह शिक्षा नीतियों को अपनी समस्याओं के लिए दोषी ठहराने का आधार नहीं रह जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री कमल पटेल ने किसानों की समृद्धि के लिए राज्य सरकार के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि किसानों का कल्याण

सर्वोच्च प्राथमिकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों से कृषि उत्पादकता को जोड़ कर हम अनेक प्रयास कर रहे हैं।

सतना जिले के प्रभारी मंत्री श्री कुंवर विजय शाह ने कहा किसी भी देश के निर्माण का आधार शिक्षा प्रणाली होती है, साथ ही भविष्य निर्माताओं का निर्माण करती है। उसके पृष्ठभूमि में शिक्षा नीति का योगदान होता है। उन्होंने कहा कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का शिक्षा नीति में संशोधन के तीन दशक बाद राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 आई है। नई शिक्षा नीति त्रिभाषा फार्मूला पर आधारित ऐसी शिक्षा नीति है जिसमें माध्यम की समस्याओं की स्थाई और प्रमुख बाधा के रूप में सामने थी, का निराकरण किया गया है। नई शिक्षा नीति बुनियाद की मजबूती पर केंद्रित है। इसमें शिक्षा का विविध स्तर पर वर्गीकरण किया गया है, जो जितना पढ़ेगा उतना उसे मिलेगा। इस शिक्षा नीति में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा ऑनर्स का प्रावधान इसीलिए किया गया है की, यदि शिक्षार्थी की शिक्षा मध्य में ही समाप्त हो जाती है तो उसे कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त हो।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रामखेलावन पटेल ने कहा कि गांव के समग्र विकास के बारे में जो नाना जी का चिंतन था उसे पूरे देश में पहुँचाने का प्रयत्न होना चाहिए।

स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक एक ही दस्तावेज बनाया गया है, जिससे पूरी नीति में संपूर्ण शैक्षिक परिदृश्य के बारे में एकरूपता दिखती हैं। पहले की शिक्षा प्रणाली मूल रूप से सीखने और परिणाम देने पर केंद्रित थी। विद्यार्थियों का आकलन प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता था। यह विकास के लिए एक एकल दिशा वाला दृष्टिकोण था। लेकिन नई शिक्षा नीति एक बहु-विषयक दृष्टिकोण की प्रासंगिकता पर केंद्रित है। जिसका उद्देश्य विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना है। नई शिक्षा नीति एक नए पाठ्यक्रम और शिक्षा की संरचना के गठन की कल्पना करती है जो छात्रों को सीखने के विभिन्न चरणों में मदद करेगी। नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य एक बच्चे को एक कुशल बनाने के साथ-साथ, जिस भी क्षेत्र में वह रुचि रखता है, उसी क्षेत्र में उन्हें प्रशिक्षित करना है। इस तरह, सीखने वाले अपने उद्देश्य, और अपनी क्षमताओं का पता लगाने में सक्षम होते हैं। शिक्षार्थियों को एकीकृत शिक्षण प्रदान किया जाना है यानी उन्हें प्रत्येक अनुशासन का ज्ञान होना चाहिए। उच्च शिक्षा में भी यही बात लागू होती है। नई शिक्षा नीति में शिक्षक की शिक्षा और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के सुधार पर भी जोर दिया गया है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली वर्ष 1986 की मौजूदा शिक्षा नीति में किए गए परिवर्तनों का परिणाम है। इसे शिक्षार्थी और देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है। नई शिक्षा नीति बच्चों के समग्र विकास पर केंद्रित है। इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य है।

खजुराहो के सांसद और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री बीडी शर्मा ने कहा कि नानाजी के ग्रामीण विकास के चित्रकूट मॉडल को पूरे देश में फैलाने की जरूरत है। अलग-अलग संस्थाएं और सरकारें इस दिशा में कार्य करें तो शीघ्र ही परिणाम मिलेंगे।

शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के लिए एक नया पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना की परिकल्पना की गई है जो शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं और उनके विकास के विभिन्न चरणों में प्रासंगिक है। इस नीति का उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को तैयार करना है जो भारत के सभी बच्चों को लाभान्वित करे। इस का लक्ष्य **“भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति”** बनाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों की नई गुणवत्ता को स्थापित करना व आसान बनाना है जो वैश्विक मानकों के अनुरूप होगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ त्रिलोचन महापात्रा ने कृषि शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बदलाव की चर्चा करते हुए सरकार के कार्यों की सराहना की। संतोषी अखाड़ा के महंत राम जी दास महाराज ने नाना जी को एक आध्यात्मिक विभूति निरूपित किया और उनके बताए रास्ते पर चलने की सीख दी।

सतना के सांसद श्री गणेश सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर यह वैचारिक मंथन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके प्रभावी क्रियान्वयन से आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का जो वातावरण बनेगा उसे उद्यमिता का भाव प्रोत्साहित होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि शिक्षा की विषयवस्तु ऐसी हो जो बच्चों को समस्या-समाधान, तर्क शक्ति एवं रचनात्मक रूप से सोचना सिखाती हो। बच्चे विषयों के बीच अंतर संबंध देख पाते हों। नया सोच और नई जानकारी को नई परिस्थितियों में उपयोग में करना सिखाती हो। शिक्षा शिक्षार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और क्षमताओं का संतुलित विकास करती हो तथा प्रक्रिया ऐसी हो जो शिक्षार्थी केन्द्रित हो, जिज्ञासा, खोज, अनुभव और संवाद के अवसर देती हो। समग्रता और समेकित रूप से देखने-समझने में सक्षम बनाती हो।

संगोष्ठी संयोजक एवं पूर्व कुलपति प्रोफेसर एनसी गौतम ने संगोष्ठी के निष्कर्ष के रूप में संकल्प पत्र प्रस्तुत किया।

आगंतुक अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो भरत मिश्रा ने कहा कि इस प्रतिष्ठित आयोजन में आप सब को पाकर हम सब गौरवान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा विश्वविद्यालय नानाजी के शैक्षिक चिंतन का जीवंत स्मारक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान लोक व्यापी होकर जन जन तक पहुँचते हैं और भारत के विश्व गुरु बनने की आधारशिला रखते हैं तो सबसे अधिक प्रसन्नता महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय और दीनदयाल शोध संस्थान को ही होगी।









## पंच सूत्रीय संकल्प

- विद्यार्थी अपने ज्ञान कौशल और प्रतिभा का उपयोग राष्ट्र के सतत विकास विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत लोगों और अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों के कल्याण के लिए करें, इस हेतु हम उन्हें प्रोत्साहित करेंगे।
- शैक्षणिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा, गरिमा और उपयोगिता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम अपने पाठ्यचर्या, शिक्षण प्रशिक्षण पद्धति एवं अनुसंधान आयामों को स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुरूप पुनर्गठित करेंगे तथा इसके लिए समन्वित प्रयास करेंगे।
- हम ऐसी सहभागी मूल्यांकन पद्धति विकसित करेंगे जो छात्र, शिक्षक एवं समाज को जोड़कर स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर समाधान प्रस्तुत करें।
- हम सब मिलकर ऐसा रचनात्मक, पारदर्शी और मूल्य आधारित कार्यप्रणाली विकसित करेंगे जिससे सामाजिक उत्तरदायित्वों से ओतप्रोत पीढ़ी तैयार हो सके।
- हम सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को समग्रता और परिपूर्णता के साथ प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्वयं को समर्पित करते हैं

# तुलनात्मक विवेचना

## शिक्षा के संबंध में नाना जी का दृष्टिकोण एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति

| क्र.सं. | आयाम                     | नानाजी का दृष्टिकोण  | राष्ट्रीय शिक्षा नीति  |
|---------|--------------------------|--|--|
| 1.      | शिक्षा का स्तरीकरण       | नाना जी का स्पष्ट मत था कि शिक्षा का स्तरीकरण आवश्यक है जो प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक को समाहित करें।            | नई शिक्षा नीति में स्तरीकरण निम्नवत रखा गया है।  |
| 2.      | मातृभाषा में शिक्षण कौशल | संज्ञानात्मक विकास के साथ मातृभाषा में सीखना अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होता है।                                    | प्रारंभिक शिक्षा को मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान।   |
| 3.      | शिक्षा की प्रधानता       | छात्रों को प्रारंभ से ही उसकी रुचि के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण देना।  | आठवीं कक्षा से परीक्षण के द्वारा छात्रों का रुझान जानना एवं उसी दिशा में उसे कौशल प्रदान करना। |
| 4.      | सामाजिक सरोकार           | युगानुकूल सामाजिक पुनर्चना के लिए शिक्षा को हथियार बनाकर विद्यार्थी को तैयार करना।                               | गांव को गोद लेने का प्रावधान तथा क्षेत्रीय चीजों का बढ़ावा देना।                               |
| 5.      | समाज की सम्पूरकता        | स्कूल से ही नहीं बल्कि समाज से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है अर्थात् समाज में प्रचलित ज्ञान को स्कूल स्तर पर लाना। | समाज तथा संस्थानों में जाकर सामाजिक एवं संबंधी ज्ञान अर्जन करना।                               |
| 6.      | शिक्षा में समग्रता       | शिक्षा व्यक्तित्व विकास की समस्त पहलुओं को समाहित करें ना कि खंडित रूप में।                                      | पहली बार प्राथमिक से वाचस्पति डिग्री तक का पूरा प्रावधान एक साथ रखा जाना।                      |
| 7.      | मूल्य                    | मूल्यपरख शिक्षा के हिमायती।  | मूल्यपरक शिक्षा पर बल दिया जाना।   |
| 8.      | आत्मनिर्भरता             | स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता शिक्षा के मूल में हो।   | विविध प्रावधानों के माध्यम से नौकरी पर निर्भरता को कम कर स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता पर जोर।    |

# सुप्रसिद्ध भजन गायिका सुश्री मुस्कान चौरसिया के भजनों से माहौल हुआ भक्तिमय

राष्ट्रीय संगोष्ठी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन रहा। जिसमें बालाघाट मध्य प्रदेश की युवा भजन गायिका सुश्री मुस्कान चौरसिया का भजन कार्यक्रम रहा, जिसमें गायिका के भक्ति संगीत का आनंद भी सेमिनार में उपस्थित लोगों को सुनने को मिला।

गायिका द्वारा बजाओ रे बाजा, राम जी का मंदिर बनाओ, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे आदि भजनों के माध्यम से माहौल को भक्तिमय बनाया।

बालाघाट के ग्रुप मां वैष्णो देवी जागरण मंच के द्वारा आयोजित संगीतमय भजन कार्यक्रम में उनकी टीम ऑर्गन पर रिंकू कपूर, ढोलक पर शुभम शर्मा, पेड़ प्लेयर अनिकेत ठाकुर, ड्रम प्लेयर नितिन कटारे, गिटार पर विवेक, तबला पर पवन, उद्घोषक के रूप में आशुतोष कटरहा, कोरस पर अंकित, आनंद आदि कलाकारों की प्रस्तुति ने माहौल को भक्तिमय बनाते हुए दीनदयाल परिसर के विवेकानंद सभागार में मौजूद दर्शकों एवं अतिथियों को खूब आनंदित किया।

शाम को संस्कृति संचालनालय भोपाल की टीम द्वारा भक्ति मति शबरी वनवासी लीला नाटक की प्रस्तुति की गई। जिसके निर्देशक गुरु निर्मल दास एवं संगीत संयोजक मिलिंद त्रिवेदी तथा आलेख योगेश त्रिपाठी का रहा।

27 फरवरी को निषादराज गुहा नाट्य प्रस्तुति रही। उपरोक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम भोपाल के ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा दोनों दिन शाम 7:30 बजे से विवेकानंद सभागार, दीनदयाल परिसर में किया गया, जो की देर रात्रि तक चलता रहा।





12 नवम्बर 2020  
सतना

सतना

www.satnaindia.com

# नानाजी की पुण्यतिथि पर देश की नई शिक्षा नीति पर मंथन

कन जी के दर्शन में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चुनौतियों का समाधान डॉ. मोहन वादव



सतना, राष्ट्रीय संघ

सतना, 12 नवम्बर 2020: देश की नई शिक्षा नीति पर मंथन के दौरान सतना में आयोजित कार्यक्रम का सत्र।



उद्घाटन सत्र

उद्घाटन सत्र में सतना में आयोजित कार्यक्रम का सत्र।

## सतना में नई शिक्षा नीति पर मंथन

सतना में आयोजित कार्यक्रम का सत्र।

# भारत रत्न नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि पर विविध कार्यक्रम 'नानाजी की आत्मनिर्भर भारत सोच का साकार रूप है नई शिक्षा नीति'

नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि पर सतना में आयोजित कार्यक्रम का सत्र।



विचार मंच पर

विचार मंच पर सतना में आयोजित कार्यक्रम का सत्र।



विचार मंच पर

विचार मंच पर सतना में आयोजित कार्यक्रम का सत्र।

## विचारमंच पर आत्मनिर्भर भारत सोच का साकार रूप है नई शिक्षा नीति

विचारमंच पर सतना में आयोजित कार्यक्रम का सत्र।

# राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल होने आए 12 राज्यों के कुलपति किसके क्या विचार



राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल होने आए 12 राज्यों के कुलपति

राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल होने आए 12 राज्यों के कुलपति

सतना, 12 नवम्बर 2020: देश की नई शिक्षा नीति पर मंथन के दौरान सतना में आयोजित कार्यक्रम का सत्र।

सतना में आयोजित कार्यक्रम का सत्र।

# भारत रत्न राष्ट्र गुरु नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि पर विविध कार्यक्रम आयोजित



भारत रत्न राष्ट्र गुरु नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि पर विविध कार्यक्रम आयोजित

भारत रत्न राष्ट्र गुरु नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि पर विविध कार्यक्रम आयोजित

# सतना स्टार शहर-आसपास 4

नानाजी की दर्शन में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तर्कों में दो दिवसीय राष्ट्रीय संकेदी का आयोजन

# नानाजी के दर्शन में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चुनौतियों का समाधान: डॉ. मोहन वादव

नानाजी के दर्शन में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चुनौतियों का समाधान: डॉ. मोहन वादव

# नवभारत सतना

# नानाजी के शैक्षिक चिंतन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में बड़ा साम्य: डॉ. मोहन वादव

नानाजी के शैक्षिक चिंतन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में बड़ा साम्य: डॉ. मोहन वादव

12 वीं पुण्यतिथि पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी से निकले पांच सूत्रीय संकल्प



नानाजी ने दिखाई थी स्वावलंबन की राह अब शिक्षा के जरिए आगे बढ़ रही सरकार

अपने लिए नहीं बल्कि अगले को लिए जीने का मुहूर्तक देने वाले राष्ट्रपति नानाजी देशमुख ने नानाजी जयन्ती के अवसर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेते हुए कहा कि शिक्षा के जरिए आगे बढ़ रही सरकार नानाजी की राह का अनुसरण करेगी।

नेतिन में सरकार ने ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित की है जो न केवल बुनियादी, संस्कृत, अल्पसंख्यक, विद्यार्थी समेत विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करेगी बल्कि उनके कौशल को विकसित करेगी। अल्पसंख्यक और नानाजातीयों को शिक्षा के माध्यम से समाज में शामिल करने के लिए सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं।

देश के उदय में विद्यार्थी में देश के विभिन्न राज्यों से अल्प कुलपति व विद्यार्थियों के साथ राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ जिसमें पांच सूत्रीय संकल्प निकाले गए। इन संकल्पों को पूरा करने का संकल्प अल्पसंख्यक विद्यार्थियों व अल्पसंख्यक कुलपतियों के संकल्प के रूप में लिया गया है।

नई शिक्षा नीति पर जाने किसने क्या कहा-

विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि नई शिक्षा नीति पर सरकार ने बहुत ध्यान दिया है। नई शिक्षा नीति को लागू करने में सरकार को बहुत ध्यान देना होगा। नई शिक्षा नीति को लागू करने में सरकार को बहुत ध्यान देना होगा। नई शिक्षा नीति को लागू करने में सरकार को बहुत ध्यान देना होगा।



राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेते हुए नानाजी देशमुख ने कहा कि शिक्षा के जरिए आगे बढ़ रही सरकार नानाजी की राह का अनुसरण करेगी। नानाजी देशमुख ने कहा कि शिक्षा के जरिए आगे बढ़ रही सरकार नानाजी की राह का अनुसरण करेगी।

राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेते हुए नानाजी देशमुख ने कहा कि शिक्षा के जरिए आगे बढ़ रही सरकार नानाजी की राह का अनुसरण करेगी। नानाजी देशमुख ने कहा कि शिक्षा के जरिए आगे बढ़ रही सरकार नानाजी की राह का अनुसरण करेगी।

राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेते हुए नानाजी देशमुख ने कहा कि शिक्षा के जरिए आगे बढ़ रही सरकार नानाजी की राह का अनुसरण करेगी। नानाजी देशमुख ने कहा कि शिक्षा के जरिए आगे बढ़ रही सरकार नानाजी की राह का अनुसरण करेगी।

28 फरवरी 2022, 12 वीं पुण्यतिथि पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन

नई शिक्षा नीति को समग्रता व प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने का संकल्प

A collection of smaller images and text snippets related to the national symposium, including photos of speakers and audience members.

चित्रकूट में शिक्षा नीति पर मंत्रियों ने रखे विचार

A collection of smaller images and text snippets related to the symposium, including photos of speakers and audience members.





## Committee for the Draft National Education Policy

### CHAIRPERSON

**K. Kasturirangan**, Former Chairman, ISRO, Bengaluru

### Members

- a. Vasudha Kamat, Former VC, SNDT Women's University, Mumbai
- b. Manjul Bhargava, R. Brandon Fradd Professor of Mathematics, Princeton University, USA
- c. Ram Shankar Kureel, Former Founder VC, Baba Saheb Ambedkar University of Social Sciences, Madhya Pradesh
- d. T. V. Kattimani, VC, Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak, Madhya Pradesh
- e. Krishna Mohan Tripathy, Director of Education (Secondary) and Former Chairperson of Uttar Pradesh High School and Intermediate Examination Board, Uttar Pradesh
- f. Mazhar Asif, Professor, Centre for Persian and Central Asian Studies, School of Language, Literature and Culture Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi
- g. M. K. Sridhar, Former Member Secretary, Karnataka Knowledge Commission, Bengaluru, Karnataka

### SECRETARY

- h. Shakila T. Shamsu, Officer on Special Duty (National Education Policy), Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, Government of India, New Delhi

### Members of the Drafting Committee

- a. Manjul Bhargava, R. Brandon Fradd Professor of Mathematics, Princeton University, USA
- b. K. Ramachandran, Advisor, National Institute of Educational Planning and Administration, New Delhi
- c. Anurag Behar, CEO, Azim Premji Foundation & Vice Chancellor, Azim Premji University, Bengaluru
- d. Leena Chandran Wadia, Observer Research Foundation, Mumbai

## Vision

The National Education Policy 2019 envisions an India-centred education system that contributes directly to transforming our nation sustainably into an equitable and vibrant knowledge society, by providing high quality education to all

## Policy Overview - Key Points

### School Education

- a. Early childhood education: The Policy emphasizes the criticality of the early years and aims to ensure quality early childhood care and education for all children between 3-6 years by 2025 with significantly increased investment and new initiatives.
- b. Foundational literacy and numeracy: There will be special attention paid to early language and mathematics in Grades 1-5. The Policy aims to ensure that every student in Grade 5 and beyond must achieve foundational literacy and numeracy by 2025.
- c. Curriculum and pedagogy: A new developmentally-appropriate curriculum and pedagogical structure for school education based on principles of brain development and learning has been developed based on a 5 + 3 + 3 + 4 design. There will be equal emphasis on all subjects - science, social sciences, art, languages, sports, mathematics - with integration of vocational and academic streams in school.
- d. Universal access: The Policy aims to achieve 100% Gross Enrolment Ratio for all school education by 2030 through various measures.
- e. Equitable and inclusive education: The Policy has several concerted initiatives to ensure that no child loses any opportunity to learn and excel because of the circumstances of birth or background. Special education zones will also be set up to focus on this.
- f. Teachers: Teachers will be recruited through robust, transparent processes, promotions will be merit-based, multi-source periodic performance appraisals will happen and progression paths to become educational administrators or teacher educators will be available.
- g. School Governance: Schools will be organized into school complexes (cluster of 10-20 public schools) - this will be the basic unit of governance and administration that will ensure availability of all resources - infrastructure, academic (e.g. libraries) and people (e.g. art and music teachers) - along with a strong professional teacher community.

- h. Regulation of Schools: Regulation and operations of schools will be carried out by separate bodies to eliminate conflicts of interest. There will be clear, separate systems for policy making, regulation, operations and academic matters.

### **Higher Education**

- a. New architecture: A new vision and architecture for higher education has been envisaged with large, well-resourced, vibrant multidisciplinary institutions. The current 800 universities and 40,000 colleges will be consolidated into about 15,000 excellent institutions.
- b. Liberal education: A broad-based liberal arts education at the undergraduate level for integrated, rigorous exposure to science, arts, humanities, mathematics and professional fields will be put in place. This would have imaginative and flexible curricular structures, creative combinations of study, integration of vocational education and multiple entry/exit points.
- c. Governance: Institutional governance will be based on autonomy - academic, administrative and financial. Each higher education institution will be governed by an Independent Board.
- d. Regulation: Regulation will be 'light but tight' to ensure financial probity and public- spiritedness - standard setting, funding, accreditation, and regulation will be conducted by independent bodies to eliminate conflicts of interest.

### **Teacher Education**

Teacher preparation programmes will be rigorous and will take place in vibrant, multidisciplinary higher education institutions. The 4-year integrated stage-specific, subject- specific Bachelor of Education offered at multidisciplinary institutions would be the predominant way of becoming a teacher. Substandard and dysfunctional teacher education institutes will be shut down.

### **Professional Education**

All professional education will be an integral part of the higher education system. Stand-alone technical universities, health science universities, legal and agricultural universities, or institutions in these or other fields, will be discontinued.

## **Vocational education**

This will be an integral part of all education - this Policy aims to provide access to vocational education to at least 50% of all learners by 2025.

## **National Research Foundation**

A new entity will be set up to catalyze and expand research and innovation across the country.

## **Technology in education**

This Policy aims at appropriately integrating technology into all levels of education to improve classroom processes, support teacher professional development, enhance educational access for disadvantaged groups and streamline educational planning, administration and management.

## **Adult Education**

This Policy aims to achieve 100% youth and adult literacy by 2030.

## **Promotion of Indian languages**

The Policy will ensure the preservation, growth, and vibrancy of all Indian languages.

## **Financing Education**

There will be substantial public investment to expand and vitalize public education.

## **Rashtriya Shiksha Aayog**

Rashtriya Shiksha Aayog or National Education Commission will be formed, headed by the Prime Minister - this will be the custodian of the vision of education in India.

## Policy Details - Key Points

### School Education

#### 1. Strengthening Early Childhood Care and Education

**Objective:** Every child in the age range of 3-6 years has access to free, safe, high quality, developmentally appropriate care and education by 2025.

The Policy emphasizes the criticality of early childhood education and the persistence of its advantages throughout an individual's life.

- a. Significant expansion and strengthening of facilities for early childhood education will happen through a multi-pronged approach contingent on local needs, geography and existing infrastructure.
- b. Special attention and priority will be given to districts/locations that are particularly socio-economically disadvantaged. Processes for suitable monitoring of quality and outcomes will be set up.
- c. A curricular and pedagogical framework for early childhood education intended for both educators and parents, will be developed. The Framework will comprise guidelines for appropriate cognitive stimulation of 0-3 year olds and educational guidelines for 3-8 year olds.
- d. Design of learner-friendly environments and the professionalization of high-quality educators for early childhood education through stage-specific training, mentoring and opportunities for continuous professional development and career mapping will also be undertaken.
- e. All aspects of early childhood education will come under the purview of the Ministry of Education (as the current Ministry of Human Resource Development will be renamed), effectively linking early childhood education with the rest of school education - a transition plan will be finalized jointly by 2019 by the Ministries of Education, Women and Child Development, and Health and Family Welfare.
- f. An effective quality regulation or accreditation system will be instituted to cover all pre- school education (private, public and philanthropic) to ensure compliance.
- g. Demand will be generated from stakeholders through large-scale advocacy and wide-scale dissemination of information to enable parents to actively support their children's learning needs.

- h. The Right to Education Act 2009 will be extended to assure availability of free and compulsory quality education for all 3–6 year olds.

## 2. **Ensuring foundational literacy and numeracy among all children**

**Objective:** By 2025, every student in Grade 5 and beyond has achieved foundational literacy and numeracy.

The Policy recognizes the severe learning crisis with respect to early language and mathematics and accords it the highest priority.

- a. Nutrition and learning are inextricably linked. The midday meal programme will be expanded - both a nutritious breakfast and a midday meal will be provided to pre-primary and primary school students. Expenditure on the programme will be linked to food costs and inflation to ensure the quality of the food served.
- b. There will be an increased focus on foundational literacy and numeracy in Grades 1-5, along with a robust system of adaptive assessment and availability of quality materials. A national repository of language and mathematics resources will be available on the National Teacher's Portal.
- c. Technological interventions to serve as aids to teachers will be piloted, and public and school libraries expanded to build a culture of reading and communication.
- d. All Grade 1 students will undergo a three-month long school preparation module.
- e. Teacher education will be redesigned to have a renewed emphasis on foundational literacy and numeracy.
- f. A National Tutors Programme (comprising peer tutors) and a Remedial Instructional Aides Programme (drawing instructors from the community) will be launched.
- g. A pupil-teacher ratio under 30:1 will be ensured at the level of each school.
- h. Social workers and counsellors will help ensure retention and mental health of all children, parental participation and mobilization of the local community and volunteers will be leveraged to ensure the Policy goals related to foundational literacy and numeracy are met.

## 3. **Ensuring universal access to and retention in education at all levels**

**Objective:** Achieve access and participation in free and compulsory quality

school education for all children in the age group of 3-18 years by 2030. While noting the progress in enrollment, the Policy expresses concern at our inability to retain children in school.

- a. 100% Gross Enrolment Ratio in pre-school through secondary school by 2030 is to be met through various measures.
- b. Access gaps will be met through increasing intake in existing schools, developing new facilities in under/unserved locations and school rationalization supported through transport and hostel facilities, while ensuring safety of all students, particularly girls.
- c. Participation and learning of all children will be ensured through tracking attendance and learning outcomes of enrolled children, tracking drop-outs and out-of-school children by teachers, social workers and counsellors, and programmes for long-term out-of-school adolescents. Multiple pathways to learning, involving formal and non-formal modes, will be available with strengthening of the open and distance schooling and technology platforms.
- d. In case of students being unable to attend school due to health issues, measures to ensure they return to school as soon as possible will include hiring health workers in schools, generating awareness among students, parents and the community-at-large, and connecting them to appropriate health services.
- e. The requirements of the Right to Education Act will be made substantially less restrictive, while ensuring safety (physical and psychological), access and inclusion, the non-profit nature of schools, and minimum standards for learning outcomes. This is to allow for local variations and alternative models, while making it easier for governmental and non-governmental organizations to start a school.
- f. The Right to Education Act will be extended to assure availability of free and compulsory education from pre-school through Grade 12.

#### 4. **New curricular and pedagogical structure for school education**

**Objective:** Curriculum and pedagogy are transformed by 2022 in order to minimize rote learning and instead encourage holistic development and 21st century skills such as critical thinking, creativity, scientific temper,

communication, collaboration, multilingualism, problem solving, ethics, social responsibility, and digital literacy.

The curricular and pedagogical structure of school education will be reconfigured to make it responsive and relevant to the developmental needs and interests of learners at different stages of their development.

- a. The curricular and pedagogical structure and the curricular framework for school education will therefore be guided by a 5+3+3+4 design:
  - ❖ Foundational Stage (age 3-8 years): Rapid brain development; learning based on play and active discovery
  - ❖ Preparatory Stage (8-11 years): Building on play and discovery; begin the transition to structured learning
  - ❖ Middle Stage (11-14 years): Learning concepts in subjects; begin navigating adolescence
  - ❖ Secondary Stage (14-18 years): Preparation for livelihood and higher education; transition into young adulthood
- b. The Secondary Stage will comprise four years of multidisciplinary study and will build subject depth, critical thinking, attention to life aspirations with flexibility for student choice.
- c. The content and process of school education will be reoriented to develop holistic learners. The curriculum load will be reduced to key concepts and essential ideas, thus enabling space for deeper and more experiential learning.
- d. All students will be encouraged to develop proficiency in languages, scientific temper, sense of aesthetics and art, communication, ethical reasoning, digital literacy, knowledge of India and knowledge of critical issues facing local communities, the country, and the world.
- e. A flexible curriculum - with no hard separation of curricular, co-curricular or extra-curricular areas; nor of arts and sciences, and 'vocational' and 'academic' streams - will enable student choice with the possibility of switching subject areas at the secondary school level.
- f. Education will be in the local language/mother tongue at least till Grade 5 but preferably till Grade 8, with a flexible (bilingual) language approach where necessary.

- g. High quality textbooks will be made available in local languages as needed and feasible, and materials will be developed for students with disability.
- h. The three-language formula will be implemented in spirit throughout the country; special measures will be taken to develop and recruit language teachers.
- i. Vocational exposure will begin early with all students taking a year-long survey course on vocational skills and crafts in Grades 6-8. In Grades 9-12, children will have access to vocational courses along with more traditional academic courses, with students having choice to 'mix and match'.
- j. The National Curriculum Framework will be revisited and revised by end-2020, and made available in all regional languages. New textbooks will be developed and high quality translations will be done.
- k. Assessment will be transformed to support student development. All examinations (including Board examinations) will test core concepts and skills, along with higher order capacities. By 2025, assessment at middle school level and above will be through adaptive computerized testing. From 2020/2021 onwards, the autonomous National Testing Agency will administer aptitude tests and tests in various subjects, which can be taken on multiple occasions during the year.
- l. Singular talents and interests will be identified and fostered through topic-centered and project-based clubs from school to district levels, residential summer programmes, and Olympiads and competitions.

#### 5. **Teachers – Torchbearers of change**

**Objective:** Ensure that all students at all levels of school education are taught by passionate, motivated, highly qualified, professionally trained and well equipped teachers.

This Policy envisages teachers as the 'most important members of our society and the torchbearers of change.' The success of any effort to foster quality education is dependent upon the quality of the teacher.

- a. Merit-based scholarships will be instituted to enable outstanding students from underprivileged, rural or tribal areas to undertake the

four-year integrated B.Ed. programme. In certain cases, employment will be guaranteed in their local areas. Female students will be targeted in particular.

- b. Recruitment of teachers will be done through a robust process based on comprehensive teacher requirement planning at all schools, with preference given to local teachers and those fluent in the local language, while ensuring diversity. The first step would be a redesigned Teacher Eligibility Test, followed by an interview and teaching demonstration. Teachers will be recruited to the district, as is done now in many States, and appointed to a school complex, and must ideally have a fixed tenure and rule-based transfers through a transparent technology-based system. They will be incentivized to teach in rural areas.
- c. The practice of 'para-teachers' (unqualified, contract teachers) will be stopped across the country by 2022.
- d. Continuous teacher professional development will be based upon a flexible and modular approach, with teachers choosing what they want to learn and how they want to learn it. Attention will be paid to induction of beginning teachers, and processes of mentoring put in place. States should adopt a technology-based system for enabling choice-based professional development and to track the professional trajectory of each teacher. There will be no centralized determination of the curriculum, no cascade-model training and no rigid norms. The resource people for delivering these programmes will be carefully selected, effectively trained and will have tenure in the role.
- e. Adequate physical infrastructure, facilities and learning resources, along with desired pupil-teacher ratio will be ensured to facilitate teachers' work. Remedial programmes will be established at all levels to help teachers ensure that all students learn.
- f. All teachers must be able to teach with no interruptions in the form of non-teaching activities during school hours (e.g. cooking midday meals, procuring school supplies, etc.). In turn, teachers will be held accountable for being absent from school without cause or without being on approved leave.

- g. Each head teacher and/or school principal will be responsible for building strong in- school development processes and a supportive school culture. The School Management Committee will be sensitized, and officials of the Directorate of School Education will reorient their functioning to support such a culture.
- h. High-quality material for teachers and teacher educators in Indian languages will be accorded priority in order to ensure the inclusion of all students.
- i. Rejuvenating academic support institutions with a careful plan to strengthen all existing academic support institutions will be accorded priority.
- j. All teachers will be able to move into either educational administration or teacher education after a minimum number of years of teaching experience. In the long term, all educational administrative positions will be reserved for outstanding teachers who are interested in administration.

**6. Equitable and inclusive education for every child in the country This policy aims to shape an education system that benefits all of India's children so that no child loses any opportunity to learn and excel because of the circumstances of birth or background.**

**Objective:** Achieve an inclusive and equitable education system so that all children have equal opportunity to learn and thrive, and so that participation and learning outcomes are equalized across all genders and social categories by 2030.

- a. Policy actions related to early childhood education, foundational literacy and numeracy, school access, enrolment and attendance will receive targeted attention and support for students from under-represented groups.
- b. Special Education Zones will be set up in disadvantaged regions across the country. States will be encouraged to declare these Zones based on clear social development and socio-economic indicators and the Central Government will provide financial support in the ratio of 2:1 for every rupee spent by the State. The key idea will be to have these Zones act

upon all that is stated in this Policy for inclusion of under-represented groups in a concerted manner, with close joint monitoring by the Centre and States.

- c. Some key initiatives are capacity development of teachers by continuously sensitising them, creating alternate pathways for recruitment of teachers from educationally under-represented groups, restricting the pupil-teacher ratio in schools with a high proportion of learners from educationally under-represented groups to not more than 25:1, creation of inclusive school environments through establishment of mechanisms which address harassments, intimidations and gender-based violence and eliminate exclusionary practices, revising curriculum to make it inclusive.
- d. Up to date information for each student will be maintained in the National Repository of Educational Data, with data analysis undertaken by the Central Educational Statistics Division.
- e. The Policy provides for financial support to individual students through a National Fund created specifically for providing scholarships, developing resources and facilities for students from under-represented groups and targeted funding and support for inclusion and access to districts and institutions as well. Alternative means of support include recruitment into the National Tutors Programme and the Remedial Instruction Aides Programme, breakfast in addition to the midday meal, and special internship opportunities. Funding will also be provided for research on inclusive education.
- f. Women's participation and education of girls to address the gender imbalance among school teachers and girls students, education of tribal, caste and religion-based groups to ensure that children of these communities receive all the benefits earmarked for them, education of children of urban poor families in order to help students to navigate life in urban poor areas and education of children with special needs as well as transgender children with continued and renewed focus to mainstream children in neighbourhood schools from foundational stage to Grade 12 are other illustrative interventions in this Policy.

## 7. Governance in school education through school complexes

**Objective:** Schools are grouped into school complexes to facilitate the sharing of resources and render school governance more local, effective, and efficient.

The establishment of school complexes will aid in mitigating many resource crunch problems that public schools, particularly small schools, currently face. As multiple public schools will be brought together into a single organizational and administrative unit, without requiring physical relocation of schools, it will aid in creating effective administrative units without compromising access barriers to students.

- a. State governments will group schools into complexes according to population distribution, connectivity and other local considerations by 2023. The grouping exercise will also include review and consolidation of schools with very low enrolment (e.g. <20 students). At the same time, access will not be impacted in the process through measures such as provision of transport. This will also be an opportunity for States to assess the status of existing schools.
- b. School complexes will break the isolation of small schools, and create a community of teachers and principals who can work together and support each other - academically and administratively. The school complex will be the primary administrative unit of the public school system.
- c. A school complex will comprise a cluster of approximately 10-20 public schools offering education from the initial Foundational stage through Grade 12 within a connected/contiguous geographic region. The Principal of the secondary school will be the head of the school complex.
- d. Each school complex will be a semi-autonomous unit that will offer education from the Foundational stage till Grade 12 consisting of one secondary school (Grade 9-12) and all the public schools imparting basic/preparatory and middle school education in its neighbourhood.
- e. The grouping of schools into school complexes will enable sharing of resources across schools including subject teachers, sports, music and art teachers, counsellors and social workers. It will also entail a well-

organized sharing of physical resources such as laboratories, libraries, ICT equipment, musical instruments, sports equipment, sports fields, etc. leading to optimum utilization of public resources facilities.

- f. The aim is to create a coherent set of educational facilities, including schools offering initial three years of foundational education, institutions offering vocational education and adult education, teacher support institutions and support for children with special needs that are located within a well-connected geographical area and can support each other in their work. The higher education institute in the district will also provide support (e.g. supporting teacher professional development).
- g. A comprehensive Teacher Development Plan will be drawn up for each complex, and peer learning communities will be consciously developed and sustained through processes such as weekly meetings, teacher learning centres. In addition, other modes of continuing professional development will be provided, such as seminars, in-class mentoring, exposure visits, etc. The academic and teacher support system, including the District Institutes of Education and Training, and the Block and Cluster Resource Centres, will be aligned to the school complex system.
- h. Each school complex will have a School Complex Management Committee comprising representatives from all the schools in the complex, as well as other institutions attached to the complex, including the adult education centre, cluster resource centre, and so on. The Committee will be empowered to have a voice to intervene on behalf of the school with the State and its bodies. It will also play a central role in the performance management of teachers.
- i. Individual schools will develop their plans, which will be used to evolve the plan of the school complex, which in turn will be endorsed by the Department of School Education. Each district will also have a District Education Council/Zilla Shiksha Parishad for both the oversight of the school system and to enable their functioning and empowerment.

## 8. Regulation of school education

**Objective:** India's school education system is invigorated through effective regulation and accreditation mechanisms that ensure integrity and

transparency, and foster quality and innovation for continually improving educational outcomes.

Regulation must become an engine of educational improvement and energize India's school education system.

- a. Regulation and operations of schools (service provision) will be carried out by separate bodies to eliminate conflicts of interest. There will be clear, separate systems for policymaking, regulation, operations and academic matters.
- b. An independent State-wide regulatory body called the State School Regulatory Authority, with a quasi-judicial status, will be created for each State, while the operations of the public schooling system of the whole State will be handled by the Directorate of School Education.
- c. Regulation will be based on a system of accreditation informed by a School Quality Assessment and Accreditation Framework. The Framework will address only basic parameters, and in turn will inform the License to Start a School. While schools will self-accredit, a mechanism of audit will be set up. This process will apply to both public and private schools.
- d. Enforcement of regulation will not be driven by the current inspectorial approach; instead, parents will become de facto regulators by virtue of all relevant information related to schools being in the public domain.
- e. Academic matters including standards setting and curricula in the State, will be led by the State Council of Educational Research and Training. Certification of competencies of students at the school leaving stage will be handled by the Boards of Certification/Examination in the State, which will conduct meaningful examinations for this purpose; however, they will have no role in determining the curricula (including the text books).
- f. Private philanthropic schools must be encouraged and freed of regulatory overload; at the same time private operators who try to run schools as commercial enterprises will be stopped.
- g. Public and private schools will be regulated on the same criteria, benchmarks and processes, ensuring that public spirited private schools are encouraged along with private philanthropic initiatives.

- h. The State Council of Educational Research and Training will develop a School Quality Assessment and Accreditation Framework for each State. This will be used by the State School Regulatory Authority for its regulation of schools based on a system of accreditation.
- i. Schools and school systems will have the flexibility to choose curricula, which must be aligned with the National/State Curriculum Framework(s).
- j. All bodies and institutions will develop annual as well as mid-term (3-5 years) plans. A systematic review process by the corresponding apex governance body will be put in place.
- k. The sample-based National Achievement Survey of student learning levels will continue to be carried out by the National Council of Educational Research and Training. States may also continue to conduct a census-based State Assessment Survey.
- l. Since the Right to Education is the statutory lynchpin for school regulation and governance, it will be reviewed, and appropriate modifications made to enable this Policy, as also to incorporate improvements based on the learnings since it was enacted.

## Higher Education

### 1. New institutional architecture

**Objective:** Revamp the higher education system, create world class institutions across the country – increase Gross Enrolment Ratio to at least 50% by 2035.

A new vision and architecture for higher education has been envisaged with large, well-resourced, vibrant multidisciplinary institutions. The current 800 universities and 40,000 colleges will be consolidated into about 15,000 excellent institutions.

- a. This new higher education architecture shall create large, well-resourced, vibrant and autonomous multidisciplinary institutions for teaching and research, significantly expanding reach and capacity while building strong educational communities. All higher education institutions will become multidisciplinary institutions, with teaching programmes across disciplines and fields.

- b. There will be three types of institutions based on a difference in focus - all will be of high quality
- ❖ Type 1 which focus on world-class research and high quality teaching across all disciplines
  - ❖ Type 2 which focus on high quality teaching across disciplines with significant contribution to research
  - ❖ Type 3 which focus on high quality teaching across disciplines focused on undergraduate education
- c. This re-structuring will be done systematically and thoughtfully, by consolidating and restructuring existing institutions and building new ones. Mission Nalanda and Mission Takshashila will be launched for catalyzing this new institutional architecture. A few pace-setting institutions, the Indian Institutes of Liberal Arts/ Multidisciplinary Education and Research Universities, may be set up as part of these Missions.
- d. All institutions will be either universities or degree-granting autonomous colleges.
- e. There will be substantial public investment to expand and vitalize public higher education through a fair and transparent system.
- f. Developing high quality institutions in disadvantaged geographical areas will be a priority.
- g. This new institutional architecture will encompass all fields, including professional fields.

## 2. Focus on high quality liberal education

**Objective:** Move towards a more imaginative and broad-based liberal education as a foundation for holistic development of all students, with rigorous specialization in chosen disciplines and fields.

All undergraduate programmes will be characterized by a liberal education approach as the foundation for holistic development through imaginative and flexible curricular structures, creative combinations of disciplines of study, and multiple exit and entry points within integrated programmes, offering rigorous specialization in chosen disciplines and fields.

- a. Liberal education with broad multi-disciplinary exposure, intended to develop Constitutional values, will be the basis of higher education. This will develop important life capacities, rigorous disciplinary understanding and an ethic of social-moral engagement. This will be the approach at the undergraduate level across all disciplines, programmes and fields, including professional and vocational fields.
- b. The Centre will set up ten Indian Institutes of Liberal Arts/ Multidisciplinary Education and Research Universities on the model and standards of the Indian Institutes of Technology.
- c. Imaginative and flexible curricular structures will enable creative combinations of disciplines of study, and offer multiple useful exit and entry points for students, thus demolishing currently prevalent rigid boundaries and creating possibilities for life- long learning. Graduate (masters and doctoral) level education will provide rigorous research-based specialization.
- d. The undergraduate degree may be of 3 or 4 years duration. Institutions may offer multiple exit options within this period, with appropriate certification, an advanced diploma in a discipline or field (including vocational and professional areas) after completing 2 years of study or a certificate after completing 1 year.
- e. The 4-year programme will provide students the opportunity to experience the full range of liberal education. This will be called the Bachelor of Liberal Arts in the chosen major and minors. The 3-year programme will lead to a Bachelors' degree. Both programmes may lead to a degree 'with honours,' if the students does research work.
- f. Certain professional streams (e.g. teacher education, engineering, medicine, law) may only have a 4-year duration (or more) for the undergraduate degree.
- g. Institutions will have the flexibility to offer different designs of Master's programmes, e.g., there may be 2-year programme with the second year devoted entirely to research, for those who have completed the 3-year undergraduate programme; there may be an integrated 5-year Master's programme; and for students completing a 4- year undergraduate degree with honours, there could be a 1-year Master's programme.

- h. Undertaking a PhD shall require either a Master's degree or a 4-year undergraduate degree with honours. The M.Phil. programme shall be discontinued.

### 3. **Creating a conducive learning environment**

**Objective:** Ensure a joyful, rigorous and responsive curriculum, engaging and effective pedagogy, and caring support to optimize learning and the overall development of students.

Curriculum and pedagogy in higher education will move away from rote learning of facts and mechanical procedures to help enable young people to contribute both as active citizens of a democracy and as successful professionals in any field.

- a. The development of vibrant and rigorous curricula will be guided by the National Higher Education Qualifications Framework, which will outline the learning outcomes associated with the degree/diploma/certification offered in various fields and disciplines. This Framework will be aligned with the National Skills Qualifications Framework to ensure equivalence and mobility across academic and professional/vocational fields.
- b. The Choice Based Credit System will be revised and improved to allow for flexibility and innovation.
- c. Stimulating learning experiences will be offered through effective pedagogical practices; all students will also be offered meaningful opportunities for social engagement. Students will be assessed not only on academic aspects but also on broad capacities and dispositions.
- d. Academic, financial and emotional support will be available for students to help them attain better outcomes.
- e. Open and distance learning will be expanded, thus playing a significant role in increasing the Gross Enrolment Ratio to 50%. Measures such as online digital repository, funding for research, improved student services, credit-based recognition of MOOCs, etc. will be taken to ensure it is at par with the highest quality in-class programmes.
- f. Internationalization of education will be facilitated through both institutional collaborations, and student and faculty mobility. An Inter-

University Centre for International Education will be set up within selected Indian universities.

#### 4. **Energized, engaged and capable faculty**

**Objective:** Empowered faculty with high competence and deep commitment, energized for excellence in teaching and research.

The most important factor for the success of higher education institutions is the quality and engagement of its faculty. This Policy puts faculty back into the heart of higher education.

- a. Every institution will have adequate faculty, ensuring that all programme, subject and field needs are met, a desirable student-teacher ratio (not more than 30:1) is maintained and diversity is ensured.
- b. The prevalent approach of ad hoc, contractual appointments will be immediately stopped.
- c. Faculty recruitment will be based on academic expertise, teaching capacities and dispositions for public service.
- d. An appropriately designed permanent employment (tenure) track system for faculty will be introduced - this will be fully functional in all institutions, including private institutions, by 2030.
- e. Faculty will be empowered to make curricular choices for their courses and pursue research with academic freedom
- f. All institutions will develop a continuous professional development plan for faculty and determine the process for its implementation. The plan should include capacity development in the field/discipline, pedagogical capacities, research and contribution to practice.
- g. Faculty recruitment and development, career progression, compensation management to be part of the Institutional Development Plan of every institution.

#### 5. **Empowered governance and autonomy**

**Objective:** Independent, self-governed higher education institutions with capable and ethical leadership.

High quality education and research requires intellectual ferment in a nurturing culture-the governance of higher education institutions determines this culture.

- a. Higher education institutions will be governed by Independent Boards, with complete academic and administrative autonomy. The formation and appointment of the Board, the Chair and the Vice Chancellor/Director (Chief Executive) will ensure elimination of external interference, including from the government, and will enable the engagement of high-capacity people with commitment to the institution.
- b. All higher education institutions will become autonomous self-governing entities and the practice of 'affiliation' will be stopped. 'Affiliated colleges' will be supported to develop into autonomous degree granting colleges and 'affiliating universities' will develop into vibrant multidisciplinary institutions.
- c. Private and public institutions will be treated at par by the regulatory regime. Commercialization of education will be stopped, and philanthropic efforts encouraged.
- d. Autonomy will be ingrained in the system - its culture, structure and mechanisms. Faculty will have academic freedom and curricular empowerment, including on pedagogical approaches, student assessment and research. Institutions will have administrative and academic autonomy. This will include the freedom to start and run programmes, decide curricula, decide student capacity, decide resource requirements and develop their internal systems, including governance and people management systems. Higher education institutions will be developed truly into autonomous, independent and self-governing entities.

#### 6. Transformation of the Regulatory System

Objective: Effective, enabling and responsive regulation to encourage excellence and public-spiritedness in higher education.

Regulation will be responsive and minimalistic to ensure public spiritedness, equity, excellence, financial stability and probity, along with good governance.

- a. The functions of standard setting, funding, accreditation and regulation will be separated and conducted by independent bodies, eliminating concentration of power and conflicts of interest.
- b. The National Higher Education Regulatory Authority will be the only regulator for all higher education, including professional education. All

current regulatory bodies will transform into Professional Standard Setting Bodies.

- c. The current University Grants Commission will transform to the Higher Education Grants Council.
- d. The General Education Council will be set up, and will develop the National Higher Education Qualifications Framework to define 'graduate attributes', that is, 'expected learning outcomes' for higher education.
- e. Accreditation on basic parameters will form the basis for regulation. The National Assessment and Accreditation Council will develop an ecosystem of Accreditation Institutions and oversee the process.
- f. There will be a common regulatory regime for public and private higher education institutions. Private philanthropic initiative will be encouraged.
- g. State Departments of Higher Education will be involved at a policy level; State Councils of Higher Education will facilitate peer support and best practice sharing.

## Teacher Education

### 1. Rigorous teacher preparation

**Objective:** Ensure that teachers are given the highest quality training in content, pedagogy and practice, by moving the teacher education system into multidisciplinary colleges and universities, and establishing the four-year integrated Bachelor's Degree as the minimum qualification for all school teachers

Teaching is an ethically and intellectually demanding profession. New teachers need rigorous preparation and practicing teachers need continuous professional development and academic and professional support.

- a. The 4-year integrated Bachelor of Education programme for teacher preparation will be offered at multi-disciplinary institutions as an undergraduate programme of study, including both disciplinary and teacher preparation courses. This will be a stage-specific, subject-specific programme that will prepare teachers from pre-school to the secondary stage (Class 12) for all subjects including the arts and sports and those with a vocational education or a special education focus.

- b. The 4-year B.Ed. degree will be on par with other undergraduate degrees and students with a 4-year B.Ed. will be eligible to take up a Master's degree programme.
- c. The current two-year B.Ed. programme will continue till 2030. After 2030, only those institutions which offer a 4-year teacher education programme will run the 2-year programme as well. These programmes will be offered to those with a graduate degree.
- d. No other kind of pre-service teacher preparation programmes will be offered after 2030.
- e. Teacher education will be offered by multi-disciplinary institutions only. Good pre-service teacher preparation needs expertise across disciplines for rigorous theoretical understanding of educational perspectives, subject and pedagogy along with a strong theory-practice connect - this demands the availability of a range of experts in core areas of education and all other school subjects along with a network of schools.
- f. Substandard and dysfunctional teacher education institutes will be shut down.

## Professional Education

1. Reintegrating professional education into higher education, Revitalizing professional education

Objective: Build a holistic approach to the preparation of professionals, by ensuring broad-based competencies and 21st century skills, an understanding of the social-human context, and a strong ethical compass, in addition to the highest-quality professional capacities.

Preparation of professionals must involve an education in the ethic and importance of public purpose, an education in the discipline, and an education for practice - for this to happen, professional education must not happen in the isolation of speciality.

- a. Professional education will be an integral part of the overall higher education system. The practice of setting up stand-alone technical universities, health science universities, legal and agricultural universities, or institutions in these or other fields, will be discontinued. All institutions

offering either professional or general education must organically evolve into institutions offering both seamlessly by 2030.

- b. Agricultural education with allied disciplines will be revived. Although Agricultural Universities comprise approximately 9% of all universities in the country, enrolment in agriculture and allied sciences is less than 1% of all enrolment in higher education. Both capacity and quality of agriculture and allied disciplines must be improved in order to increase agricultural productivity through better skilled graduates and technicians, innovative research and market-based extension linked to technologies and practices. Capacity to prepare professionals in agriculture and veterinary sciences through programmes integrated with general education will be increased sharply. The entire design of agricultural education shall be changed to develop professionals with the ability to understand and use local knowledge, traditional knowledge and emerging technologies while being cognizant of critical issues like declining land productivity, climate change, food sufficiency for our growing population, etc. Institutions offering agricultural education must benefit the local community directly; one approach could be to set up Agricultural Technology Parks to promote technology incubation and dissemination.
- c. Legal education programmes will be restructured. Professional education in law must be globally competitive, adopting best practices and embracing new technologies for wider access to justice and timely delivery of justice. At the same time, it must be informed and illuminated with Constitutional values of Justice - Social, Economic and Political - and directed towards national reconstruction through instrumentation of democracy, rule of law and human rights. The curricula for legal studies must reflect socio-cultural contexts along with, in an evidence-based manner, the history of legal thinking, principles of justice, practice of jurisprudence and other related content appropriately and adequately.

State institutions offering law education must consider offering bilingual education for future lawyers and judges - in English and in the language of the State in which the law programme is situated. This is to alleviate delay in legal outcomes consequent to need for translation.

- d. Healthcare education shall be re-envisioned such that the duration, structure and design of the educational programmes is as much as is required for the roles that people play. For example, every healthcare process/intervention (e.g. taking/reading an ECG) does not necessarily need a fully qualified doctor. All MBBS graduates must possess: (i) Medical skills (ii) Diagnostic skills (iii) Surgical skills and (iv) Emergency skills. Students will be assessed at regular intervals on well-defined parameters primarily for the skills required for working in primary care and in secondary hospitals. The first year or two of the MBBS course will be designed as a common period for all science graduates after which they can take up MBBS, BDS,

Nursing or other specialisations. Graduates from other medical disciplines such as nursing, dental, etc., will also be allowed lateral entry into the MBBS course: a medical education qualification framework will facilitate this. Quality of nursing education will be improved; a national accreditation body for nursing and other sub-streams will be created. Given that our people exercise pluralistic choices in healthcare, our healthcare education system must be integrative - this would mean, illustratively, that all students of allopathic medical education must have a basic understanding of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy

(AYUSH), and vice versa. There shall also be a much greater emphasis on preventive healthcare and community medicine in all of healthcare education.

- e. Technical education faces specific challenges as these disciplines are neither entirely knowledge based nor are they entirely skill based. Further, as the influence of technology on all human endeavour grows, the silos between technical education and other disciplines are expected to erode. Going ahead, not only will these sectors continue to demand well-qualified individuals for several decades, but there will be greater need for closer collaboration between industry and institutions to drive innovation and research. Engineering and technology programmes will be revised to prepare professionals who are well prepared for both current and future practices, and are able to exploit emerging science

and technology while being responsive to changing socio-economic and environmental contexts. Curriculum will be renewed to develop among students the ability to apply their knowledge and skills in different, often unknown, settings, and inculcating professional dispositions and ethics. There will be a strategic thrust on new and emerging disciplines, e.g. artificial intelligence, big data analysis, etc.

Accreditation/ranking of institutions will incentivize collaboration with industry, faculty with industry experience, enhanced internship opportunities, etc.

## **National Research Foundation**

### **1. Catalyzing Quality Academic Research**

**Objective:** Catalyze and energize research and innovation across the country in all academic disciplines, with a special focus on seeding and growing research at universities and colleges – create a conducive ecosystem for research through competitive peer-reviewed funding, mentoring and facilitation.

Research and innovation are central to growing and sustaining a large and vibrant economy, uplifting society, and inspiring a nation to achieve greater heights. The rapid changes occurring in the world today - climate, technology, population dynamics and so on - make a robust research system more important than ever.

- a. The National Research Foundation will be set up through an Act of Parliament, as an autonomous body of the Government of India. It will be given an annual grant of Rs. 20,000 crores (~ 0.1% of GDP); this will be increased progressively over the next decade as the country's capacity for quality research is developed.
- b. The primary scope of work of the Foundation will include:
  - ❖ Funding research in all disciplines across the academic landscape through a competitive, peer-review based process.
  - ❖ Building research capacity at academic institutions across the country.
  - ❖ Creating beneficial linkages between researchers, government and industry to ensure that the most urgent national issues are researched

and the latest research breakthroughs are implemented for the public good.

- ❖ Recognizing outstanding research through special prizes and seminars.
- c. The Foundation will have four major divisions to start with - Sciences, Technology, Social Sciences and Arts and Humanities.

## **Additional Key Focus Areas**

### **1. Education Technology**

**Objective:** Appropriate integration of technology into all levels of education - to support teacher preparation and development; improve teaching, learning and evaluation processes; enhance educational access to disadvantaged groups; and streamline educational planning, administration and management.

This Policy aims to see that technology is appropriately integrated into all levels of education for: i) improving teaching, learning, and evaluation processes; ii) supporting the preparation of teachers and their continuous professional development; iii) enhancing educational access to disadvantaged groups and iv) streamlining education planning, administration and management.

- a. The National Educational Technology Forum, an autonomous body will be set up to facilitate decision making on the induction, deployment, and use of technology, by providing to the leadership of educational institutions, state and central governments, and other stakeholders the latest knowledge and research as well as the opportunity to consult and share best practices with each other.
- b. Technology integration into educational processes (e.g. support translation, act as a pedagogical aid, facilitate continuing professional development, online courses, etc.) will be optimized through digital repositories, teacher preparation to use technology, qualified support and research. Centres of Excellence in Educational Technology will be set up to undertake research and support use of technology.
- c. The National Repository of Educational Data will maintain all records related to institutions, teachers and students in digital form.

## 2. Vocational Education

**Objective:** Integrate vocational education into all educational institutions - schools, colleges and universities. Provide access to vocational education to at least 50% of all learners by 2025.

This Policy sets a goal of achieving skill development among at least 50% of learners through the school and higher education system by 2025, in order to realize the full potential of India's demographic dividend.

- a. Vocational education will be integrated into all education institutions in a phased manner over the next decade. Focus areas will be chosen based on skills gap analysis and mapping of local opportunities, and technical and vocational education will be part of the larger vision of liberal education. The National Committee for the Integration of Vocational Education will oversee the effort.
- b. This transition will be facilitated through collaboration between educational institutions and technical institutions and industry, through a separate fund for integration.
- c. The National Skills Qualifications Framework will be detailed further for each of the disciplines/vocations/professions. Further, Indian standards will be aligned with the International Standard Classification of Occupations maintained by the International Labour Organization. The Framework will provide the basis for Recognition of Prior Learning. Through this, dropouts from the formal system will be reintegrated by aligning their practical experience with the relevant level on the Framework. The Framework will also facilitate mobility across general and vocational education.
- d. Vocational education at the undergraduate level will be scaled up to a capacity of 50% of enrolment by 2030-35. Higher education institutions can offer vocational education either on their own or in partnership with industry.
- e. Models of offering vocational education, and apprenticeship, can also be experimented with by higher education institutions. Incubation centres will be set up in higher education institutes in partnership with industries.

- f. 'Lok Vidya', knowledge developed in India, will be made accessible to students through integration into vocational education courses.

### 3. **Adult Education**

**Objective:** Achieve 100% youth and adult literacy rates by 2030, and significantly expand adult and continuing education programmes.

Literacy and basic education enable participation in personal, civic, economic and life-long learning opportunities-it is the right of each citizen. However, an unacceptable proportion of our youth and adult population still remains non-literate.

- a. A National Curriculum Framework for Adult Education will be developed to cover five broad areas - foundational literacy and numeracy, critical life skills, vocational skills, basic education and continuing education. Textbooks and learning materials, alongwith criteria for assessment and certification will be developed aligned to this Framework.
- b. A cadre of Adult Education Centre managers and instructors, as well as a large team of one-on-one tutors created through the National Adult Education Tutors Programme will be capacitated to deliver adult education.
- c. Existing approaches and programmes will be leveraged to identify participants, community volunteers will be encouraged - each literate member of the community to teach at least one person to read will be a key strategy. Large scale public awareness will be generated. There will be special emphasis on women's literacy.

### 4. **Promotion of Indian Languages**

**Objective:** Ensure the preservation, growth, and vibrancy of all Indian languages.

True inclusion and preservation of culture and traditions of each region, and true understanding by all students in schools, can be achieved only when suitable respect is given to all Indian languages, including tribal languages. It is thus absolutely critical to preserve the truly rich languages and literatures of India.

- a. Focus on language, literature, scientific vocabulary in Indian languages will be enabled through strong Indian language and literature

programmes across the country, recruitment of teachers and faculty, focused research, and promotion of classical languages.

- b. Existing national institutes for promotion of classical languages and literature will be strengthened. A National Institute for Pali, Persian and Prakrit will also be set up.
- c. The mandate of the Commission for Scientific and Technical Terminology, namely to develop a vocabulary for uniform use across the country, will be renewed and vastly expanded to include all disciplines and fields, and not just the physical sciences.

## **Rashtriya Shiksha Aayog**

### **1. Transforming Education: Rashtriya Shiksha Aayog**

**Objective:** Synergistic functioning of India's education system, to deliver equity and excellence at all levels, from vision to implementation, led by a new Rashtriya Shiksha Aayog.

The Indian education system needs inspiring leadership which will also ensure excellence of execution.

- a. The Rashtriya Shiksha Aayog or the National Education Commission will be constituted as an apex body chaired by the Prime Minister.
- b. The Union Minister of Education shall be the Vice Chairman with direct responsibilities related to day-to-day matters.
- c. The Aayog will comprise eminent educationists, researchers, Union Ministers, a representation of Chief Ministers of States and eminent professionals from various fields. All members of the Aayog will be people with high expertise and record of public contribution in their fields, and will be people with unimpeachable integrity and independence.
- d. The Aayog will be the custodian of education in India. It will champion an integrated national vision of education while nurturing the diversity of our society. It will facilitate effective and synchronized vision and action from all concerned actors and leaders across national, State, and institutional levels.
- e. The Aayog will work closely with every State to ensure coordination and synergy. States may set up apex State level bodies for education which may be called the Rajya Shiksha Aayog or the State Education Commission.

## Financing Education

### 1. Financing Education

- i. This Policy commits to raising educational investment as it believes that there is no better investment towards a society's future as the benefits of education accrue to society as a whole.
- ii. The Policy, therefore, envisions an increase in public investment on education, by both the Central government and all State Governments, to 20%, over a 10 year period.
- iii. Financial support will not be compromised for important components such as learning resources, matters of student safety and well-being, nutritional support, adequate staffing, teacher development and support for all initiatives to ensure equitable high quality education for underprivileged and under represented groups.
- iv. The Policy calls for the rejuvenation, active promotion and support for private philanthropic activity in the education sector. All public-spirited funding on a not-for-profit basis for any educational endeavor will be channelized towards critical needs of existing institutions.
- v. In addition to one-time expenditure, primarily related to infrastructure and resources, this Policy identifies the following key thrust areas: (i) expansion and improvement of early childhood education, (ii) ensuring foundational literacy and numeracy, (iii) adequate and appropriate resourcing of school complexes, (iv) food and nutrition (breakfast and midday meal), (v) teacher education and continuing professional development of teachers, (vi) revamping colleges and universities, and (vii) research.
- vi. Governance and management will focus on the smooth, timely and appropriate flow of funds, and their usage with probity. This will be enabled by clear separation of roles, empowerment and autonomy to institutions, appointment of people to leadership roles, and enlightened oversight.
- vii. The matter of commercialization of education has been dealt by the Policy through multiple relevant fronts, including the 'light but tight'

regulatory approach, the substantial investment in public education, and by mechanisms for good governance including transparent public disclosure.

## 2. **Way Forward**

The Policy outlines key actions led by various bodies, along with timelines and a plan for review, to ensure that the Policy is implemented in its spirit and intent, through coherence in planning and synergy across all bodies involved in education.

In every epoch of humankind, knowledge represents the sum of what is created by all previous generations, to which the present generation adds its own.

The motif of the Mobius strip symbolizes the perpetual, developing and live nature of knowledge - that which has no beginning and that which has no end.

This Policy envisages creation, transmission, use and dissemination of knowledge as a part of this continuum.

## **New National Education Policy 2022 नई शिक्षा नीति What is NEP 5+3+3+4 Structure**

National Educational Policy (NEP): Union Cabinet paved the way for transformative reform in school and higher education system by launching the New National Education Policy (NEP) on 29<sup>th</sup> July 2020. They also renamed MHRD as Ministry of Education. After the old national education policy which was launched way back in 1986, this is the first education policy of 21<sup>st</sup> century that has **replaced 34 years old education policy**. The new NEP is based on four pillars which are **Access, Equity, Quality, and Accountability**. In this new policy, there will be a 5+3+3+4 structure which comprises 12 years of school and 3 years of Anganwadi/ pre-school replacing old 10+2 structure.

### **NEP 2022 Timeline**

UGC Chairman said that the due to COVID-19 pandemic affected the implementation of NEP but they assure that once the condition normalizes then it will be implemented at a faster pace.

By 2030 the minimum education qualification for teaching will be a 4 year integrated B.Ed course.

Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank said that they have no plan to revise the reservation norms under NEP.

Meghalaya Chief Minister said that they will form a task force for the implementation of New Education Policy and after the constitution of such force Meghalaya will become the first state in the country that will implement this NEP.

### **New National Educational Policy 2020**

Through this new education scheme, they are trying to bring more than 2 crore students into the mainstream and with the help of this, they aim to achieve 100% GER (Gross enrollment ratio) from pre-school to secondary by the end of 2030. Through this NEP 2020 government is looking forward to making India a “global knowledge superpower” and it will be only done by making education system for schools and colleges more flexible, holistic, and multi-disciplinary which will bring out their unique capabilities.

## Major Reform in National Education Policy

### नई शिक्षा नीति 2020 कब से लागू होगी

- Students now take a school examination which was conducted by the appropriate authority in grades 3, 5, and 8.
- Board examination for 10<sup>th</sup> and 12 will be continued but will be redesigned with the aim of holistic development.
- PARAKH (Performance assessment, review, and analysis of knowledge for holistic development) a new national assessment platform will be set up.
- Mathematical thinking and scientific temper coding will start from class 6.
- Vocational education will start in school from 6<sup>th</sup> grade which also includes internships.
- The 10+2 structure will be replaced by 5+3+3+4...
- The new system will have 12 year of schooling and 3 years of pre-school/ Anganwadi.
- Till grade 5th this policy will emphasize local language/regional language/ mother-tongue as the medium of instruction.
- At school and higher education, Sanskrit will also be included at all levels as an option for students which includes three language formulas.
- As an option, literature of India and other classical languages will also be available.
- No student would be forced for any Language.
- Higher education will receive flexibility in subjects.
- There will be multiple entries and exit points with appropriate certification for higher education.
- UG programmes can be of 3 or 4 years with multiple exit options with appropriate certification in this period like certificate will be awarded after 1 year, advanced diploma after 2 years, degree after 3 years, and bachelor with research after 4 years.
- Academic Bank of Credit (ABC) will be created in which digitally academic

credit earned by students will be stored through different HEIs and it will be transferred and counted for final degree.

- The curriculum in all subjects has been reduced to its core essentials.
- Through this, they focus on critical thinking, discovery, inquiry, discussion, and teaching based on analysis and holistic learning methods for education.
- Regulator for higher education will be light but tight.
- Focus on E-learning so that they can reduce the dependency on textbook.
- Under the new policy education will get **6% of GDP** earlier it was **1.7%** which will definitely boost the education system.
- By the end of 2040, they aimed that all HEIs will become multidisciplinary institutions and each of them will have 3000 or more students.
- In next 15 years, college affiliation will be phased out.
- At least one large multidisciplinary HEI should be built-in or near every district by 2030.
- Aim to achieve 100% youth and adult literacy.
- NTA will offer a common entrance exam for admission in HEIs
- **#NEP2020 Fact:** Do you know this was the 3<sup>rd</sup> NEP policy first policy came in 1968 and the 2<sup>nd</sup> one came in 1986 but it was amended in 1992.

### **What is the vision of New National Education Policy?**

“The NEP 2020 envisions an India Centred education system that directly contributes to the evolution of our nation enduring into an equitable and vibrant knowledge society by giving them a top-class quality of education.”

Through this NEP, our country’s education system and research facility will become more robust and with the help of this, students who spent thousands of dollars on education in foreign countries will get global standards in line in India.

## NEP 2020

### ECCE (Early childhood care and education) Foundation of learning:

Through this policy, the children who are in the age group of 3 to 6 year has access to free, safe, high quality, developmentally appropriate care, and education by 2025. Because right now there is a severe learning crisis in India because children are enrolled for pre-primary but they fail to attain basic skills.



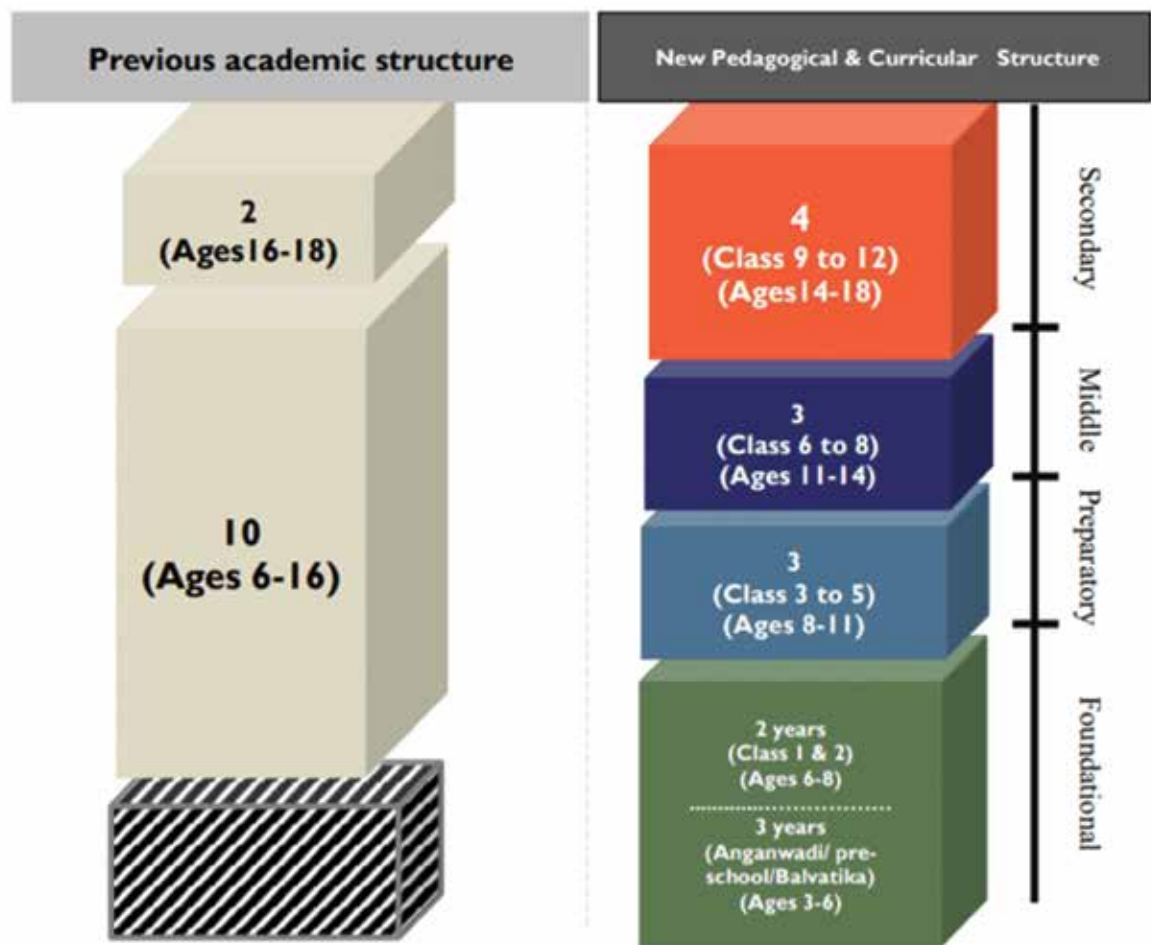
MHRD | Government of India  
Ministry of Human Resource Development

### Ensuring Universal Access to Education at all levels



### New Curriculum Structure

- Restructuring of school curriculum and pedagogy to new 5=3+3+4 pattern
- The new curricular structure was designed in the interest of learners at different stages of their development such as 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14, and 14 to 18 years.
- Foundation stage will be of 5 years: 3 years of pre-primary and grades 1, and 2
- Preparatory stage will be of 3 years: Grades 3, 4, and 5
- Middle or upper primary will be of 3 years: Grades 6, 7, and 8
- High or secondary stage will be of 4 years: Grades 9, 10, 11, and 12
- All stages mentioned above will incorporate Indian and regional traditions, ethical reasoning, socio-emotional learning, quantitative and logical



reasoning, digital literacy, computational thinking, scientific temper, languages, and communication skills properly.

### Education in Mother Tongue/Regional Language

As we know young children grasp new things quickly when we taught in their own language instead of some other language which they are not used to, and this policy also recognizes the same thus they added a point in this new policy that children up to grade 5 will be taught in their mother language but it can also prefer to grade 8 if required.

**For this, textbooks will also be made available in their language but if somehow it was not possible to provide, the language of interaction between teacher and students will be their home language.**



**Narendra Modi** ✓

@narendramodi

Framing of NEP 2020 will be remembered as a shining example of participative governance. I thank all those who have worked hard in the formulation of the NEP 2020.

May education brighten our nation and lead it to prosperity.

7:04 PM · 29 Jul 20 · [Twitter Web App](#)

From grade 1 onwards young children will get exposure to two to three languages which may increase their speaking proficiency, interaction, and ability to recognize the same by grade 3.

### **How teachers will be Recruited under NEP?**

Under the new National Education Policy, if there is a shortage of teacher who speaks given languages, in that case, special efforts will be made and the scheme will be rolled out to recruit teacher including retired teachers who can speak the local language required.

### **Elective Foreign Language**

In secondary school children can opt for the foreign language of their choice which could be French, German, Spanish, Chinese, and Japanese and this will only be an elective and not in place of the three language formula.

## Higher Education Under New National Education Policy

- ❖ Higher education plays an important role in improving human well-being and developing India and through this NEP they aim to increase their **GER from 26.3% to 50% by 2035**, and around 3.5 cr new seats will also be added to higher education institutions.
- ❖ Under this, UG education could be of 3 or 4 years with numbers of entry and exit options.
- ❖ Multidisciplinary education and Research University will be set up of global standards.
- ❖ HECI (Higher education commission of India) will be the only body for entire higher education (except medical and legal education).
- ❖ HECI will have 4 independent verticals such as **NHERC (National higher education regulatory council)** for a directive, GEC (General education council) for standard setting, HEGC (Higher education grants council) for sponsoring, and NAC (National accreditation council) for recognition.
- ❖ Globalization of higher education.
- ❖ An academic bank of credit will be established in which credit earned by the students during their academics from different HEIs could be stored and transferred at the time final degree.
- ❖ National research foundation will act as a peak body that fosters a strong research culture and builds research capacity covering higher education.

## College Affiliation Under NEP 2020

The affiliation of colleges will be phased out in 15 years and a mechanism will be established for granting graded autonomy to colleges. And after some time it is presumed that every college will develop into a self-governing degree provider or an intermediary of a university.

## Focus on Vocational Studies at the School Level

In 12<sup>th</sup> five year plan 2012-2017, it is estimated that not more than 5% of Indians from the age group of 19 to 24 have received formal vocation education which is too low if we compare it to the other countries like USA 52%, Germany 75%, and South Korea 96%. That's why under this policy every child from grades 6 to 8 must learn at least one vocational or more.

- ❖ The importance of basic knowledge of various livelihood and life skills such as gardening, woodwork, pottery, electric work, and others.
- ❖ They aimed that by the end of 2025 they have at least 50% of learners from school and higher education who have to get exposure of vocational education.

### **B.Ed. will be of 4 years**

Under this new and inclusive national curriculum framework for teacher education which will be formulated by NCTE with the help of NCERT, by the end of 2030 the minimum qualification for teachers will be a 4 year B.Ed. degree program. For stand-alone teacher education institutes, inadequate standards strict action will be taken against them.

### **Students Financial Aid**

The national scholarship portal (NSP) will be expanded to support, encourage children and their progress will be tracked so that they can receive scholarships. Private HEIs will be encouraged so that they can offer several studentships and fellowships to their children.

### **No hard separation of streams under NEP 2022**

Every student will get the opportunity to engage in arts and humanities as well as in the study of arts and science and social science because of this no hard separation going to be done between **'curricular' and 'extra-curricular activities' or 'co-curricular activities'**.

Every school subject will be considered as curricular rather than extra or co-curricular which includes yoga, sports, dance, music, sculpting, woodworking, gardening, and electric work.

NCERT will prepare syllabi and textbooks as per the NCF (national curriculum framework) so that these subjects could be incorporated into the curriculum which SCERTs (State Councils of Educational Research Training) in states may edit, rewrite, and supplement as per their needs.

Physical education will be incorporated strongly throughout their curriculum with a consideration that what is interesting and safe at each age.

Also, there is no hard separation between 'vocational' and 'academic' stream because they wanted every student will get an equal opportunity to develop both capabilities.

## **Under whose chairmanship new national education policy was drafted?**

It was done under the chairmanship of former chairman of ISRO and ex-member of parliament K. Kasturirangan.

Term HEIs stand for what?

## **Higher Education Institution**

New national assessment centre has been set up named PARAKH what does it stand for?

PARAKH stands for Performance Assessment, Review, and Analysis of knowledge for Holistic Development.

## **When will the new National Education policy be implemented?**

The implementation program of NEP is under preparation and it will be carried as per the timeline envisaged in NEP.

## **Where one can collect complete details about NEP?**

As we have mentioned everything about NEP in this article but still if you want to know more about it then its complete information is available in the public domain which has been carried out by the Education Ministry of India.



75  
आज़ादी का  
अमृत महोत्सव



श्री शिवराज सिंह चौहान  
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

श्री नरेन्द्र मोदी  
प्रधानमंत्री

# मुख्यमंत्री

# उद्यम क्रांति योजना

मध्यप्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वरोज़गार के लिए बैंको के माध्यम से कोलेटरल फ्री ऋण और ब्याज अनुदान सहायता



## किन परियोजनाओं के लिए

- रुपये 1 लाख से 50 लाख तक मे-युफैवैरिंग युनिट के लिए।
- रुपये 1 लाख से 25 लाख तक सेवा इकाई और खुदरा व्यवसाय के लिए।



## कैसे मिलेगी सहायता

- प्रदेश के 18 से 40 वर्ष तक की उम्र के युवा।
- शैक्षणिक योग्यता - न्यूनतम 12वीं पास।
- परिवार की वार्षिक आय रुपये 12 लाख से अधिक न हो।



## कितनी मिलेगी सहायता

- वितरित किए जाने वाले ऋण पर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरीयम अवधि सहित)।
- ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरीयम अवधि सहित)।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्यप्रदेश



# मध्य प्रदेश ऊर्जा साक्षरता अभियान

ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार द्वारा "ऊर्जा साक्षरता अभियान" प्रारम्भ किया जा रहा है



## अभियान के उद्देश्य

- ✓ प्रदेश के समस्त 7.5 करोड़ नागरिकों को समयबद्ध कार्य योजना अनुसार ऊर्जा साक्षर बनाना।
- ✓ ऊर्जा के व्यय एवं अपव्यय की समझ विकसित करना।
- ✓ ऊर्जा के पारम्परिक एवं वैकल्पिक साधनों की जानकारी, इनका पर्यावरण पर प्रभाव, ऊर्जा संरक्षण एवं प्रबंधन के प्रति जागरूकता पैदा करना।
- ✓ पर्यावरणीय जोखिम एवं जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को कम करना।

## म.प्र. ऊर्जा साक्षरता अभियान से जुड़ने की प्रक्रिया

- ✓ अभियान से जुड़ने के लिए लॉगिन करें [www.usha.mp.gov.in](http://www.usha.mp.gov.in)
- ✓ अभियान से जुड़ना पूर्णतः नि:शुल्क।
- ✓ वेबपोर्टल या मोबाइल ऐप पर (ऐप डाउनलोड कर) "ओटीपी" के माध्यम से पंजीकरण।
- ✓ पंजीकरण उपरांत अपनी स्वेच्छा अनुसार पाठ्यक्रम का चयन कर सकेंगे।
- ✓ पाठ्यक्रम के चयन पर प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम (Module) डाउनलोड करने की सुविधा।



विश्व में इस अनूठे अभियान के माध्यम से विद्यार्थियों एवं जन साधारण को ऊर्जा, सौर ऊर्जा और ऊर्जा की बचत के विषय में जानकारी दी जायेगी।



जनसाधारण तक ऊर्जा के उपयोग के लाभ की जानकारी पहुँचाने एवं अपनाने का कार्य एक मिशन के रूप में क्रियान्वित किया जायेगा।



अभियान में श्रेणीगत प्रशिक्षण सर्टिफिकेशन का प्रावधान किया गया है।



प्रतिभागी अपनी सुविधा अनुसार, ऑनलाईन पद्धति से बहु विकल्पिय प्रश्नों के रूप में एक श्रेणीगत प्रशिक्षण (Graded Learning) अनुसार परीक्षा में भाग ले सकेगा।



प्रश्न कम्प्यूटर द्वारा रेण्डम आधार पर प्रस्तुत होंगे। प्रतिभागियों के उत्तरों के आधार पर ऑनलाईन ऊर्जा साक्षरता प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा जो कि "ओटीपी" वेरीफिकेशन से डाउनलोड किया जा सकेगा।